DISINTEGRATION OF THE SOCIALIST BLOC – A CRITICAL STUDY OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA'S RESPONSE AND INTERPRETATION

Dissertation submitted to Jawaharlal Nehru University in partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of

MASTER OF PHILOSOPHY

NAVEEN CHANDER

CENTER FOR EAST ASIAN STUDIES

School of International Studies

Jawaharlal Nehru University

India

2002

CENTRE FOR EAST ASIAN STUDIES
SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI - 110 067 INDIA

Telegram : JAYENU
Phones Off. : 6107676, 6167557 Extn. 2346

Fax: 91-11-616 5886
91-11-616 2292

Date 29th July 2002

CERTIFICATE

This dissertation entitled "DISINTEGRATION OF THE SOCIALIST BLOC – A CRITICAL STUDY OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA'S RESPONSE AND INTERPRETATION" is submitted by NAVEEN CHANDER in partial fulfillment of six credits for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY of this University. This dissertation is his original work according to the best of our knowledge and has not been submitted for any other degree of this University or any other University. We recommend that this dissertation be placed before the examiners for evaluation

Lalima Varma		
Dr. Lalima Verma	**Prof. G.P. Deshpande**	**Dr. Alka Acharya**
(Chairperson)	**(Supervisor)**	**(Co-Supervisor)**

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन i-vi

भूमिका vii-ix

अध्याय - 1: 1-14

समाजवादी ब्लॉक का बिखराव : एक संक्षिप्त रूपरेखा

अध्याय - 2 : 15-35

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में बदलाव व चीन पर उसका प्रभाव

अध्याय - 3 : 36-62

समाजवाद निर्माण के विभिन्न अनुभवों पर
चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के विचार

अध्याय - 4 : 63-88

समाजवादी ब्लॉक का बिखराव व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी
की प्रतिक्रिया

निष्कर्ष : 89-96

संदर्भ-ग्रंथ सूची 97-107

प्राक्कथन

इस अध्ययन की विषय-वस्तु मूलतः प्राथमिक क़िस्म की है तथा साथ ही कई मायनों में सीमित भी है। प्रस्तुत अध्ययन का आधारभूत उद्देश्य मुद्दों व सवालों को रेखांकित करने का है। चूंकि इस विषय पर अध्ययन बहुत सीमित हुआ है ; अतः प्रस्तुत अध्ययन में कोई महत्वपूर्ण व निष्कर्षात्मक टिप्पणी देना न केवल अव्यवहारिक होगा अपितु अध्ययन की सीमितता के चलते अनुचित भी। इस सीमित अध्ययन की कोशिश सोवियत संघ के समाजवादी ब्लाक के रूप में बिखराव से उत्पन्न हुई राजनीतिक परिस्थितियों से उपजे मुद्दों को चीनी संदर्भ में रेखांकित करना भर है ।

समाजवादी ब्लाक के बिखराव व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रियाओं और व्याख्याओं से सम्बंधित यह प्रस्तुत अध्ययन, दरअसल उन सवालों से निकला जो अक्सर 1991 के सोवियत विखंडन के बाद अध्ययन के लगभग हर क्षेत्र से उठने लगे। न सिर्फ़ यह सवाल अकादमिक रूप से उठे बल्कि यह सवाल उन जनआन्दोलनों से भी उठे जो मौजूदा व्यवस्था के विकल्प की बात तो करते हैं, परन्तु समग्र बदलाव के समाजवादी चिंतन व अनुभव को नकार देते हैं, जहाँ एक और उनके चिंतन व बदलाव की भाषा तो उसी विरासत की है जो रूस चीन आदि समाजवादी देशों ने स्थापित की, परन्तु अपने मूल में यह भाषाई अनुकरण ही साबित हो रहा है। मूलतः बदलाव की आकाँक्षा से प्रेरित सोचों में नई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की बात तो है ; परन्तु उस इतिहास से एक ख़ास क़िस्म का अलगाव है, जिस इतिहास को, बदलाव की आकांक्षा रखने वाले आंदोलनों व आम लोगों ने स्थापित किया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि समग्र बदलाव का एकमात्र इतिहास सिर्फ़ 1917, 1949 या पूर्वी यूरोप ही रहा है। न ही यहाँ यह तात्पर्य है कि 19 वीं सदी में पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में जिन विभिन्न व्यवस्थाओं की समाजवाद के रूप में स्थापना की गई, उस आधार पर आन्दोलन या उस वैचारिक दिशा का अनुकरण नहीं रहा ।

दरअसल यह दोनों धाराएं एक साथ मौजूद हैं, परन्तु दोनों तरह की वैचारिक सोच और बदलाव की आकाँक्षा से प्रेरित आन्दोलन एक महत्वपूर्ण रूप से पिछली सदी में मार्क्सवादी विचार-धारा व समाजवादी व्यवस्था के अुनभवों व प्रयोगों से जुड़े हैं और प्रभावित भी हैं। और यही वह बिन्दु हैं जहाँ से फ़िलहाल संक्षिप्त, पर अध्ययन के स्तर पर एक व्यापक सवाल खड़ा होता है। जहाँ तक ग़ैर-मार्क्सवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के बदलाव का इतिहास है, वह, ऐतिहासिक रूप से कहें तो, अन्ततः कोई वैकल्पिक व्यवस्था की (और वैकल्पिक भी अधिकांश हाशिए पर पड़े लोगों के संदर्भ में) स्थापना नहीं कर पाया, मूल रूप से व्यवस्था 'रूप' के स्तर पर बदलाव के बाद भी आन्तरिक रूप से पूंजीवादी या बुर्जुआ ही बनी रही और यह सवाल या कहें गैर-मार्क्सवादी और समाजवादी व्यवस्थओं की अपूर्णता समसामयिक परिदृश्य पर भी स्पष्ट है, कहने का मूल तात्पर्य यह है कि बदलाव प्रेरित ग़ैर-मार्क्सवादी विचारधाराएं या आन्दोलन कोई वैकल्पिक (पूंजीवाद के संदर्भ में) व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाए, और यह स्थिति आज भी भारत सहित दुनिया भर के अनेक जन-आन्दोलनों के बारे में कही जा सकती है।

दूसरा, बदलाव से प्रेरित वह आन्दोलन जो मार्क्सवादी विचारधारा व समाजवाद के इतिहास से स्वयं को जोड़ते हैं , उन आन्दोलनों को विचारधारा के साथ-साथ अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष करना पड़ रहा है, वह चाहे संसदीय लोकतंत्र के जरिए बदलाव चाहने वाली कम्युनिस्ट पार्टियाँ हो या वर्ग संघर्ष के हथियारबंद संघर्ष के ज़रिए क्रांति की सोच वाले साम्यवादी आन्दोलन हों। संक्षेप में कहें तो, समाजवादी देशों के अन्दर विभिन्न क़िस्म के प्रतिरोधों के चलते 1989 से 1991 तक जो समाजवादी ब्लॉक का बिखराव हुआ ; उसने न केवल विचारधारा की प्रासंगिकता के सवाल को मार्क्सवाद के संदर्भ में उठाया बल्कि विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की वैधता व स्वीकार्यता पर भी सवाल उठने लगे और उसी के एक प्रभाव के रूप में मौजूदा "मार्क्सवादी" आन्दोलन राजनीतिक सैद्धान्तिक रूप से कमजोर हुए हैं। और जो समाजवादी देश चाहे वह किसी भी रूप में हो बचे रहे

वह हर तरह से आर्थिक, राजनैतिक बदलाव के बतौर ही बचे रह पाए हैं। चाहे वह चीन हो, क्यूबा या अन्य कोई।

कुल मिलाकर एक और महत्तवपूर्ण बिन्दु यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समाजवाद का दुनिया भर में क्षरण हुआ, दूसरी तरफ बदलाव को मुखातिब आन्दोलनों के मौजूद होते हुए भी यह आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी विचारों के नेतृत्व में नहीं है। इसी में महत्वपूर्ण यह भी है कि न तो कोई वैकल्पिक विचारधारा जो मौजूदा व्यवस्था के ख़िलाफ़ हो अस्तित्व में आती दिखती है और न ही गुणात्मक स्तर पर सामाजिक बदलाव होते दिख रहे हैं । वैश्विक पूंजीवाद के ख़िलाफ़ जन-आन्दोलन महज विरोध की सीमा तक है, वही पितृसत्ता व पूंजीवाद के विरूद्ध महिला आन्दोलन मूलतः स्वतन्त्र क़िस्म में दिशामान है । मूलतः अलग-अलग क़िस्म के विरोध स्वतंत्र रूप से स्वयं को प्रदर्शित तो करते रहे हैं, पर समग्र बदलाव की कोई विचारधारा व दिशा नही दिखती।

इस नयी परिघटना जो कि अपने मूल में पूंजीवाद विरोधी है पर इस विरोध में विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद से अलगाव दरअसल पिछली सदी की समाजवादी व्यवस्थाओं की कमजोरियों व नाकामियों की भी उपज है । समाजवादी निर्माण के काल में रूस और चीन से लेकर पूर्वी यूरोप अफ्रीका, लैटिन अमेरीका तक समाजवाद पर ग़ैर-जनतांन्त्रिक होने के आरोप लगते रहे और इस विमर्श में कुछ हद तक तथ्य भी है । इसी के एक प्रभाव के चलते आधुनिकता की समाजवादी व्याख्या, व प्रयोगों पर सवाल उठे। इस के चलते दुनिया के तमाम ऐसे मुक्ति संघर्ष जो आम-आदमी से जुड़े हैं, मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होते हुए भी अलगाव की स्थिति में हैं ।

यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, जिन सवालों के एक संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण दायरे में यह अध्ययन भी आता है, वह सवाल हैं, यदि मार्क्सवाद समतामूलक समाज को स्थापित करने की विचारधारा है, यदि समाजवाद अधिकांश आम लोगों के विकास का दावा करता हे तो २० वीं

सदी में 1917 की रूसी क्रान्ति व पूंजीवाद के मरणासन्न की घोषणा करने वाला रूस व तमाम पूर्वी यूरोप क्यों समाप्त हो गया ? समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन को लाखों लोगों ने नकार कर सदी के समाप्त होते-होते स्वयं निर्मित व्यवस्थाओं को क्यों उखाड़ फेंका ? समाजवादी प्रयोगों निर्माण की क्या पेचीदगियाँ थीं जिनके चलते वह अपने वर्ग-रहित-राज्य-विहीन साम्यवादी समाजों के निर्माण से पहले ही ध्वस्त हो गई ? जो देश इस दौर में बचे रहे वह किन अर्थों में मार्क्सवादी होते हुए भी अस्तित्व में हैं और इस तरह के कई सवाल, जो अन्ततः समाजवाद के प्रयोगों के विस्तृत पड़ताल की माँग करता है, अलग-अलग रूपों में उठते हैं । यहां सवालों का यह प्रस्तुत अध्ययन जो परिघटना के स्तर पर इन सवालों से जुड़ा है; सीमित अर्थों में कुछ सवालों को रेखांकित करने की कोशिश है । दरअसल इन व्यापक सवालों के रूप में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दौर में समाजवादी देशों का एक व्यवस्था के रूप में पतन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियों की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगे, साथ ही विचारधारा के सन्दर्भ में मार्क्सवाद की अप्रासंगिकता के मुद्दे उठे, उस दौर में जो देश इससे बचे रह पाए उसकी क्या वजहें थीं जिन की सीमित अर्थों में वह समाजवादी है या तब थे, इन तमाम दौर में स्वयं को कैसे विकसित कर पाए । यहाँ यह बात मूलतः फिलहाल चीन के ही संदर्भ में कही जा रही हैं। इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा तत्कालीन कम्युनिस्ट देशों की पतन के इस दौर पर प्रतिक्रिया व विश्लेषण से भी जुड़ता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समाजवाद के पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ से समाप्त होने पर क्या विश्लेषण रहा और स्वयं के लिए उन्होंने क्या सबक निकाले ? इससे एक ओर यह जानने की कोशिश है कि इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों की समाजवाद को लेकर क्या समझ थी साथ ही, तत्कालीन समय में कम्युनिस्ट पार्टियों पर बिखराव के प्रभाव को भी रेखांकित किया जा सकेगा । चीन के संदर्भ में इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह जानना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी सिद्धान्त व व्यवहार की समझ में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों के संदर्भ क्या हैं ?

प्रथम अध्याय मूलतः उन व्यापक घटनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा है जो 1989 से 1991 तक पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ के विघटन के रूप में घटी। एक तरह से यह अध्याय नहीं बल्कि इस दौर में समाजवादी देशों के विघटन की प्रक्रिया का सिलसिलेवार ब्यौरा है। इस संक्षिप्त घटनाक्रम के ब्यौरे का महत्व इस बात में है कि यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रियाओं व विश्लेषण को वह संदर्भ प्रदान करता है जिससे वह प्रभावित हो रही थी। एक तरह से यह अध्याय अन्य तमाम अध्यायों की पष्ठभूमि का काम करता है ।

दूसरे अध्याय में मूलतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत विखण्डन के बाद उत्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में समय व उसकी विदेश नीति पर आने वाले बदलावों को रेखांकित करने की कोशिश करता है। पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन बतौर एक समाजवादी देश कैसे व्यवहार करता है। मूलतः यह अध्याय सोवियत विघटन के बाद की परिस्थितियों में जहाँ एक और विश्व-व्यवस्था के चीनी आँकलन की समझ को रेखांकित करता है वही अमेरिका व दुनिया के अन्य देशों के सम्बधों में आने वाले बदलावों को समाजवादी ब्लाक के संदर्भ के रूप में देखने की कोशिश करता है ।

तीसरा अध्याय महत्वपूर्ण रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी व सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवाद निर्माण की सैद्धांतिक समझदारियों की चर्चा करता है। दोनों देशों के समाजवाद, व मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर जो समझ विकसित हुई । वह एक ओर सोवियत-विखंडन पूर्व की राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को रेखांकित करता है ; वहीं दूसरी ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया व विश्लेषण को उसकी सैद्धान्तिक समझदारी से भी जोड़ता है । मूलतः यह अध्याय सिद्धान्त और व्यवहार की उन समझदारी की चर्चा करता है जिसके आधार पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवादी संकट पर प्रतिक्रियाओं का विकास होता है ।

अन्तिम अध्याय जो कि समूचे अध्ययन का महत्वपूर्ण अध्याय है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवाद के बिखराव पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं को रेखांकित करता है । सन 1989 से 1991 तक समाजवादी ब्लाक के रूप में सोवियत संघ में हो रहे घटनाक्रमों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बदलती प्रतिक्रियाएं और विश्लेषण इस ऐतिहासिक दौर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समाजवादी संकट के आंकलन व पार्टी पर प्रभाव को स्पष्ट करता है। यह अध्याय महत्वपूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्थाओं के संकट के दौर में (जिसका हिस्सा स्वयं चीन भी था) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बतौर समूचे समाजवादी ब्लॉक में आ रहे बदलावों के विघटन व प्रतिक्रिया के रूप में रेखांकित करने की कोशिश करता है ।

समाजवादी ब्लॉक के बिखराव के रूप में सोवियत संघ को केन्द्र में रखने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, प्रथम चूंकि पूर्वी यूरोप व अन्य देशों पर प्रतिक्रियाओं को समाजवादी अध्ययन में रेखांकित करना मुश्किल भी है तथा अव्यवहारिक भी । सब कुछ समेटने के चलते कुछ भी महत्वपूर्ण न कह पाने की स्थिति होनी की सम्भावना थी । दूसरे समाजवादी आधुनिकता की जिस सोच के आधार पर समाजवादी व्यवस्थाओं का निर्माण 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद हुआ सोवियत संघ उसका प्रेणेता होने के साथ-साथ ही एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करता रहा था । पूर्वी यूरोप व अन्य समाजवादी देशों की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं में सोवियत संघ प्रेरित समाजवादी मॉडल को आसानी से रेखांकित किया जा सकता है । अतः सोवियत संघ को समाजवादी ब्लॉक के केन्द्र के रूप में अध्ययन करना महत्वपूर्ण होगा ।

अंत में शोध की भाषा हिन्दी होने के साथ-साथ, कई जगह अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया गया है । इसकी मूल वजह दरअसल अनुवाद की सीमितता । चूंकि अधिकतर संदर्भ चीनी भाषा से अंग्रेज़ी में अनुवाद वाले हैं, ऐसे में अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करने से संदर्भ का सही अर्थ संप्रेषित न हो पाने की संभावना रहती है । अतः संदर्भ व सूचिकाओं को अंग्रेज़ी में दिया गया है।

भूमिका

मैं अपने पर्यवेक्षक प्रो0 गोविन्द पुरुषोत्तम देशपाण्डे व सह–पर्यवेक्षक डा0 अलका आचार्य के प्रति अति कृतज्ञ हूँ, जिनके अथाह परिश्रम, बौद्धिक क्षमताओं व सटीक मार्गदर्शन के चलते यह अध्ययन सम्पन्न हो पाया। प्रो0 देशपाण्डे के साथ लम्बे बौद्धिक विमर्शों ने अक्सर अध्ययन की दिशा को सही दिशा की ओर एकाग्र किया। उनके सानिध्य में रहकर न सिर्फ अध्ययन की तार्किक गहराइयों व पेचीदगियों को समझने में सहायता मिली, अपितु अध्ययन के सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भों के महत्त्व को भी नए सिरे से समझ पाया। प्रो0 देशपाण्डे के एक "बौद्धिक योद्धा" होने के साथ–साथ उनके भीतर रचनात्मक सृजनात्मक नाटककार के रूप में कार्यकर्त्ता ने मुझे हमेशा अध्ययन की सीमा के बाहर कुछ करने की प्रेरणा दी है।

डॉ0 अलका आचार्या के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। यह कहना कम–अज–कम मेरे लिए नाकाफी है कि मेरी सह–पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने मेरी तमाम अराजकताओं को सहते हुए विषय–वस्तु से लेकर प्रूफ रीडिंग तक हर वह कार्य किया, जो मुझे करना चाहिए था। उनके अपार स्नेह के चलते मुझे हमेशा यह महसूस हुआ कि छात्र और अध्यापक के बीच इतना सहज सम्बन्ध किसी और के साथ सम्भव नहीं हो पाता। भाषा के रूप में हिन्दी के मेरे चुनाव को प्रो0 देशपाण्डे और अलका मैडम ने हमेशा प्रोत्साहित किया। चूँकि इस स्वतंत्रता के बगैर यह अध्ययन संभव नहीं था।

प्रो0 मनोरंजन मोहंती के समय–समय पर सहयोग से इस अध्ययन की विषय–वस्तु को स्पष्ट करने में काफी मदद मिली, छात्र जीवन की शुरुआत से एम0ए0 की कक्षाओं तक, तथा आई0सी0एस0, डी0सी0आर0सी0 में अक्सर उनके वक्तव्यों ने चीन के अध्ययन में मेरी रुचि को जागृत किया।

रवि सिन्हा, सुभाष गताड़े, डा0 संजय कुमार के साथ बौद्धिक व राजनीतिक विमर्शों ने मुझे इस अध्ययन के लिए प्रेरित किया। सुभाष गताड़े द्वारा समय–समय पर महत्त्वपूर्ण विषयों पर सामग्री ने काम में काफी मदद पहुँचाई।

डॉ0 आदित्य निगम के सहयोग व सुझावों ने अन्त तक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

PSU, PYS और स्त्री अधिकार संगठन के साथियों ने अध्ययन जारी रखने हेतु हर तरह की सहायता पहुँचाई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष व कर्मचारियों के हमेशा सहयोग के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।

Chinese Studies, CSDS का मै विशेष रूप से आभारी हूँ जहाँ से अक्सर महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई।

सराय के तमाम दोस्तों का सहयोग अन्त के दिन तक मिलता रहा, विशेषतः रविकान्त के सहयोग के चलते अन्तिम दिन मैं अपना कार्य पूरा कर पाया, अन्यथा यह अध्ययन पूरा करना मुश्किल था। सोहन की कई रातों की मेहनत से यह टाईप हो पाया और प्रशान्त के परिश्रम के प्रूफ रीडिंग हुआ, अन्त में अविनाश न होते तो यह अध्ययन अपने वर्तमान रूप में न आ पाता।

योगेन्द्र और ऋतु और उनके सहयोग और उनके घर गुजारी अनगिनत रातों में लम्बी बातचीत का किस रूप में शुक्रिया अदा किया जाय, पता नहीं?

भगवती, नरेश, सुरेश, वीरेन्द्र और तमाम दोस्तों ने किसी न किसी रूप में समय–समय पर मदद की। मेरे सभी क्लासमेट जबिन, अरविन्द, परिमल, विदिशा, शैलेन के साथ बहस मुबाहिसे ने जे0एन0यू0 में जीवन का बहुत आसान बनाया।

अनूप और रोस्मिन ने हर ऐन वक्त पर आर्थिक से लेकर मानसिक स्तर पर सहयोग दिया।

अपने माता–पिता, बूबू, राजू, जीवन, भाभी सभी लोगों के अपार उत्साह ने मुश्किल समय में भी मुझे पढ़ते रहने का हौसला दिया। हालाँकि यह और बात है कि उनकी चाह मुझे आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बनाने की रही, जिससे मैं अब तक नफरत करता हूँ, और शायद करता रहूँ।

लोकेश के लिए मैं क्या कहूँ– क्या लिखूँ यह सोचते हुए अजीब किस्म की अनुभूति होती है और आभास होता है कि क्या उसके परिश्रम, लगन और प्रेम के बिना यह शोध पूरा हो पाता?

नवीन चन्द्र

अध्याय - 1

समाजवादी ब्लॉक का बिखराव - एक संक्षिप्त रूपरेखा

पिछली सदी संभवतः विश्व इतिहास की उन महत्वपूर्ण सदियों में गिनी जाती रहेगी; जहाँ समाज के ग़रीब और शोषित वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए न सिर्फ़ संघर्ष किया, अपितु ऐसी व्यवस्थाओं के निमार्ण का प्रयास भी किया जो तुलनात्मक रूप से उसके मुक्ति संघर्षों की उच्चतम परिणति भी थी । पिछली सदी आधुनिकता के उस महाआख़्यान की भी सदी रही ; जहाँ पूंजीवादी आधुनिकता के बरक्स समाजवादी आधुनिकता के मूल्य स्थापित किए गए । आधुनिकता के इन मूल्यों का विकास मार्क्सवादी विचारधारा ने संभव बनाया और रूसी क्रान्ति, चीनी क्रान्ति सहित पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने इन्हें अमली जामा भी पहनाया ।

लेकिन पिछली सदी इसी संदर्भ में इसके पतन की भी गवाह बनी। इतिहास के जिस दौर में यह परिवर्तन संभव हुए वह दौर सदी के एक दशक में चरमरा कर ध्वस्त भी हो गया। मुक्ति संघर्षों के उच्च आदर्श, समाजवादी व्यवस्थाएं विशाल सोवियत संघ अपने आदर्श समाज व लक्ष्यों से बहुत पहले ही समाप्त हो गया ।जिन उच्च समाज व्यवस्थाओं को जन समूहों ने अपने रक्त से निर्मित किया, उन्हीं जन समूहों ने उसकी समाप्ति भी की । आधुनिकता के जिन नए मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया गया उन पर भी सवाल उठाए गए चाहे वह, समाजवादी जनतंत्रा की बात हो अथवा पितश्सत्ताा की समाप्ति तथा स्त्री-पुरूष समानता का मसला हो, निसन्देह, मार्क्सवादी विचारधारा के ज़मीनी प्रयोगों में स्थापित व्यवस्थाओं के भीतर से ये सवाल गंभीर रूप से उठाए गए और इसी के चलते विचारधारा और सिद्धान्त के क्षेत्र पर स्वयं आधुनिकता पर ही सवाल उठने लगे हैं । फिर चाहे वह समाजवाद की आधुनिकता ही क्यों न हो ? इसके प्रति उत्तर में दर्शन के रूप में उत्तर-आधुनिकता का विमर्श, आज मार्क्सवाद के लिए चुनौती भी पेश कर रहे हैं। जन संघर्षों द्वारा निर्मित समाजवादी व्यवस्थाओं की उपलब्धियाँ अपार संभावनाओं के साथ ही भयंकर सीमाएं और समस्याएं

भी सामने आयीं । सोवियत संघ में मूलतः जोसफ स्यलिन के काल में शुरू हुई यह सीमाएं और समस्याएं चीन, पूर्वी यूरोप व अन्य समाजवादी देशों में सामने आती रहीं ।

समाजवादी व्यवस्थाएं इन सीमाओं, समस्याओं के चलते दुनिया के अधिकतर देशों में अपने मुकाम तक पहुंचने में असफल रहीं । क्लासकीय रूप में आज समाजवाद का पतन हो चुका है । पोलेंड और हंगरी से शुरू हुआ यह पतन, पूर्वी यूरोप के तमाम समाजवादी देशों को ध्वस्त करता हुआ 1991 में सोवियत संघ तक पहुंचा और अक्टूबर क्रान्ति की इस जन्मस्थली में समाजवाद सोवियत विखंडन के साथ दिसम्बर 1991 में समाप्त हो गया ।

अपवाद के रूप से परिवर्तन के उस दौर में कुछ एक देशों के साथ चीन एक ऐसा देश रहा है जिसके समाजवादी होने या न होने के बारे में अब भी बहस है या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि, क्रान्ति के इतिहास की उपज के रूप में चीन अब भी उस तरह समाप्त नहीं हुआ जिस तरीके से पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ का समाजवादी ढांचा व कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गए । हालांकि चीन में पूंजीवाद के लक्षण आसानी से इंगित किए जा सकते हैं फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, राज्य का नियोजन में गहरा हस्तक्षेप व सामाजिक सुरक्षा जैसे कई मसलों पर समाजवादी व्यवस्था के लक्षण रूप आज भी मौजूद हैं । अतः विषय के रूप में चीन के समूचे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व अध्ययन महत्वपूर्ण है, जिसमें यह समझने की कोशिश की जा सकती है कि पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ के पतन की ऐसी पेचीदगियां रहीं जिससे चीनी कम्युनिस्ट शासन बच पाया, साथ ही राजनीतिक रूप से समूचे घटनाक्रम के प्रभाव को चीन सहित, समसामयिक मार्क्सयवादी विचारधारा के संकट को समझाया जा सके । हालांकि यह अध्ययन बहुत सीमित अर्थो में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर ही केन्द्रित है, और संदर्भ की प्रतिक्रिया के रूप में सोवियत संघ की घटनाएं व बदलाव ही अधिक केन्द्र में रखने की कोशिश की गई है ।

ग़ौरतलब है कि 1989 से 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक की प्रक्रिया काफ़ी लम्बी रही है और इस दौर में चीन पर इसका प्रभाव तदनुसार प्रतिक्रियाएं की बदलती संदर्भ के हिसाब से रही है। यह प्रतिक्रियाएं, जहां एक ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की उस दौर में विकसित होती है समझदारी पर रोशनी डालती है, वही यह उस दौर में हो रहे बदलावों का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की समझदारी पर असर को भी रेखांकित करती है । स्वाभाविक रूप से 1989 से शुरू हुए इन बदलावों का चीन के राजनैतिक नीव पर पड़ा साथ ही दुनिया भर के समाजवाद का संकट, एक अर्थ में चीन का संकट भी था क्योंकि चीन भी उसी अतीत की विरासत था और ऐसा नहीं था कि यह घटनाएं सिर्फ पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ में ही हो रही थीं दरअसल इनके प्रभाव क्षेत्र में चीन भी था । 1989 का आंदोलन जिसने समूचे चीनी राष्ट्र को झकझोरा, इसी समाजवादी संकट का हिस्सा था । अतः चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक था । चीन कम्युनिस्ट पार्टी के समूचे दौर के आंकलन व प्रतिक्रिया से पहले ज़रूरी है कि घटनाक्रम के विकास का अध्ययन किया जाए ।

पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति [1]

1989 के उत्तारार्ध में पूर्वी यूरोप की उथल-पुथल ने यूरोप को एक बार फिर महत्वपूर्ण कगार पर ला खड़ा किया था । कम्युनिस्ट शासन के विरोध में जन-समूहों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ । इस ऐतिहासिक बदलाव की चपेट में "पिपुल्स डेमौक्रेसी" का दावा करने वाली कम्युनिस्ट सरकारें एक के बाद एक धराशायी होती गयीं । हालैंड और हंगरी से शुरू होकर गहरे राजनीतिक बदलाव का यह सिलसिला क्रमशः पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पूर्वी बर्लिन, लिपजिंग, सोफिया और प्राग को अपने आगोश में ले लिया । लाखों की संख्या में उमड़े जन समूहों ने इन देशों की "पिपुल्स डेमौक्रेटिक" राज्य सत्ताा को समाप्त कर दिया । "राजनीतिक आर्थिक सुधारों" की अंधाधुंध घोषणाओं के बावजूद एक के बाद एक सरकारें गिरती

प्रस्तुत अध्याय मूलतः घटनाओं का ब्यौरा है अतः संदर्भ के लिए कुछ पुस्तकों व पत्रिकाओं की सहायता ली गई है। पूरे अध्याय में सभी संदर्भों का स्रोत यही पुस्तकें और पत्रिकायें हैं।

१. हरपाल बराड़ - सोवियत संघ का पतन, संशोधनवादी नीतियों की अनिवार्य परिणति, अनु०-टी. डी. वैरिया, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, २०००, लोकदस्ता पत्रिका-मेन स्ट्रीम, ई.पी.डब्ल्यू, फ्रंट लाइन, कम्युनिस्ट।

गयीं और शासक पार्टियों का पुराना नेतत्व धाराशायी हो गया। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों विशेषकर 1985 के गौर्बाचेव कालीन सोवियत संघ में हो रहे व्यापक बदलाव आर्थिक राजनीतिक सुधारों के इन देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।

विघटन की इस व्यापक प्रक्रिया की शुरूआत पोलैंड और हंगरी की घटनाओं से हुई थी। 24 अगस्त 1989 को पोलैंड में एक नई सरकार ने सत्ता संभाली "सॉलिडेरिटी" आन्दोलन के प्रमुख नेता तादोज मात्सोवियेच्की इस नई सरकार के प्रधानमंत्री बने थे । सत्ता की मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी 'पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी (पी.यू.डब्ल्यू.पी.) के हाथों से शासन, "सॉलिडेरिटी" आन्दोलन के हाथों में आ गया, जो पश्चिमी ढंग की पूंजीवादी प्रणाली का हिमायती था नयी सरकार के बनते ही सॉलिडेरिटी के सर्व प्रमुख नेता 'वालेसा' की उदघोषणा की "पहले किसी ने की समाजवाद से शुरू करके पूंजीवाद की ओर जाने वाली राह नहीं पकड़ी है । हम ठीक यही करने जा रहे हैं ।"

जनरल जारू जेल्सकी के नेतश्त्व वाली पी.यू.डब्ल्यू.पी की कम्यूनिस्ट सरकार अत्यधिक अलोकप्रिय हो चुकी थी, विकल्प के रूप में सॉलिडेरिटी आन्दोलन को व्यापक जन समर्थन मिला । ग़ौरतलब है कि सरकार बनाने से केवल चार महीने पहले तक सालिडारिटी एक ग़ैर-कानूनी संस्था थी । जन-आंदोलन के दबाव में 5 अप्रैल 1989 को इसे कानूनी मान्यता दी गई थी। ४ जून को हुए राष्ट्रीय आम चुनावों में इसे भाग लेने की अनुमति मिली जिसमें इसने पी.यू.डब्ल्यू.पी को करारी शिक़स्त दी और अगस्त में इसने अपनी ग़ैर-कम्युनिस्ट सरकार बनाई और उसमें पी.यू.डब्ल्यू.पी ने भी भागीदारी की ।

पश्चिमी देशों और मीडिया में पोलैण्ड की बहु-दलीय जनतंत्रा की स्थापना का व्यापक स्वागत हुआ । पश्चिमी जर्मनी के चांसलर कोल ने पोलैण्ड की यात्रा की और 2.4 अरब डाल के कर्ज और सहायता की घोषणा की । अमेरीका ने 85.7 करोड़ डालर की सहायता देना स्वीकार किया, हालांकि अगस्त से पहले बुश सरकार ने केवल 23.8 करोड़ का वादा किया था । हंगरी में घटनाएं और भी

नाटकीय रूप से सामने आने आयीं। अक्टूबर 1989 की 14 वीं कांग्रेस में हंगरी की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो हगंरियन सोशलिस्ट वर्कस पार्टी के नाम से जानी जाती थी औपचारिक तौर पर अपना विसर्जन कर दिया । इसकी जगह हंगेरियन सोशिस्टि पार्टी का गठन हुआ, जिसने साम्यवादी विचारधारा के मूलभूत उसूलों को घोषित रूप से त्याग दिया इन नयी पार्टी ने बहु-पार्टी व्यवस्था, संसदीय जनतन्त्रा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुले बाज़ार की नीतियां को स्वीकारने की घोषणा की ।

हंगरी में इन परिवर्तनों का पश्चिमी देशों के मीडिया में व्यापक स्वागत हुआ। हंगरी को "पश्चिमी ढंग की आज़ादी वाला पूर्वी खेमे का देश" घोषित किया गया। दूसरी तरफ हंगरी की सरकार ने "यूरोपीय समुदाय" में शामिल होने की अपील की हंगरी में एक एक्सन्चेंज खोला, निजी उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कानून बनाए, हंगरी की नई सरकार ने विदेशी कम्पनियों को पूंजीनिवेश के लिए नए सिरे से और नई सुविधाओं के साथ आमंत्रित किया । इसके साथ ही हंगरी के नए शासकों ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसने पूर्वी यूरोप में कम्युन्स्टि विरोधी ताक़तों को और मज़बूत बनने में सहायता पहुँचाई । हंगरी ने आस्ट्रीया के साथ अपनी सीमा को खोल दिया । पश्चिमी जर्मनी जाने वाले हज़ारों पूर्वी जर्मनी नागरिक चेकोस्लावाकिया होकर हंगरी पहुचने लगे और वहाँ से आस्ट्रिया होते हुए पश्चिम जाने लगे। इससे जहाँ एक ओर पूवी जर्मनी की सरकार पर दबाव बढ़ा, वहीं दूसरी और इन घटनाओं के प्रवाह में पूर्वी जर्मनी के शहरों में सरकार, विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए । हंगरी के नए शासकों के इस कदम तथा चेकोस्लावाकिया के सहयोग के चलते पूर्वी जर्मनी की शासनरत पार्टी और सरकार का संकट फूट पड़ा । पूर्वी बर्लिन, पिजिंग तथा अन्य नगरों में विशाल विरोध प्रदर्शन होने लगे, जन-सैलाब के इस दबाव के चलते पूर्वी जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टी एस.ई.डी. को स्वयं को बचाने तथा सरकार बचाए रखने के महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़े । 8 नवम्बर को पार्टी के नेता एरिक होनेकर ने तथा पार्टी की समूची पोलित ब्यूरो ने इस्तीफा दे दिया । ईगोन क्रेन्ज के नेतत्व में नई पोलित ब्यूरों का गठन हुआ, क्रेन्ज ने तत्काल, सोवियत संघ के गोर्बाचेवी सुधारों की तर्ज़ पर

अपने यहां भी सुधारों की घोषणाएं की । इसके साथ ही पुरानी सरकार ने इस्तीफा दे दिया । नयी सरकार का गठन हुआ "सुधारवादी" नेता हान्स मोड्रो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और एस. ई.डी. की नयी पोलित ब्यूरो में उन्हें भी स्थान दिया गया।

सबसे महत्वपूर्ण घटना 9 नवम्बर 1989 को घटित हुई । पूर्वी जर्मन सरकार ने पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ अपनी सीमाएं खोल दीं, और ऐतिहासिक "बर्लिन की दीवार" ढहा दी गयी । लाखों की तादाद में पूर्वी जर्मन नागरिकों ने पश्चिम बर्लिन की सैर की, प्रति-आगुंतुक 100 मार्क की दर से प. जर्मनी में लोगों ने सैर की तथा पश्चिमी दुनिया तथा पूंजीवादी बाज़ार का आनन्द लेकर वापस लौटे । दुनिया भर में "बर्लिन की दीवार के बारे में प्रचलित "मिथक"[2] का नए सिरे से प्रचार किया गया कि यह दीवार साम्यवाद का घणास्पद प्रतीक है, और इसके ढहने के साथ ही साम्यवाद का ख़ात्मा हो रहा है ।परन्तु यह सारे आर्थिक, राजनीतिक सुधार भी क्रेन्ज के नेतत्व को बचाने के लिए कम साबित हुऐ । लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के दबाव, और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने की शर्मनाक स्थिति में क्रेन्ज को दिसम्बर 1989 के पहले हफ़्ते में नेतत्व को इस्तीफा देना पड़ा । विपक्षी ग्रुप "न्यू फोरम" के वकील के रूप में काम कर चुके "सुधार समर्थक" नेता "ग्रेगोर गाइसी " को 8 दिसम्बर को नया नेता चुन लिया गया। केन्द्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरों का विसर्जन कर दिया गया और इसकी जगह 100 सदस्यी कार्यकारिणी चुनी गई । पार्टी ने पूर्वी जर्मनी की जनता से माफ़ी मांगते हुए पूर्ववर्ती नेतत्व को "देश को एक ऐसे सफ़र में डालने" का ज़िम्मेदार ठहराया जिसके चलते "उसका आस्तित्व ख़तरे में पड़ गया है ।" पूर्व कम्युनिस्ट नेता ऐरिक होनेकर समेत कई शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकद्दमे शुरू किए गए । "गैर कम्युनिस्ट" लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मान्फ्रेड गरलाख नए राज्याध्यक्ष चुने गए ।

परन्तु इतने सबके बाद भी सरकार और पार्टी विरोधी आन्दोलन थमा नहीं आन्दोलन के नेतत्वकारी लोग संविधान में दर्ज "कम्युनिस्ट पार्टी" की नेतश्त्वकारी भूमिका" को निरस्त करने की

मांग कर रहा था । अन्ततः प्रधानमंत्री मोड्रो ने इसकी कुछ ही दिन में घोषणा कर दी और कम्युनिस्ट शासन का औपचारिक अन्त हो गया । परिवर्तन के इस तूफान में बुल्गारियाँ के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर दिया । 35 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झिवकोव को नेतत्व से और राज्याध्यक्ष के पद से 16 नवम्बर 1989 को इस्तीफा देना पड़ा । पोलित ब्यूरों के कई अन्य सदस्यों को भी हटा दिया गया। सुधारवादी नेता पीटर ग्लादेनोव नए नेता और राज्याध्यक्ष चुने गए जिन्होंने नियुक्ति के तत्काल बाद "सुधारों" की घोषाणाएं कीं । परन्तु राजधानी सोफ़िया की सड़कों पर जन-प्रदर्शन फिर भी जारी रहे। झिवकोव पर मुकदमा चलाने की माँगें उठती रहीं। जन-आन्दोलन के दबाव में महीने भर के अन्दर ही पार्टी की पोलित ब्यूरो में दुबारा "छटनी" करनी पड़ी और दिसम्बर के पहले सप्ताह में फिर कई वरिष्ठ नेताओं को हटाया गया । जन-आंदोलनों के लगातार दबाव के चलते, पार्टी का टिकना मुश्किल हो गया । 10 दिसम्बर 1989 को सेन्ट्रल सोफिया में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया । लोगों ने बड़े जोर से पुराने संविधान को निरस्त कर नये संविधान के निर्माण और झिवकोव पर मुकदमे को चलाने की मांगें भी कीं ।

इस सब के मद्देनजर पार्टी को सत्ता की कमान, विपक्ष को सौंपनी पड़ी "लोकतांत्रिक ताक़तों का संघ" नाम से विपक्ष ने कम्युनिस्ट पार्टी की कीमत पर अपने को मजबूत बनाया तथा पारिस्थितियों को सुधारने के लिए सोवियत संघ की तर्ज़ पर सुधार शुरू किए । अंततः लोकतांत्रिक ताक़तों के संघ ने मुक्त बाज़ार को मंजूरी देकर, कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का एकाधिकार समाप्त कर दिया ।

बुल्गारिया के पश्चात अगला प्रहार चेक गणराज्य पर हुआ । कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने अन्य देशों में हो रहे जन-आन्दोलनों के चलते, अपने बचाव हेतु कई सुधारों की घोषणाएं कीं । पार्टी के नेता मिलोस डेक्स की सरकार ने सुलगते जन-आन्दोलन के दबाव में पश्चिम की यात्रा की छूटें दी थीं । लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार व लोकतन्त्र की बहाली के नाम पर आन्दोलन प्रचंड हो

चला ! नवम्बर के तीसरे सप्ताह के दौरान "प्राग" में हज़ारों छात्रों ने विशाल प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन को चेक पुलिस ने दबा दिया और छात्रों की बुरी तरह पिटाई की गई । इस घटना के पश्चात आन्दोलन में व्यापक रूप धारण कर लिया, आन्दोलन पूरे देश में फैल गया । रोज लाखों लोगों के प्रदर्शन होने लगे । 24 नवम्बर 1989 को लाखों लोग (लगभग 5 लाख) प्राग की सड़कों पर उतर आए । उसी दिन प्रदर्शन के दबाव में मिलोस जेक्स को तथा पार्टी नेतत्व के बड़े हिस्से को इस्तीफा देना पड़ा । इस्तीफे के बाद ख़ुशी मनाने हेतु विशाल रैलियाँ हुईं । 24 नवम्बर 1989 की रैली को अलेक्सान्द्र दुब्चेक ने भी सम्बोधित किया । ग़ौरतलब है कि इन्ही दुब्चेक के नेतत्व में चेक गणराज्य में दो दशक पहले ही गोर्बाचेव-मार्का "सुधारों को लागू करने की कोशिश की गई थी । परन्तु तब सोवियत संघ में गोर्बाचोव का उदय नहीं हुआ था। उस समय के सोवियत नेतत्व ने इस "प्राग वसन्त" को सोवियत टैंकों के बल पर दबा दिया था, दुब्चेव की सरकार को बर्ख़ास्त करके उसकी जगह गुस्ताव हुसाक की सरकार को नेतत्व दिया गया और दुब्चेक को अज्ञातवास में भेज दिया था ।

परिवर्तन की चपेट में आए अन्य देशों की ही तरह यहाँ की "कम्युनिस्ट पार्टी" के नए नेता कारेल अरबानेक ने तत्काल सुधारों की घोषणाएं कीं । "सुधारवादी" प्रधानमंत्री लाडिस्लाव अडामेक ने तो यहां तक कहा कि संविधान में "कम्युनिस्ट पार्टी की नेतत्वकारी भूमिका" से सम्बंधित प्रावधान में फेर-बदल किया जा सकता है । इस सबके बावजूद आन्दोलन का दबाव कम नही हुआ अन्ततः सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्षी दल "नागरिक मंच" के नेतत्व में 10 दिसम्बर को नयी सरकार ने शपथ ग्रहण की । शपथ ग्रहण करते ही नागरिक मंच ने अपना विश्वास ज़ाहिर करते हुए कहा, "नियोजित अर्थव्यवस्था सुधार्य हैं ।" और एक विकसित बाज़ार और वास्तविक प्रतिस्पर्धा का निर्माण, काम की हसरत "साथ ही यह भी जोड़ा कि हम यह "मैडम थैचर" की जरूरत है ।"

पूर्वी यूरोप को हिलाकर रख देने वाले इन ऐतिहासिक जन-आन्दोलनों का उग्रत्तम रूप

रोमानिया में दिखा, रोमानिया में उग्रतम रूप अख्तियार करने के साथ ही आन्दोलन अचानक ढंग से घटित हुआ । दिसम्बर के अन्तिम दिनों में 1989 में 24 साल से चला आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त कर दिया गया । कम्युनिस्ट पार्टी के नेता निकोलाई चोसेस्कू का शासन सशस्त्र विद्रोह के द्वारा समाप्त कर दिया गया । इस विद्रोह को रोमानिया की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था । विद्रोह के दौरान, सेना और पार्टी में विभाजन हो गया, परन्तु इस विभाजन में बड़ा हिस्सा विद्रोह के समार्थन में गया । चोसेस्कू समर्थक ताक़तों ने सत्ता वापस लेने की कोशिश में सशस्त्र संघर्ष छेड़ा था परन्तु उनकी हार हो गई । चोसेस्कू और उनकी पत्नी को गिरफ़्तार करने के बाद उन पर गुप्त मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदण्ड दे दिया गया । चोसेस्कू शासन के ख़ात्मे के बाद सत्ता में आए राष्ट्रीय मोर्चे की अंतरिम सरकार के जरिए अपनी स्थति सुदृढ़ बनाई । विद्रोह को सोवियत संघ और बारसा सन्धि के न्य देशों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। गृहयुद्ध के दौरान जब चोसेस्कू समर्थक शाक्तियाँ सशस्त्र संघर्ष में व्यस्त थी तब इस बात की संभावना भी बनी थी कि सोवियत संघ विद्रोह के समर्थन में सेना भेजे । दरअसल विद्रोह की शुरूआत तिमिसुआरा नामक शहर में हुए विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुई । चोसेस्कू की सुरक्षा सेनाओं ने इन प्रदर्शन का हिंसात्मक दमन किया, जिसके फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन पूरे रोमानिया में फैल गए और जल्द ही उन्होंने सशस्त्र विद्राह का रूप ग्रहण कर लिया सेना में विभान के साथ ही ग्रह युद्ध ने रोमानियों के मुख्य शहरों को चपेट में ले लिया हज़ारों की तादाद में लोग गृह-युद्ध की भेंट चढ़े - एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5,00,000 लोग मारे गऐ थे ।

ब्रिटेन के फाईनेंशल टाईम्स ने अपने सम्पादकी "डिकेड आफ डैमोक्रेसी में वर्ष 1989 को ए ट्रू मिरेविलिस" यानि अजूबों का वर्ष बताते हुए लिखा, "चाउशेस्कू के ख़िलाफ़ हिंसक विद्रोह के साथ लेनिन, द्वारा 1917 में शुरू किए गए यूरोपीय इतिहास के निरंकुश काल का अंत हो गया । एक मात्रा अलबानिया ही अविचलित उत्तराधिकारी बचा हैं, इसके अलावा यह लेनिन का उत्तराधिकारी मिख़ाईन गोर्वाचौव है जिसने स्वाधीनता के इस पुनर्जन्म में दाई का काम किया है ।"

ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धान्तिक पत्रिका मार्क्सिज़्म टूडे के संपादक मार्टिन जैकेस ने सम्पादकीय टिप्पणी में कहा, "स्तालिनवादी व्यवस्था ढह गई है, यह अपने विनाश के चरम बिन्दु पर जा पहुंची थी किन्तु यह साधारणतया स्टालिनवाद का ही अंत नहीं है एक महत्वपूर्ण अर्थ में यह लेनिनवाद का अंत है ।"

पश्चिमी मीडिया द्वारा पूर्वी यूरोप की इन घटनाओं पर इस तरह की प्रतिक्रिया अस्वाभाविक नहीं थी, चूंकि पश्चिमी पूंजीवादी देश एक अरसे से बुर्जुआ जनतंत्र, खुले बाज़ार, बहुदलीय व्यवस्था के समर्थक रहे हैं ।

पूर्वी यूरोप के जन-उभार में पश्चिमी देशों का समर्थन इसी के अनुरूप ही था । वही पूर्वी यूरोप की जिन कम्युनिस्ट देशों की सत्ता ग़ैर-कम्युनिस्ट नेतृत्व में गई उन्होंने तुरंत आर्थिक, राजनीतिक सुधारों की घोषणाएं भी कीं । पोलैण्ड में लेख वालेसा ने अमेरीका के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा, "हमें पोलैंड की ८० प्रतिशत अर्थव्यवस्था के लिए ख़रीददार चाहिए - पूर्वी यूरोप में आप इस सदी के व्यवसायिक सौदे कर सकते हैं ।" चेकोस्लावाकिया में नागरिक मंच ने विकसित बाज़ार व्यवस्था और वास्तविक प्रतिस्पर्धा के निर्माण की बातें कहीं । दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया पूंजीवादी जनतांत्रिक व्यवस्था की सभावनाओं को व्यक्त करते हुए 2 जनवरी 1990 को फाइनेंसिल टाईम्स में लिखता है ।

"1980 के दशक की सारी सफ़लताओं के बावजूद 1990 के दशक में काफ़ी कुछ करना बाकी है । पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ में अब सक्रिय बाजार अर्थव्यवस्थाएं स्थापित करनी पड़ेंगी, ताकि उनके नए लोकतंत्र की स्थिरता को मज़बूती प्रदान की जा सके । रूमानिया में चाउशेस्कू के ख़िलाफ़ विद्रोह की सफलता पर 26 दिसम्बर 1989 के ईडिपेडेंट ने संभावना व्यक्त करते हुए लिखा, "रूमानिया और सोवियत संघ के बीच सामान्य सीमा लम्बाई के हिसाब से पोलैण्ड की सीमा के दूसरे

नंबर पर है । उन पड़ोसी देशों में लोकतान्त्रिक सुधारों के वक्त पूरा होने से गोर्बाचौव पर उन बन्धनों को ढीला करने के लिए अवश्य ही दबाव बढ़ेगा जो समाजवादी गणतन्त्रों के संघ के घटक गणतन्त्रों को मास्को के साथ जोड़े है । यह बात तय है कि पूर्वी यूरोप में इसी साल (1990) में होने वाले चुनावों की श्रंखला सोवियत संघ में इसी प्रकार के अधिकारों की माँगों को प्रोत्साहित करेगी । लिथुआनिया की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मूल सोवियत पार्टी से स्वतंन्त्रता की घोषणा के प्रति गौर्बाचोव की सावधानीपूर्ण किन्तु आक्रमण प्रतिक्रियाएं संकेत देती हैं कि आर्थिक सुधारों की ही तरह, वह ऐसे साहसिक प्रयासों के लिए अभी तैयार नहीं हैं, जो सुधारवादी मांगों को पहले ही अधिकतर कर सकते हैं ।

"केवल कड़े कदमों द्वारा ही, जैसे कि सम्पत्ति के अधिकार को फिर से लागू करने तथा गणतन्त्रों के एक ढीले परिसंघ के निर्माण के द्वारा, गोर्बाचोव इस कठिन कार्य को अंजाम देने की आशा कर सकते हैं, जिसे ग्लास्तनोस्त और पेरेस्त्रोइका ने शुरू किया हैं, तरूण रूमानिया इस के साहस ने दिखा दिया है कि अत्यधिक बेरहम दमन और अत्यधिक दिल दहला देने वाला नरसंहार भी विचारों की ताक़त और मुक्ति की कामना को दबा नहीं सकता ।"

और अंत में बचा था स्वतंत्र कम्युनिस्ट देश यूगोस्लाविया, आधा बल्कन व आधा सैन्ट्रल यूरोप में। यूगोस्लावाकिया द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात से ही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे । शीत युद्ध के कम्युनिस्ट विरोधी होने के चलते काफी तहत मिली थी । साथ ही यूगोस्लाविया ने मार्शल टीटो की लीगेशी के चलते शीतयुद्ध में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की शुरूआत की तथा युद्ध विरोधी मुहिम में गुट-निरपेक्ष देशों में काफी लोकप्रियता भी पायी । परन्तु अन्य समाजवादी देशो की ही तरह लोकतान्त्रिक संस्थाओं का अभाव तथा दूसरा सर्ब लोगों में व्यापक सर्बिया की आकाँक्षा का उत्पन्न होना, इस सम्बन्ध में यूगोस्लवाकिया व चेकोस्लावाकिया की समस्या काफ़ी कुछ एक जैसी थीं ।

टीटो के समय काल से कम्युनिस्ट ताक़तों के सामने सर्व जनता की अकांक्षाओं पर रोक लगाने की समस्या थी । टीटो की मत्यु के पश्चात मई 1988 में मिलोसेविच (Slobodan Milosevic) ने कम्युनिस्ट पार्टी का नेतश्त्व संभाला ।मिलेसंविच 42 प्रतिशत सर्ब जनसंख्या के प्रतिनिधि थे जो कि यूगोस्लाविया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता थी ।

राष्ट्रीयताओं के दमन के सवाल पर यूगोस्लाविया में संकट शुरू हुआ। यूगोस्लाविया संघ का बिखराव 1991 में शुरू हुआ जब इसके एक संविधानिक संघ सोलाविनिया (Solvcnia) ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषण कर दी । इसके साथ ही क्रोशिया (Crotia) तथा बोस्निया, हर्जेगाविनिया ने भी स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । सर्बिया जो कि यूगोस्लाविया गणतन्त्र का सबसे बड़ा हिस्सा था ने स्वयं को सर्बिया-मोटीगरो (Serbia-Montecnegro) गणतन्त्र के रूप में बनाए रखा । हिंसात्मक संघर्षों के दौरान, यूगोस्लाविया बिखराव शुरू हुआ तथा यह कई अलग स्वतंत्र गणतन्त्रों में विभक्त हो गया । सर्बिया जो कि तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था, ने बोस्निया के बड़े भूभाग को कब्ज़ा लिया क्योंकि यहाँ मूलतः सर्व आबादी की बहुतायत थी ।

समाजवादी ब्लॉक का यह महत्वपूर्ण संघ, अन्तिम दिनों में नणातीय हिंसाओं के भयंकर दौर से गुज़रकर विखंडित हुआ जिसमें, सर्व, मुस्लिम, क्रोशियाई, लोग बड़ी संख्यामें हताहत हुए । अंततः टीटो के दौर का समाजवादी संघ, जिसमें हर समुदाय के लोग कम्युनिस्ट शासन के अन्तर्गत थे , विभिन्न राष्ट्रों में बंट गया ।

दरअसल यूगास्लाविया के विघटन तक (1989-91) पूर्वी यूरोप के शुरू हुए जब उभारों की प्रकृति में काफ़ी बदलाव आ चुका था । हालांकि यह बदलाव विभिन्न देशों की आंतरिक समस्याओं के सदंर्भ में ही था, फिर भी यूगोस्लाविया और रोमानिया के जन-उभारों की प्रकृति में हिंसा व राष्ट्रीयताओं के सवालों का उभरना, कई महत्वपूर्ण बदलावों व मुद्दों की और संकेत करता है, मसलन जनतन्त्र की मांग से शुरू होकर हिंसात्मक प्रवृत्ति का रोमानियाई संस्करण तथा राष्ट्रीयताओं के संघर्ष

का यूगोस्लावियाई प्रकरण तथा इसके पश्चाल, सोवियत संघ के राष्ट्रीयताओं के आन्दोलन ने इस दौर में न सिर्फ़ समाजवाद में जनतन्त्रा का बेहतर आर्थिक जीवन के सवालों को उठाया अपितु समूचे समाजवाद के निर्माणकाल में आधुनिकता की समझ पर भी सवाल खड़ा किया ।

बरहाल यूगोस्लाविया के विघटन के साथ-साथ सोवियत संघ भी अपने अन्तिम दौर में पहुंच चुका था । सोवियत संघ का बिखराव समाजवाद के तावूत में आखरी कील साबित हुई। सोवियत संघ में घटनाएं बहुत आश्चर्यजनक व तेजी से घटीं। २८वी कांग्रेस के पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को समाप्त करने के बाद से तथा राष्ट्रपति के रूप में बोरिस येल्सिन के चुने जाने ने सोवियत विघटन में तेजी ला दी ।

गोर्बाचौव के सुधारों के चलते सी.पी.पी.एस.यू. में रेडिकल, माड्रेट्रस तथा कंजरवेटीव (Radical, Moderate) and (Conservative) के बीच संघर्ष शुरू हुआ।

सोवियत संघ के गोर्वाचौव के सुधार विरोधी ग्रुप ने गोर्वाचोव को कम्युनिस्ट पार्टी से हटाकर सत्ता पर क़ब्जा कर लिया १६ अगस्त १६६१ को पोलोजेकोव तथा उसके समर्थकों ने तख़्ता पलट पर एक "आपातकालीन राज्य कमेटी का निर्माण किया" तथा सेना, KGB के सदस्यों सहित आठ लोगों की इस कमेटी ने राज्य सत्ता पर कब्जा कर लिया । यह तख़्ता पलट दरअसल यूरोप से भिन्न था । जहां यूरोप में जन-उभारों का मकसद कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति करना था, सोवियत संघ में तख्ता पलट का उद्देश्य कम्युनिस्ट शासन को किसी तरह बनाए रखने को लेकर हुआ । हालांकि यह मूलतः गोर्बाचौव के विरूद्ध राजनीतिक तख्ता पलट था न कि जन-उभार । परन्तु तीन दिन पश्चात आश्चर्य जनक रूप से ये असफल हो गया तथा येल्तिसिन व उनके सहयोगियों ने एक विशाल जन-समूह को सम्बोधित करते हुए इस असफलता की घोषणा कर, जनतन्त्र बहाली का वादा किया ।

कुछ दिनों पश्चात गोर्बाचौव की वापसी हुई इस बीच लिथुआनिया , एस्टोनिया, पहले ही अपनी स्वतंन्त्रता की घोषण कर चुके थे, दिसम्बर 1991 क्रिसमस के दिन गोर्बाचौव ने संघ के विसर्जन व राष्ट्रीयताओं की स्वतन्त्रता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर, स्वयं का त्यागपत्र भी दे दिया । इसके साथ ही सोवियत संघ के विखंडन की औपचारिकता भी समाप्त हो गई, और सोवियत संघ अब संघ न रहकर रूस रह गया ।

संक्षेप में पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ के विघटन की यह प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से घटित हुई, मानो सब पूर्व योजना के तहत हुआ हो । पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ तक मूलतः सभी देशों में मूल मुद्दे एक-समान थे जनतान्त्रिकरण की माँग, जीवन स्तर में सुधार की माँग । शान्तिपूर्ण पर उग्र आन्दोलनों के आगे कम्युनिस्ट शासनों का एक झटके में बिखर जाना दरअसल इस बात को स्पष्ट करता है कि यह कोई स्वतःस्फूर्त तत्कालिक कारणों से उपजी घटनाएं नहीं थीं, अपितु यह साफ़ तौर पर यह रेखांकित होता है, कि दरअसल इसकी भूमिका एक लम्बे समय से बन रही थी । और जहाँ इन आन्दोलनों का दमन करने की कोशिश की गई यह और व्यापक रूप में भड़क उठे, रूमानिया इसका प्रबल उदाहरण है । संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि यह तमाम घटनाएं कुछ महीनों या सालों के प्रभाव में न होकर उस दौर से जुड़ी हुई थी जिस दौर में समाजवाद का निर्माण हुआ , उसी निर्माण दौर की पेचीदगियों व समस्याओं ने एक समय के पश्चात उग्र रूप में इन व्यवस्थाओं का अन्त कर दिया, तथा विश्व भर में समाजवाद के अप्रसांगिक होने की बहसों को भी बल दिया ।

अध्याय-२

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव व चीन पर उसका प्रभाव

आने वाले तीन-चार साल हमारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वक्तव्य तंग सियाओ पिंग ने सन् १९८९ में पेईचिंग में हुए "प्रतिक्रांतिकारी" उभार के दमन पर दिया था। इस वक्तव्य के दौरान तंग सियाओ पिंग ने शुरूआत में ही कहा "जल्दी या देरी से इस तूफान को आना ही था।" कुछ दिनों पश्चात इसका विश्लेषण उन्होंने कुछ इस तरह किया "यह दरअसल पश्चिम के शान्तिपूर्ण विकास और हमारे चार Cardinal Principal के बीच का टकराव है।" "बुर्जुआ उदारीकरण" के विरूद्ध इन वक्तव्यों के दौरान विश्लेषण में जो बात प्रमुखता से उभर कर सामने आई, वह तमाम समस्या की जड़ को "बाहरी" रूप में परिभाषित करता रहा। हालांकि १९८९ से १९९१ तक पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति से सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति और बिखराव तक कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न मंचों पर यह एक बहस का मुद्दा रहा कि इस "प्रतिक्रान्तिकारी" उभार का स्रोत महज "बाहरी" है या इसका कोई "भीतरी" रूप भी है।

बहसों में लगभग इस बात पर पूर्ण सहमति थी कि ४ जून १९८९ की घटना एक प्रतिक्रान्तिकारी उभार था। बहस थी तो उसके स्रोत व कारण पर, जाहिर है कि "भीतरी" स्रोत के रूप में सबसे अधिक सवाल आर्थिक सुधारों की प्रकृति पर हुए। परन्तु अन्ततः पार्टी की सामूहिक समझदारी में स्रोत को बाहरी रूप में परिभाषित किया गया और बुर्जुआ उदारीकरण को एक समस्या के रूप में परिभाषित करते हुए चीन में उसके खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष शुरू हुआ।

इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और प्रक्रिया चल रही थी, पूर्वी यूरोप के देशों में एक के बाद एक कम्युनिस्ट शासनों की समाप्ति, उनके खिलाफ व्यापक "जनआन्दोलन" लोकतन्त्र के मुद्दे पर व्यापक ध्रुवीकरण जिसने लगभग सभी देशों में, कम्युनिस्ट शासनों का अन्त कर दिया। दुनिया भर में कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार व विचारधारा के अन्त की घोषणा के पूंजीवादी के सिद्धान्त व्यापक स्तर पर फैले।

१९८९ के दौरान इन दो व्यापक घटनाओं का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जहाँ एक ओर अन्दरूनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी १९८९ के दमन के पश्चात "स्वीकार्यता/लोकप्रियता" के लिए जूझ रही थी, वहीं इस घटना के पश्चात विश्व स्तर पर "मानवाधिकार के हनन के चलते चीन की व्यापक आलोचना हुयी। अमेरिका, जापान सहित कई देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बावजूद मानवाधिकार पर अपनी समझदारी को जाहिर करने के बाद चीन कूटनितिक स्तर पर विदेशों से अपने सम्बंधों को सही दिशा न दे सका। कुल मिलाकर जो व्यापक परिपेक्ष्य उत्पन्न हुआ उसमें चीन "अन्दरूनी" और "बाहरी" तौर पर स्वीकार्यता के प्रश्न के इर्द-गिर्द जूझता रहा।

सन् १९८९ से १९९१ तक दुनिया के सामरिक, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन में व्यापक बदलाव आया। यह बदलाव मूलतः पूर्वी यूरोप के विघटन से शुरू हुआ और इसकी प्रक्रिया को सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी लोकप्रियता को और बल मिला। अन्ततः १९९१ में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति के तत्पश्चात उसके विखराव ने शीत युद्ध की समाप्ति की और दुनिया का शक्ति सन्तुलन दो ध्रुवीय रूप में समाप्त हो गया, जाहिर तौर पर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके अमेरीका एक मात्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आया।

सोवियत संघ के बिखराव ने सम्भवतः दुनिया के शक्ति सन्तुलन को सबसे अधिक प्रभावित किया, स्वयं विखण्डन के पश्चात रूस और पूर्व समाजवादी राज्य अमेरीका की ओर उन्मुख हुए। चीन पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े चूंकि सोवियत संघ के बाद चीन समाजवादी

देशों में प्रमुख स्थान पर था। चीन १९७० से जिस "strategic triangle" का लाभ ले रहा था वह समाप्त हो गया था।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आशंकित भविष्य के चलते ही सोवियत संघ के बिखराव को रोकने की कोशिश भी की थी। जिस गोर्बाचौव व सोवियत संघ को वह गैर-समाजवादी मानता था उसके बचाव की वजह प्रमुखतः वह वजह रही, जिसे वह "अमेरीकी विश्व व्यवस्था" के विकास के रूप में देखते थे।

बरहाल जो महत्वपूर्ण बात थी वह सोवियत संघ के बिखराव के विश्लेषण के बारे में थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर सोवियत संघ के बिखराव ने नए सिरे से बहस को शुरू किया। बहस का विषय सोवियत संघ में बिखराव के कारण थे, पार्टी में दो तरह की राय थी एक जो १९९१ के बिखराव को बुर्जुआ उदारीकरण व शान्तिपूर्ण विकास मानता था, दूसरा जिसमें स्वयं तंग सियाओ पिंग थे उनका मानना था कि इस पूरे प्रकरण का कारण, सोवियत की बदतर आर्थिक हालत, व गोर्बाचौव के आधे-अधूरे सुधार व कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को नकारना था। कुल मिलाकर पूरे प्रकरण के स्रोत को "अन्दरूनी" रूप में देखा गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वयं चीन में १९८९ के विश्लेषण पर बदलाव करते हुए उसके कारण को चीन की पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सम्बोधित किया गया। जैसा कि पिछले अध्याय में विदित है १९९२ में १४वीं पार्टी कांग्रेस में इस राय व समझदारी को स्वीकृति मिली। इस विश्लेषण के साथ एक और समझदारी आई जिसमें तंग सियाओ पिंग ने कहा "हमें अमेरीका से अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहिए यदि हम लगातार उनसे संघर्ष में उलझे रहेंगे तो यह हमारे आर्थिक सुधारों के लिए समस्या पैदा करेगा और हमें अपने सुधारों को सुचारू रूप से चलाने हेतु अमेरिकी मदद की जरूरत है। कुल मिलाकर १९९२ की १४वीं पार्टी कांग्रेस ने दो चीजें तय कर दी। चूंकि चीन और सोवियत संघ में "समस्या का कारण भीतरी आर्थिक विकास से जुड़ा है अतः आर्थिक सुधार पर जोर दिया जाए।

दूसरा इन सुधारों की प्रक्रिया में अमेरीका की मदद की जरूरत महसूस की गई, अतः उससे सम्बन्धों को सुधारने की बात हुई। पहले वाले प्रस्ताव ने "बुर्जुआ उदारीकरण" को नकार कर समस्या के रूप में दक्षिण-पश्चिमी भटकाव से ज्यादा वामपंथी भटकाव" को खतरा माना गया, इसी के साथ दूसरे निष्कर्ष ने 'इस समझदारी को पुख्ता किया कि चूँकि बुर्जुआ उदारीकरण, व शान्तिपूर्ण विकास एक बड़ी समस्या नहीं है तो अमेरीका पश्चिमी पूंजीवादी प्रदेशों से सम्बन्धों को सुधारा जाए।

१९९२ की कांफ्रेंस में तमाम, वह लोग जो बुर्जुआ उदारीकरण व शन्तिपूर्ण विकास को खतरे के रूप में रेखांकित कर रहे थे, तथा तंग की सुधार नीतियों पर सवाल खड़ा करना चाह रहे थे, वह परिधि पर चले गए।

इस पूरे दौर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के परिप्रेक्ष्य से कुछ बातें सामने आती है, जिससे हम इस दौर में चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक स्थिति के बारे में उहापोह की स्थिति की चर्चा कर सकते हैं।

व्यापक परिपेक्ष्य से देखें तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने १९९१ के पश्चात् जो राय बनायी वह एक तरह से उसी समझदारी का विकास था जिसमें उसने आर्थिक सुधारों को करने व खुले द्वार की नीति की वकालत की थी। हालांकि "आर्थिक सुधार" व "खुले द्वार" की नीति की शुरूआत १९७० के बाद शुरू हुई स्वयं माओ का सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान अमेरीका से सम्बंध सुधारने की पहल करना व चाओ एन लाई द्वारा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना इसके शुरूआती बिन्दु के रूप में ईंगित किए जा सकते हैं। परन्तु विचारधारात्मक स्तर पर १९७८ फिर भी चीन में एक नए दौर की शुरूआत करता है।

परन्तु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा १९८९ के घटना के विश्लेषण में। १९९१ के पश्चात आया बदलाव जिसे बुर्जुआ उदारीकरण को समस्या के रूप में तरजीह नहीं दी तथा १९९१ से पहले सोवियत संघ को एक तरफ बचाने की कोशिश तथा

दूसरी ओर चीन में "शान्तिपूर्ण विकास" तथा बुर्जुआ उदारीकरण के खिलाफ विचारधारात्मक बहसे १९९२ की कांग्रेस के बाद परिधि में चली गई जहाँ १९९१ तक अमेरीका एक खतरे के रूप में दिखाई देता था। जो शान्तिपूर्ण विकास को बढ़ावा देता था, जिसे १९८९ व १९९१ की घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया गया उसके साथ खुले रूप में सहयोग की नीति तथा सुधारों में तेजी को १९९२ की कांग्रेस में स्वीकृति आश्चर्यजनक थी। यही वह बिन्दु है जहाँ यह अध्ययन का विषय बनता है। कुल मिलाकर चीन की राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर आए इस बदलाव की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ का बिखराव पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था की समाप्ति, उसी दौर में क्येन अनमेन की घटना, एक साथ कई स्तर पर चीन को घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर रही थी। अतः यह महत्वपूर्ण है कि चीन की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों की अध्ययन करते हुए १९९१ के पश्चात वैश्विक स्थिति में आए परिवर्तनों से उस पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया जाए।

१९८९ के उत्तरार्द्ध में चीन के मीडिया द्वारा लगातार तंग सियाओ पिंग द्वारा अप्रैल-जून के संकट को "जल्दी या देरी से bound को आना ही था" के रूप में व्याख्यित किया जाता रहा।[1] कारक के रूप में "बाहरी (external) को "घरेलू" से अधिक तरजीह देना विदेशी खतरे को ईंगित कर रहा था, तंग के "वामपंथी" विरोधियों को इसने आर्थिक सुधार व "खुले द्वार की नीति पर हमला करने का मौका दिया। रेनमिन रि पाओ द्वारा माओ कालीन समझदारी को दुहराते हुए आत्मनिर्भरता को स्वस्थ विकास हेतु जरूरी माना"[2] पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के समाचार पत्र Jiefang Jun bao में चीन के इतिहास में घर व असफलता के कारणों को कमजोर हथियार व पर्यवेक्षण में कमजोरी को बताते हुए आगे कहा "एक बार लोग देश के राष्ट्रीय सुरक्षा खो दें तो, विघटन inevitable है। दूसरा लेख कहता है कि "Peaceful evolution is more vicious, wicked and more conducive to infiltration and

---

1 Deng Xiaoping speech of 9 June 1989, *Jiefangjun bao*, 28 June 1989, p. 1. Emphasis added by author.

2 "Only socialism can save China", editorial, *Renmin ribao*, 22 July 1989, p. 1.

deception" than other imperialist strategies aimed at socialist countries."[3] 13, 1989 के संकट में "some reactionary forces in the United States openly intervened" by supporting "illegal organization" at students and workers. एक लेख ने "विचारधारा व सांस्कृतिक, Intiltration - through economic and trade contacts and cultural exchange के खतरे पर जोर दिया।"।[४] Jiefangfjun Pao सिरिज में अन्तिम title था "Beware of Glint and flash of Gold Steel in the halo of peace."[5]

एक साल बाद (१९८९ के) व अप्रैल में तंग ने साम्यवाद के विघटन व गोर्बाचौव के "betrayal" के बाद कहा "under the present situation all enemy attention will be concentrated on China. They will use every pretext to cause trouble, to create difficulties and pressare for us. The next three to five years will be extremely difficult for our party and our country."[६]

३ मई १९९० में Jiang Zemin ने Patriotism and the Mission of the Chinese Intellectual" पर भाषण देते हुए कहा "hostile forces at home and abroad to subvert the socialist system in China through peaceful evolution to turn China into a vassal state dependent on the western superpowers"[7] आगे उन्होंने जोड़ा we need to learn and assimilate the excellence of every

---

3 Qu Quanshen, "Beware of the 'peaceful evolution' scheme by hostile international forces," *Jiefangjun bao*, 7 November 1989, p. 3.

4 Bai Keming, "Questions and answers on studying Jiang Zemin's Natinoal Day speech," *Jiefangjun bao*, 9 November 1989, p. 2.

5 Wan Yaoting and Ma Guangwu, "Beware the glint and flash of cold steel in the 'halo of peace", *Jiefangjun bao*, 1 December 1989.

6 "Deng Xiaoping sees the future for the CCP", *Zhengming*, Hong Kong, No. 151 (1 May 1990) as cited by Michael Yahuda, "Deng Xiaoping : the statesman," *The China Quarterly*, No. 135 (September 1993), p. 564.

7 *FBIS - CHI*, 4 May 1990, pp. 8-13.

country in the world, including those who live under the capitalist system".[8]

एक महीने बाद Chinese people's political consultative conference (CPPCS) ३ जून १९४०, अफीम युद्ध का वह पहला दिन जिसमें नशीले पदार्थों को जलाया गया था" के मौके पर रेनमिन रिपाओ "peaceful evolution" की पार्टी लाइन को दुहराया।[9] पर साथ ही Jiang's Zemin ने खुले द्वार की नीति के बारे में कहा "While we must hold high the banner of patriotism we should not indiscriminately reject anything foreign and close our door to outside wolrd" yet while we must open to the outside world we should not yield to any pressure and advocate total westernization."[9]

फिर भी विदेशी खतरा बराबर एजेंडे पर रहा "The United States mustered forces almost simultaneously from three sides - Korea, Taiwan and Indo-China to strangle Independent China in its infancy." ४ जून की घटना पर पिछले साल कुछ अमेरीका नेतृत्व विदेशी ताकतों ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए और हमारे अन्दरूनी मामलातों में दखल दिया, Jiefangjun में आगे लिखा गया "Since Western capitalism has never stopped its aggression against China and its plunderity China." Now peaceful evolution is infact a kind of spiritual opium more misleading and deceptive than opium. We must not relax our vigilance against the imperialist led aggression and peaceful evolution conspiracy at any time."[10]

खाड़ी युद्ध ने नए सिरे से चीन पर इसके प्रभाव पर बहस को शुरू किया। He Xin द्वारा अमेरीका-विरोधी एक दस्तावेज लिखा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में वितरित किया गया।

DISS
324.251
C3611 Di
TH10419

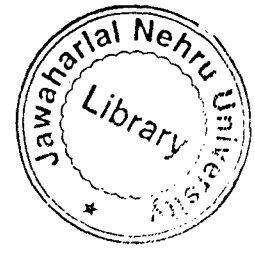

8 *FBIS-CHI*, 4 June 1990, p. 44.
9 *FBIS-CHI*, 4 June 1990, p. 13.
10 *FBIS-CHI*, 11 October 1990, p. 4-6.

इस दस्तावेज में साफ तौर पर यह ईंगित किया गया कि "अमेरिका अपने नेतृत्व में विश्व एकीकरण का प्रयास कर रहा है साथ ही यह चेतावनी देते हुए कहा कि "united states undoubtedly devate all its energy to turning China into Chaos and subjugating and dissecting China. अमेरीकी राष्ट्रपति बुश से तिब्बत के दलाईलामा से white house में मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को बर्बाद करना चाहता है।" उप-विदेश मंत्री Liu Huaqin ने चीन में अमेरीकी राजदूत जेम्स लिली से सख्त विरोध दर्ज करते हुए कहा कि अमेरिका तिब्बत में उन नेताओं का समर्थन कर रहा है जो चीन को बाँटना चाहते हैं।"

पूर्वी यूरोप से इस दौर में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति व सोवियत संघ से कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की समाप्ति पर तंग ने २४ character prescriptoin जारी किए। परन्तु मीडिया ने लगातार अमेरीका प्रयोगिप्त शान्तिपूर्ण विकास" व बुर्जुआ उदारीकरण का विरोध प्रमुख रूप से किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धान्तिक पत्रिका Qiushi ने तंग के कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए लिखा "After China opened her doors and carried out a policy of opening to the outside world, the capitalist-corrupted ideas and ways of life kept pouring in through various channels. in large quantity. The question of "which will win out,' socialism or capitalism is still not really solved. Therefore we must-build a strong wall ideologically, effectively resist and overcome capitalist ideas."[१२]

जुलाई के मध्य में ताईवान के पत्रकारों से बात करते हुए जेम्स लिली चीन की राष्ट्रीय अस्मिता पर चुटकी लेते हुए कहा। "China today is a declining empire with twentieth century nuclear teeth and a nineteenth century view of sovereign right."[13] प्रमुखतः डेंग सियाओ पिंग के one country two system के ताईवान संदर्भित

---

11 *FBIS-CHI*, 18 April 1991, p. 12-13.

12 *FBIS-CHI*, 15 August 1991, p. 20-21.

13 *FBIS-CHI*, 15 August 1991, p. 1-2.

एकता के सुझाव को उन्होंने "असहनीय तथा "सम्प्रभुता का दृष्टिकोण" के रूप में सम्बोधित किया, साथ ही यह भी कहा कि - China's notion of sovereignty has had trouble over the issue of Xingjiang, Tibet and Hong Kong[14] दो दिनों पश्चात् ताईवान में अमेरीकी संस्था के चेयरमैन Natale Beldochi ने अमेरीकी अकादिमियों को बताया कि "The people of Taiwan are developing a unique and separate Taiwan identity."[15]

चीन की तरफ इस वक्तव्यों को देर से पर कड़ा जवाब दिया गया। ६ अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति Yang Shangkun ने एक बड़ी रैली को सम्बोधित करते हुए कहा "some foreign forces are instigating the Taiwan independence movement to split the motherland, साथ ही चेतावनी देते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा we will absolutely not permit any foreign forces to interfere. We will never sit by and watch any act of separating Taiwan from China - Whoever plays with fire will perish by fire."[16]

१६ अगस्त को गोर्बाचौव के खिलाफ सोवियत संघ में तख्ता पलटा तथा बाद में सोवियत संघ की समाप्ति ने चीन में वामपंथी गुट ने खुले द्वार की नीति के विरूद्ध पार्टी स्तर पर बहस शुरू की।

रेनमिन रिपाओ ने चेतावनी दी "under these circumstances China may have to bear greater pressure than before"[17] अमेरीका को निशाना बनाते हुए कहा "Western hostile forces achieved success in some countries therefore now they are glaring like a tiger covetling its prey and are trying by all means to

---

14 *Renmin ribao*, overseas edition, 10 August 1991, p. 2. in *FBIS-CHI*, 14 August 1991, pp. 3-4.

15 Ibid.

16 *Renmin ribao*, 10 October 1991, pp. 1, 3 in *FBIS-CHI*, 15 October 1991, pp. 31-34. The rally was in the Beijing Olympic Centre.

17 *FBIS-CHI*, 29 August 1991, p. 22. The article originally appeared in *Zhonggong dangshi yanjiu.*

subvert and in infiltrate China, putting their hopes of peaceful evolution on the younger generation."[18]

२४ सितम्बर को Jiang Zemin ने Lu Xun's के जन्मदिन की ११०वीं वर्षगांठ पर अमेरीका के खतरे व सोवियत संघ के बाद की स्थिति के मद्देनजर कहा - "International hostile forces will never stop using peaceful evolution against us for a single day. Bourgegis liberalisation is an internal matching force which they use to carry out peaceful evolution. Those kind of hostile activities constitute a real threat to China's independence, sovereignty, development and reform. In other words peaceful evolution and bourgeois liberalization are aimed not only at overthrowing our socialist system but, fundamentally, at depriving us of our national independence and state sovereignty."[19]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के आठवें प्लेनरी सेशन से पहले जियांग जैमिन इन सब मुद्दों पर गंभीर संघर्ष की बात कर रहे थे।[20] इससे कुछ ही पहले, अमेरीका के राज्य सचिव जेम्स बेकर का पेईचिंग दौरा होने वाला था, अमेरिका के उच्च पदासीन अधिकारी की तियेनआनमेन के बाद पेईचिंग आने की यह महत्वपूर्ण घटना थी।

सितम्बर के मध्य तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की कांग्रेस से पहले तंग व उसके शक्तिशाली विरोधी Chen yun के बीच विदेश नीति को लेकर समझौता हुआ परन्तु सुधार व खुलेपन की नीति पर मतभेद बने रहे। उन्होंने यह समझ विकसित की कि अमेरिका ने मास्को की परिस्थिति में "added fuel to the flames" का काम किया तथा चीन को मानव अधिकार तथा, MFN के जरिए कमजोर बनाने की कोशिश की। महत्वपूर्ण रूप से इसी समय तंग सियाओ पिंग ने अमेरीका से सम्बन्धों को लेकर नयी समझ बनाई। तंग ने

---

18 *FBIS-CHI*, 3 September 1991, p. 26-27.
19 *FBIS-CHI*, 6 November 1991, pp. 28-30.
20 *FBIS-CHI*, 9 October 1991, p. 19.

तत्कालीन घटनाओं से निपटने हेतु निर्देश देते हुए कहा - "The city is under siege; the enemy is more powerful than we; regard defence as the main strategy".[21] यह वक्तव्य पिछले उस वक्तव्य से बहुत भिन्न था, जो तंग सियाओ पिंग ने सोवियत विखंडन के दौरान खास तौर पर दिया था।

उसी समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण, गोपनीय दस्तावेज में अमेरिका विरोधी राजनीतिक लाईन को निकाला गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय संचार विभाग व विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा निकाले गए इस दस्तावेज में कहा गया "we have the experience of dealing with the Americans on the battlefield. They are nothing terrible. The war theatre may be selected by the Americans in Korea, Taiwan. They have nuclear weapons, so have we."[22]

इस दस्तावेज पर तंग सियाओ पिंग ने "too tough" कहा तथा आने वाले समय में अमेरिकियों से बातचीत के दौरान "flexibility" रखने जैसे शब्दों का प्रयोग किया।

अमेरीकी सचिव तीन दिन की यात्रा के लिए १५ नवम्बर को चीन पहुँचे बिना किसी भव्य स्वागत के तथा टेलीविजन कवरेज के उनसे बातचीत की गई। उनकी १८ वें लम्बी बातचीत में मानव अधिकार का मुद्दा छाया रहा जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के Jiang Zemin, राष्ट्रपति Yang Shangkun , प्रधानमंत्री Li Peng, विदेश मंत्री Qian Qichen और विदेशी आर्थिक सम्बन्धों तथा व्यापार मंत्रालय के Li Langing साथ हुई थी।

Li Peng ने कहा - "over the past 100 odd years, the Chinese nation has had its fill of aggression and devastation by foreign powers. We therefore highly treasure our independence and sovereignty."[23]

---

21 *FBIS-CHI*, 6 November 1991, pp. 28-30. "Enemy troops are outside the city wall. They are stronger than we. We should be mainly on the defensive."

22 *FBIS-CHI*, 10 January 1992, pp. 23-24.

23 *Renmin ribao*, 18 November 1991, pp. 1, 4 in FBIS-CHI, 20 November 1991, p. 4.

तंग सियाओ पिंग व उनके विरोधियों के बीच विवाद का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धान्तिक पत्रिका Qiushi पर काफी प्रभाव पड़ा। जुलाई १९९१ में इस के बतौर दावा किया गया "opening the door to the outside world" की नीति के तहत पूंजीवादी विचार चीन में प्रवेश कर रहे हैं। इसके चलते जरूरत है विचारधारात्मक महान दीवार की।" परन्तु आश्चर्यजनक तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करने वाले इन निर्देशों को प्रभावित करने वाले इन निर्देशों का हवाला १९९२ जनवरी के Qiushi में नहीं मिलता। जहाँ July के दौरान विवाद व संघर्ष के प्रमुख बिन्दु "पूंजीवाद या समाजवाद" थे वहीं १९९२ में यह मूलतः मानव अधिकार के उन मुद्दों की ओर खिसक गए जिसके बारे में आम राय थी कि ये मुद्दे अमेरिका एकाधिकारवादी पूंजीवादी सरकार के समाजवाद के खिलाफ कदम हैं।" यहां महत्वपूर्ण रूप से १९९२ की उस सोवियत विखंडन पश्चात् परिस्थितियों का समय आ गया जिसमें चीन का आँकलन उसकी, समझदारी, विदेशों से सम्बन्धों के बारे में उसकी राय में मतभेदों के बावजूद बदलने के संकेत साफ दिखते हैं।

१.१. सैद्धांतिक मतभेदों का उभार

तंग सियाओ पिंग उसके विरोधियों की बीच विमर्श ने Qiushi को काफी प्रभावित किया। जुलाई १९९१ में यह कहा गया था कि "opening the door to outside world" resulted in capitalist ideas, इसलिए इसके खिलाफ "a great wall ideologically" बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का कोई भी सम्बन्ध जनवरी १९९२ के मुद् दों पर सामने नहीं आया। जिस तरह जुलाई में विवाद प्रमुखतः समाजवाद व पूंजीवाद के बीच था, परन्तु अब यह मूलतः मानवाधिकार तथा 'अमेरिकी पूंजीवाद व सरकार का समाजवाद व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा के खिलाफ हमले की तरफ घूम गया।

१९९२ की १४वीं पार्टी कांग्रेस से पहले तंग सियाओ पिंग अचानक राजनीतिक परिपेक्ष्य से बाहर हो गए, यह वह समय था जब तंग अपने दक्षिण प्रांतों की यात्रा पर थे "इसी दौरान

Deng Xiao Ping का महत्वपूर्ण वक्तव्य आया" Now we are subject to influence from both leftist and rightist ideas १९९३ में वामपंथ पर इस वक्तव्य का और कड़ा रूप सामने आया जिसमें मुख्य समस्या के तौर पर 'वामपंथी' का मुख्य माना गया।"[२४] शान्तिपूर्ण विकास को तंग सियाओ पिंग ने नए तरह से परिभाषित किया।" तंग ने कहा "The Threat was neither present or imminent because hostile forces pin their hopes on the people of several generations following us, when we people of the older generation are still around and have weight, hostile forces are aware no change can be be affected,[25] दूसरा वक्तव्य यह कहता था कि दरअसल समस्या भीतर से है बाहर से नहीं "if something wrong occurs in China, it will come from within the communist party" यह सोवियत संघ के बिखराव के बाद से बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्यों में से एक है गौरतलब है कि १९८९ में जो, घटना थियेनआनमेन पर घटी उसके सन्दर्भ में तंग सियाओ पिंग का कथन था "International Climate was the major cause of trouble" या दरअसल समस्या की वजह Four Cardinal Principal तथा bougieois, liberalization के बीच संघर्ष से उत्पन्न हुई। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ के बिखराव से उत्पन्न हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आंकलन, समस्या को प्रदेश व पार्टी की तरफ घुमा देता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के पतन के दौर में चीन की दमन को व पार्टी की नीति को वैधता देते हुए समस्या का स्रोत विचारधारात्मक व राजनीतिक रूप से बाहरी रूप में सम्बोधित किया। यह १९८९ के बाद वैचारिक रूप से यह एक नयी समझदारी की ओर इशारा करता है और इस समझदारी का महत्वपूर्ण संदर्भ बिन्दु साफ तौर पर सोवियत संघ का बिखराव था। इसी के चलते चीन में दो तरह के बदलाव वैचारिक राजनीतिक रूप से तंग सियाओ पिंग के वक्तव्यों में आते हैं। पहला, चूंकि समस्या की

---

24 This passage is longer and stronger in the subsequent official version, with "leftist" ideas "particularly deep-rooted" and "the 'leftist' things have done terrible harm to our Paryt in the past." Therefore while guarding against "rightism", "China should mainlyguard against 'leftism'."

25 The later version read "imperialism" instead of "hostile forces".

वजह Internal है तो विदेशों से सम्बन्ध सुधारने की बात को वैधता मिलती है दूसरे चूंकि समस्या "भीतरी" है वह भी पार्टी में तो leftism मुख्य समस्या है जो सुधारों के विरूद्ध है। तंग के विरोधी हालांकि लम्बे दौर से सुधार समर्थक रहे; परन्तु १९८९-९१ के घटनाक्रमों ने उन्हें चेताया जिसके चलते तंग का विरोध सुधारों पर लगाम आदि महत्वपूर्ण होने लगे वहीं दूसरी ओर तंग के 'southern tour' वह १४वीं पार्टी कांग्रेस के बीच leftism को मुख्य तौर पर समस्या तथा peaceful evolution को अधिक तरजीह न देना, नए अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन की आगामी स्थितियों को तय कर रहा था। १४वीं पार्टी कांग्रेस के पश्चात तंग सियाओ पिंग ने अपनी अमेरीकी नीति पर हमले को मानने से इनकार करते हुए कहा some in the Party want to ally China with the north, support the north and resist the United States." "China and the United states are different in political ideology but there is no conflict between their fundamental interest, we do not have contention in politics, territory, or resource or problems left over from history in other region."[26]

तंग सियाओ पिंग ने इसके साथ ही प्रचार विभाग पर हमला करते हुए मार्च में छह पृष्ठों के दिशा-निर्देश न्यू चाईना न्यूज ऐजेंसी (NCNA) को भेजो, जिसमें अमेरिका की गंभीर आलोचना न करने पर जोर था।[२७]

"We should adopt a careful and positive policy and report well on bilateral relations and exchange between China and the United States..... As for US, words and deeds interfering in our internal affairs and harming our sovereignty - we should expose this but we should carry out a reasonable, beneficial restrained struggle and not use phrases such as 'Western hostile forces headed by the United States'..... We should not mention names of U.S. leaders lightly alluding indirectly to negative

---

26 *FBIS-CHI*, 6 April 1992, pp. 1-2.

27 *South China Morning Past*, 28 March 1992, p. 11, in FBIS-CHI, 30 March 1992, p. 2. The report was filed from Beijing.

references to 'Bushism'.[28] इसके पश्चात अमेरिका पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हमलों में बहुत कमी आयी। Peaceful Evolution, the threat from 'Western hostile forces' and 'US imperialism' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम हो गया।

अन्ततः अमेरीका के साथ सम्बन्धों और वर्तमान राजनीतिक संकटों में बहस पर तंग की समझदारी को पार्टी ने मान लिया। परन्तु तंग का विरोध कम नहीं हुआ। १४ अप्रैल को CAC ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को एक पत्र लिखा जिसके अनुसार तंग ने वामपंथ को मुख्य समस्या के तौर पर ईंगित किया है परन्तु असल समस्या का स्रोत १० सालों से rightist tendency तथा bourgeois liberalization है। साथ ही 'open door policy' के संदर्भ में उन्होंने कहा "we should not rely on the west in our constructions till less should we wish for western alliance or co-operation trade, exchange and credit cannot be separated from the actual political system or Global strategy of hegemonist capitalist countries. Economy is the main means employed by hegemonist countries in carrying out blackmail, subversion, peaceful evolution and intervention." चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के व पीपुल्स आर्मी के इन सेवानिवृत्त जरनलों की तरफ से पूंजीवादी देशों पर निर्भर रहने की समझ का कड़ा विरोध किया गया।

लेकिन बावजूद इसके अप्रैल १९९३ में Pla के ११६ उच्च अधिकारियों ने तंग सियाओ पिंग व सियांग जेमिन को पत्र लिखकर व्यापक राजनीतिक ब्यूरो की बैठक करने को कहा। इस पत्र में अमेरिका के खिलाफ संभावित aggressive नीति अपनाने की बात कही। इसने दावा किया कि "China's unilateral concession had impaired the dignity of the Chinese People, damaged the image of the Chinese nation, undermined the glorious tradition of the people's libration army and dampened the PLA's moral and canbut effectiveness." एक मई को इस संख्या में ५० सेवानिवृत्त तथा

---

[28] *FBIS-CHI*, 6 May 1991, p. 1.

कार्यरत जरनलों का ईजाफा हो गया, इन्होंने तंग से सीधे मिलकर पत्र सौंपा" जिसमें उन्होंने नीतियों में बदलाव की चिंता रेखांकित करते हुए कहा "we follow in the steps of the former soviet union, resulting in a situation of state disintegration and social turbulence. We will thenbe condemned by history and China might once again be reduced to a semi-colonial country."

तंग सियाओ पिंग और आर्मी के बीच अमेरीका को लेकर यह विवाद अपने संदर्भ के चलते अति महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के विघटन का तथा समाजवादी ब्लाक के पतन के प्रभाव को चीनी राजनीति में दोनों रूपों से देखा जा सकता है, एक और जहाँ तंग इसका हल, अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारने, No confrontation तथा आर्थिक विकास के जरिए देख रहे थे, वहीं उनके विरोधियों में अमेरिका विरोध व 'संघर्ष के बिन्दु प्रमुख थे दोनों ही समझदारियों में संदर्भ महत्वपूर्ण रूप से पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ रहे थे।

इसी प्रक्रिया में Jaing Jemin ने बढ़ते विरोध के चलते तंग से थोड़ा अलग राय रखी और कहा - "The position of the revolutionaries of the elder generation disidentical with that of the CCP Central Committee political bureau state council and central military commission." परन्तु तंग सियाओ ने अपनी समझदारी पर समझौता नहीं किया, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों के चलते उसकी भाषा में कुछ परिवर्तन जरूर आया "it now seems our policy towards the United states need to be examined it is true that we cannot be dependent on a certain big power in opening up and developing trade we will be easily subjected to interference, control and blackmail by means of political factors." परन्तु इसी भाषा में उन्होंने अपनी नीतियों पर अडिग रहने का संकेत दिया - "The central authorities have a plan to extricate ourselves from passivity within two to three year's problem of deviation to the right and worshipping the united states do not exist in our relation with the united states. Thus it will be

unsuitable to criticize and blame it from the high plane of principal."[29] जहाँ एक तरफ तंग सियाओ निरंतर १९८९ की घटना व खासतौर पर १९९१ के बाद avoid confrontation की बात करते रहे वहीं सम्प्रभुता के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया, तिब्बत, हांगकांग ताईवान को वह Internal affair के रूप में सम्बोधित करते रहे, चीनी राजनीति में सम्प्रभुता व अल्पता का यह, पक्ष तंग ही नहीं माओ के समय से ही एकरूप में हमेशा मौजूद रहा है। बरहाल, इस बहस में एक और गंभीर विमर्श २५ नवम्बर से ५ दिसम्बर तक एक कांफ्रेंस के जरिए जुड़ा आर्मी व सिविलियन की इस कांफ्रेंस में ६० पेपर पढ़े गए, इसमें सहमति बनी थी "U.S. hegemonism" will target china to change the course of its ideology by "ideological infiltration into China's upper strata.[30]

जनवरी में तंग सियाओ पिंग दुबारा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उच्च अधिकारियों से मिले तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हुए उन्होंने कहा "Of course there are some countries hoping China will have great Chaos, such as a civil war - Its is also possible that some people may try to make trouble in China with support from foreign countries and hostile forces - foreign countries and hostile forces have never stopped trying to make trouble in China." Therefore "it is correct for the leadership group of our army to have such an awareness."[31]

मूलतः तंग सियाओ पिंग द्वारा समर्थित नीति में १९८९ व १९९१ वो संदर्भों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखता है। १९८९ में बुर्जुआ उदारीकरण को समस्या के रूप में "बाहरी" तत्व करार देना या यह कहना "International Climate was the cause of trouble" एक

---

29 The four reportedly were Song Renquiong, Qin Jiwei, Wang Enmao and Zhang Aiping, who "shed tears while they appealed to Deng". Ibid.

30 *FBIS-CHI*. 25 January, 1994, p. 4-6.

31 Lo Ping, "When I am no longer around, will China plunge into great chaos?" *FBIS-CHI*, 3 February 1994, pp. 26-29.

साथ दो तरह की बात करना था। चीन १९८९-९० के बाद कूटनीतिक तौर पर दुनिया से अलगाव की स्थिति परन्तु १९९०-९२ में चीन ने विदेशों से सम्बंध सुधारने के दिशा में तीव्र प्रगति की। बचे हुए समाजवादी देशों व तीसरी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों से भी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए।

चीन के समाजवादी देशों से सम्बन्धों को सुधरने की शुरूआत अक्टूबर १९९१ से हुई, उत्तरी कोरिया से Kim Il-Sung पेईचिंग की यात्रा पर गए सोवियत संघ के विघटन पश्चात दो बड़े समाजवादी देशों के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी अक्टूबर १९९२ में चीनी राष्ट्रपति, Yang Shang Kun, Pyongyang पहुँचे तथा उन्होंने Kim को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी। अगस्त १९९२ में चीन की तरफ से दक्षिणी कोरिया की यात्रा भी हुई, जिसका उद्देश्य, दक्षिण कोरिया से अच्छे सम्बन्ध बनाना था।

पेईचिंग का नेतृत्व वियतनाम से भी सम्बन्ध था, विकसित करने का इच्छुक था। इस सम्बंध में वियतनाम के रक्षा मंत्री Le Duc Anh की जुलाई १९९१ में चीन यात्रा एक बड़ा कदम थी। पेईचिंग व हानओई (Hanoi) के बीच बेहतर सम्बन्धों के तौर पर उसी साल वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जरनल सेक्रेटरी Do Muoq की पेईचिंग यात्रा को रिश्तों में स्वाभाविकता आने की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। चीन की तरफ से 'Li Peng' चीनी प्रधानमंत्री ने अगले साल वियतनाम की यात्रा की। ये दो देश जो आर्थिक सुधारों की सड़क पर थे; अपने मतभेदों को छोड़कर दोनों देशों ने सहयोग की नीति अपनाने पर जोर देने लगे।

पेईचिंग ने तीसरी दुनिया के देशों से अपने कूटनीतिक सम्बंधों को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। विदेश मंत्री Qian Qichen की नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण कदम, August 1990 में Indonesia से कूटनीतिक सम्बन्धों का शुरू करने में दिखता है।

इसी को रखते हुए अगले साल सिंगापुर से भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की तथा कूटनीति को जारी रखा गया।

मध्य पूर्व के देश चीन का एक और लक्ष्य थे; जिससे वह जल्द ही सम्बन्ध सुधारना चाहता था। जुलाई १९९० में सऊदी अरब ने अपने कूटनीतिक, सम्बन्धों को आगे बढ़ाते हुए नया दौर शुरू किया। पेईचिंग ने साथ ही दूसरे देशों की नई सतारूढ़ सरकारों से संबंध बढ़ाने की पहल भी की। दिसम्बर १९९१ में Li Peng ने दिल्ली की यात्रा की ३१ सालों में किसी चीनी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी।

तीसरी दुनिया के देशों के साथ-साथ चीन ने विकसित देशों से सम्बन्धों को सुधारने की भी पहल की। G-7 की बैठक में १९९० में जापान ने चीन को न केवल कर्ज देना स्वीकार किया अपितु और देशों को की ऐसा करने को कहा। उसी साल October 1991 में European Community (EC) ने भी चीन के खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया। जापान के साथ सम्बन्धों की नई दिशा चीन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। क्योंकि जापान चीन को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश था। वे 180 billion Yen loan के पैकेज का चीन में आठवीं पंचवर्षीय योजना (१९९१-९५) में चीन के आधुनिकीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ा। जापान से सम्बन्ध सुधारने के पश्चात अन्य पश्चिमी देशों का आर्थिक प्रतिबंध कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गया था।

१० अगस्त १९९१, Kaifu वह पहले ४-७ के नेता थे जिन्होंने थ्येनआनमन में की घटनाओं के बाद से चीन की यात्रा की थी। आने वाले दो महीनों में ब्रिटिश Prime Minister Johan Major, इटली की प्रधानमंत्री Andreotti और यूरोपीय कमीशन के उप-राष्ट्रपति ने एक के बाद एक चीन की यात्रा की। अन्ततः नवम्बर १९९१, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य, सचिव James Baker पेईचिंग आये ।

हालांकि दूसरी और यह सभी देश लगातार चीन से यह आग्रह करते रहे कि चीन को मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, हालांकि चीन ने इस पर कोई समझौते नहीं किया।

पेईचिंग का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अलगाव समाप्ति का यह अभियान जारी रहा, ३१ जनवरी १९९२ को U.N. Security Council की मीटिंग में ली पिंग (Li Peng) ने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात की। जापान के Emperor Akihito की, २३० (to) १९९२ की बैठक ने चीन के विकसित देशों से सम्बन्ध सुधारने की पहल का बहुत अधिक मजबूत किया।

पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासनों की समाप्ति व सोवियत संघ के बिखराव से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर चीनी कम्युनिष्ट पार्टी की राय कुछ संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल १९८९ में पूर्वी यूरोप के पतन व थ्येनआनमेन घटना से लेकर १९९१ के सोवियत विखंडन तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नीतिगत स्तर पर कोई निर्णायक दिशा तय नहीं कर पायी। यहाँ तक की सोवियत यूनियन के बिखराव थ्येनआनमेन की घटना, पूर्वी यूरोप के पतन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विश्लेषण में कई बार, अतार्किक व सुनियोजित बदलाव देखने को मिलते हैं ठीक, उसी तरह जिस प्रकार सोवियत संघ में गोर्बाचौव के सत्ता में आने से दिसम्बर १९९१ तक गोर्बाचौव के बारे में तीन तरह के विश्लेषण सामने आए। प्रक्रिया १९९१ में सोवियत विखंडन के पश्चात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद के रूप में साफ ईंगित की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय परीदृश्य के बारे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी उस समझदारी से विचलित होती है जो उसने १९२९ में बनाई थी जहाँ उसने कहा था कि ''बुर्जुआ उदारीकरण'' व 'चार कार्डिनल प्रिंसपल' के बीच का द्वन्द्व समस्या की जड़ है। और १९९२ में साफ तौर पर समस्या के बुर्जुआ उदारीकरण व शान्तिपूर्ण विकास था अमेरीकी साम्राज्यवाद को न ठहराकर पार्टी में leftism तथा अपनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सम्बोधित किया। यही नहीं सीधे तौर पर अमेरीका से जो confrontation की नीति और, उसकी आलोचना न कर सहयोग के बारे में बात करना इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन ने समाजवादी

ब्लॉक के बिखराव से जो समझदारी बनाई, वह दरअसल उन परिस्थितियों व राजनैतिक दबावों से निकलती है जो सोवियत विखंडन के बाद उत्पन्न हुई। वहीं दूसरी ओर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत विखंडन के पश्चात् अमेरीका व पश्चिमी ताकतों से संघर्ष की नीति अपनाने व बुर्जुआ उदारीकरण के खिलाफ शान्तिपूर्ण विकास के खिलाफ वैचारिक व राजनैतिक संघर्ष करने वाला भी एक पक्ष मौजूद था।

यह पक्ष जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व सेना का एक हिस्सा था; इस बात पर जोर दे रहा था कि चीन को आर्थिक सुधारों के बारे में पुनर्विचार कर "बुर्जुआ सोच" व तत्वों से संघर्ष करना चाहिए, हालांकि १९९२ की पार्टी कांग्रेस में इन सब दरकिनार करते हुए पार्टी ने अमेरीका उन्मुख सहयोग की नीति पर ही जोर दिया।

अध्याय - ३

समाजवाद निर्माण के विभिन्न अनुभवो पर चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के विचार

चीन के सुधार-समर्थक नेताओं की तरह गोबाचोव भी इस बात के पक्षधर थे कि समाजवाद का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वे इस प्रक्रिया को अतीत की समस्याओं के निराकरण और सुधारों के लिए ज़रूरी समझते थे। 'नई सोच', 'समाजवाद का नवीनीकरण' तथा 'मानवीय और लोक-तांत्रिक समाजवाद' जैसे प्रत्यय गोर्बाचोव की इन्हीं कोशिशों की ओर संकेत करते हैं । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नज़र में समाजवाद का क्षरण और अंततः 1991 में सोवियत संघ का पतन गोर्बाचोव की इन कोशिशों के परिणाम थे । यहां यह देखना ख़ासा महत्वपूर्ण होगा कि इन दोनों देशों के सुधार कार्यक्रमों की भिन्नताओं और उसके फलस्वरूप समाजवाद के भीतर जो परिवर्तन हुए, उनमें वैचारिक पुनर्मूल्यांकन की क्या भूमिका थी ।

चीन और सोवियत संघ के घटना-प्रक्रमों की तुलना करने से हमें जहां इस सवाल को समझने में भदद मिलेगी, वहीं पुनर्मूल्याँकन के चीनी प्रयास की विशिष्टता को समझने की भी दष्टि प्राप्त होगी । इस अध्याय में माओत्तार चीन और गोर्बाचोवकालीन सोवियत संघ में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया और अन्तवर्स्तु को तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास किया गया हैं । प्रस्तुत अध्ययन में सुधार-समर्थक नेताओं और उनके समर्थकों के दष्टिकोण को केंद्र बनाया गया है।

दोनों देशों में समाजवाद पर पुनर्विचार करने का उपक्रम इन सवालों को उठाए जाने के साथ शुरू हुआ कि समाजवाद के सिद्धांत और व्यवहार की सही समझ क्या है। पुनर्विचार की प्रक्रिया को इस बिन्दु से शुरू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वांछित परिवर्तन को वैध ठहराने के साथ-साथ समाजवाद के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता भी व्यक्त की जा सके ।

चीन में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अर्थात 1970 के दशक के अंत में उभरने वाली सत्य की बहस का एक केंद्र बिन्दू कम्युनिस्ट पार्टी का अंधमाओवाद था । यह समूह मौजूदा नीति और विचारधारा में बदलाव लाने के सख़्त ख़िलाफ था । अतः पुनर्मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में हुआ कि जड़सूत्रावाद और माओ के ''रेडिकल'' समाजवादी आग्रहों की कमियों को रेखांकित करते हुए समाजवाद की एक ऐसी समझ को विकसित करना ज़रूरी था जो सिद्धांत के वस्तुनिष्ठ संदर्भ और समाज की विशिष्ट स्थितियों पर समुचित ध्यान दे। इस प्रक्रिया के तहत माओत्तार दौर के नेतत्व ने माओ के रेडिकल चिंतन पर गंभीर प्रश्न खड़े किए और देश के लिए एक अलग रास्ते की तज़बीज करने लगे ।

सोवियत पुनर्मूल्याँकन के आरंभिक चरण - आद्रोपोव के कार्यकाल से लेकर गोर्बाचोव के प्रारंभिक दो वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा समाजवाद के प्रति अपनाया जा रहा जड़सूत्रवाही रवैया ही था ।1984 के आरंभ से बौद्धिक और सरकारी हलकों में दो स्थापित मतों को लेकर विचार विमर्श का सिलसिला शुरू हुआ । ये दो मत इस प्रकार थे - १. 'विकसित समाजवाद' का सिद्धांत जिसके अनुसार सोवियत संघ में समाजवाद परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका था और वह समाजवादी उत्पादन संबंधों के आधार पर कार्य कर रहा था । यह मत ब्रेजनेव के काल में विशेष रूप से प्रचलित था । २. दूसरा मत इस तर्क पर आधारित था कि समाजवादी व्यवस्था के स्थापित होते ही उत्पादन संबंध स्वतः ही उत्पादक शक्तियों के अनुकूल ढल जाते हैं, और इस प्रक्रिया में समाजवाद के विकास के लिए असीमित संभावनाएं पैदा करते हैं ।' ये दोनों ही मत मौजूदा उत्पादन संबंधों की बुनियादी सत्यता में विश्वास करते थे । सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर इन मतों को असंदिग्ध समझा जाता था ।बाद के वर्षों में गोर्बाचोव ने इन धारणाओं के संबंध में कहा था " कि इन विचारों को समाजवाद बुनियादी लक्षण माना जाता था । परन्तु इन धारणाओं को इतना जड़ और कट्टर बना दिया गया था कि किसी भी तरह के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विश्लेषण की संभावनाएं ख़त्म हो गई थीं" ।[1]

---

1. Mikhail S. Gorbachev, report at the CPSU Central Committee Plenum on January 27, 1987, *Pravda*, January 28, 1987.

सोवियत संघ में समाजवाद के विकास से संबंधित इस प्रस्तावना के मत में यह बात थी कि उस काल के कुछ निश्चित कार्य भार थे। अतः सोवियत संघ के दो पूर्व नेताओं ने सोवियत समाज के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। लेकिन इन लक्ष्यों के साथ मूल समस्या यह थी कि वे गलत आंकलन पर आधारित थे । इसलिए उनके अनुरूप जिन आर्थिक नीतियों को तज़बीज़ की गई थे वे भी असफ़ल सिद्ध हो गईं। निकिता ख्रुश्चेव के नेतत्व में (1961) आयोजित C.P.S.U. के तीसरे पार्टी कार्यक्रम में एक ऐसे संक्रमण काल की बात की गई थी जिसके अनुसार 1980 के दशक तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट समाज का लक्ष्य प्राप्त हो जाना था । तदनुरूप यह घोषणा की गई कि कम्युनिज़्म का पूर्ण निर्माण ही अब देश का व्यावहारिक कार्यभार है । 1971 की बीसवीं कांग्रेस में ब्रेझनेव ने ख्रश्चेव की उस त्वरिकत और अविवेकपूर्ण घोषणा का स्वर मंद करते हुए उसमें विकसित समाजवाद' की लंबी अवस्था का फ़िकरा जोड़ दिया । हालांकि इस अवधारणा के तहत कम्युनिज़्म के लक्ष्य को अनिश्चित काल तक टाल दिया गया, परन्तु सोवियत व्यवस्था की महान उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए इस अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता रहा । उल्लेखनीय है कि कथित अवधारणा समाज की वास्तविक समस्याओं को उद्घाटित करने के बजाए सफलताओं की ज़्यादा बात करती थी। अतः हुआ कि चीन यह अवधारणा भी किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोध में खड़ी थी ।

सोवियत संघ में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया ठीक उसी समय शुरू हुई जब 'विकसित समाजवाद' की अवधारणा का परित्याग कर दिया गया । 1984 में Yuri Andropov और गोर्बाचोव ने सोवियत समाजवाद के विकास-स्तर पर बात करते हुए यह तकरीर की कि सोवियत संघ समाजवाद के निर्माण की लंबी अवस्था के 'पहले चरण में ही है । उनके मुताबिक वर्तमान दौर का एक महत्वपूर्ण कार्यभार इस विकसित समाजवाद को सुधारना था। इस बात का साफ़ अर्थ था कि व्यवस्था में कुछ ख़ामियां थीं जिन्हें दूर करने के लिए सुधार ज़रूरी थे ।[3] गोर्बाचेव द्वारा 1985 में

3. Yuri Andropov, "Ucheniye Karl Marx I Nekotorye Vonrosy Sotsialisticheskolo stroiteltva v CCCP," *Kommunist* 3 (1983): 9-23; and "Gorbachev Keynotes Ideologycal Conference," *The Current Digest of the Soviet Press* (hereafter CDSP) 36, 50 (1985):2.

C.P.S.U. का नेतत्व ग्रहण करने के बाद 'विकसित समाजवाद' के स्थान का प्रश्न सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया। कुछ लोग इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाना चाहते थे जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से दरकिनार करना चाहते थे। फरवरी 1986 में आयोजित 27 वीं कांग्रेस के अवसर पर गोर्बाचोव ने इस अवधारणा पर कुठाराघात करते हुए कहा कि यह अवधारणा समाजवाद की असफलताओं का ज़िक्र न करके आत्ममुग्धता का भाव पैदा करती है । हालांकि पार्टी के नए कार्यक्रम में इस अवधारणा को बनाए रखा गया परन्तु सोवियत विचारधारा के इस महत्वपूर्ण तत्व की बहुत कम चर्चा की गई । नए कार्यक्रम में 'समाजवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमण' की बात न करके 'समाजवाद के सर्वांग सुधार की बात की गई ।[4] इसके बाद 'विकसित समाजवाद' का पद सोवियत शब्दावली से जल्द ही ग़ायब हो गया। वर्षों बाद गोर्बाचेव ने इस धारणा का प्रत्यय - 'विकसित समाजवाद' के साथ उल्लेख किया था ।

इस तरह, अगर 'विकसित समाजवाद' की मान्यता से पीछे हटने का मतलब सोवियत व्यवस्था की ख़ामियां को स्वीकार करना था तो 'सहज अनुकूलन' (Automatic Adaptation) के विचार का नकार इन ख़ामियों के केंद्र की ओर इशारा करता था । गोर्बाचोव ने इस विचार की आलोचना पहली बार 1984 की वैचारिक कांफ्रेस में की थी । उसने कहा था कि उत्पादन संबंधों और उत्पादन शक्तियां को परस्परता ख़ुद ब ख़ुद स्थापित नहीं हो जाती, इसके लिए हमें समाजवादी अर्थतंत्रा के समूचे ढांचे को सतत् और सोद्देश्यपूर्ण ढंग से परिष्कृत करना पड़ता है ।'' इस समीकरण के कारणों को समझाते हुए गोर्बाचेव ने यह कहा कि समाजवादी उत्पादन संबंधों में कुछ तत्व पुराने पड़ जाते हैं और उन्हें संरक्षित करने से आर्थिक और सामाजिक स्थितियां गड़बड़ा जाती हैं । कांग्रेस में उन्होंने 'सहज अनुकूलन' की बात करने वालों से यह सवाल पूछा कि 'पुरातन उत्पादन संबंध क्यों अप्रासंगिक

---

4. For the evolution and decline of "developed socialism," see Alfred Evans, Jr., "The Decline of Developed Scialism? Some trends in Recent Soviet Ideology," *Soviet Studies* 38, 1 (January 1987) : 1-23.

हो गएने इस संदर्भ में उन ऐतिहासिक आपात स्थितियों का उल्लेख किया जिनके चलते एक ख़ास तरह के संबंध अस्तित्व में आए, इसलिए उन्होंने इस बात की दलील दी कि ऐसे संबंधों को समाजवाद में अलग हटाकर देखना चाहिए ।

27वीं कांग्रेस का सूत्रापात करते समय गोर्बाचोव ने 'नई सोच' को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरशाही को और सुधारोन्मुख बनाने का प्रयास किया । इस कांग्रेस के अनेक मसौदे देंग के "emancipation of the mind" के अभियान से मिलते-जुलते थे। कांग्रेस में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिन्दू कट्टर सैद्धांतिक रवैये को छोड़ने और समाजवादी आर्थिक संरचनाओं की नई अवधारणा को अपनाने से संबंधित था। इसी प्रकार एक-दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे के तहत यथार्थ को सही ढंग से समझने और तदनुरूप नीतियां बनाने के लिए लेनिन के रचनात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही गई ।

एक अन्य ऐसे ही संबंधित विषय के बारे में चर्चा करते हुए कांग्रेस में 'द्वंदात्मक सोच' को प्रोत्साहित करने की बात की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि 'यथार्थ को उसके समस्त पहलुओं और अन्तर्विरोधों के साथ देखा जाए तथा उसे नए पुरातन के साथ संघर्ष के रूप में समझा जाए' । गोर्बाचोव ने इस संदर्भ में कहा था कि सबसे ज़रूरी द्वंदात्मक सोच को विकसित करना है, मार्क्स के मुताबिक द्वंदात्मकता किसी भी प्रक्रिया को उल्टा नहीं करती, वह अपनी प्रकृति से ही आलोचनात्मक और क्रांतिकारी होती है ।[5] इस प्रकार गोर्बाचोव की नई सोच डेंग के 'द्वंदात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण' की तरह सैद्धांतिक मताग्रह का विरोध करती थी और व्यवहार के लिए एक नई तरह की मूल्य व्यवस्था स्थापित करने की हिमायत करती थी । परन्तु अपने तमाम बड़बोलेपन के बावजूद तत्कालीन सोवियत नेतृत्व, चीन के सुधार-समर्थक नेताओं के मुकाबले मौजूदा व्यवस्था के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध था । यह नेतृत्व बेझनेव के 'ठहराव' की तुलना में समाजवाद को तकनीकी प्रगति

5. Gorbachev, speech at the all-union confefrence of the heads of social sciences faculties.

alternate n

और त्वरित आर्थिक विकास के ज़रिए सुधारने के पक्षधर था। इसके लिए आर्थिक तंत्र की पुनसंर्रचना करना कम महत्वपूर्ण मुद्दा था । राजनीतिक रूप से गोर्बाचोव की खुलेपन और लोकतांत्रीकरण की नीति मुख्यतः पार्टी के आर्थिक एजेंडा को ही आगे बढ़ाने का माध्यम था ।[6]सोवियत नेतत्व के इन प्रयासों पर लहीम शहीम सिद्धांतों का दबाव था या नहीं था, (चीनी नेतत्व के अभियान पर यह बात लागू नहीं होती) गोर्बाचोव का मुख्य उद्देश्य 'रूढ़िवादी और जड़ ताक़तों' को दरकिनार करता था ।

समाजवाद में संशोधन व सुधार

अप्रैल 1979 से लेकर 1983 के शहरी सुधारों तक चीन में पुनर्मूल्यांकन का फोकस समाजवाद की गलतियों और ज़्यादतियायं पर रहा। यह प्रयास मौजूदा व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करने के साथ शुरू किया गया । आर्थिक क्षेत्र में, इसने चीन की विशिष्ट स्थितियों को नज़रअंदाज़ करके सोवियत सैक्टोरल और आर्थिक मॉडल अपनाए जाने की आलोचना की । राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में इस समीक्षा में यह कहा गया कि कथित दौर में सर्वहारा राज्य के 'रूप' की अवहेलना की गई। ऐसी बौद्धिक और साहित्यिक चर्चाओं को जिनमें राज्य के वर्ग चरित्रा या उसके जनता पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव का ज़िक्र किया गया था, 1981-83 के अभियानों के दौरान दबा दिया गया ।

सोवियत पूर्नमूल्यांकन के दूसरे चरण में दो तरह की समस्याएं सामने आई । पहली - नेतत्व के ऊपरी स्तर पर मतैक्य का अभाव था, दूसरी-नीचे के स्तर पर सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में दिक्कतें आ रही थीं । इस सबके चलते गार्बाचोव ने सोवियत व्यवस्था कीा पेचीदा समस्याओं को गहराई से समझने का आहवान किया । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, 1987 के जनवरी प्लेनम की बैटक आयोजित की गई । प्लेनम से सोवियत व्यवस्था में जड़ीभूत स्टालिनवादी प्रवशत्तियों की विधिवत समीक्षा का सिलसिला शुरू किया गया। ग़ौरतलब है कि प्लेनम की बैठक रूढ़िवादी तत्वों

---

11. Gorbachev, report at the CPSU Central Committee Plenum, April 23, 1985 in Gorbachev, *Speeches and Writings*, 136-38; and political report tot eh Twenty-seventh Congress, in ibid., 36-37, 60-66.

के दबाव के कारण बरसों से टलती आ रही थी । यहां गोर्बाचोव ने अपने भाषण में समाजवाद को उसके मौजूदा रूप से साफ़ तौर पर भिन्न बताया । यह बेहद महत्वपूर्ण है कि गोर्बाचोव ने समाजवाद के मौजूदा रूपों को असली समाजवाद के लिए अहितकर बताया उनके मुताबिक इस विकशति के कारण सामाजिक संबंधों ने अपरिवर्तनीय सिद्धांतों का रूप धारण कर लिया था । इसलिए वह इन मौजूदा विकशतियों को महज ठीक करने की बात नहीं करते थे, बल्कि उन्हें 'अनुपयुक्त और ग़ैर ज़रूरी' मानते थे । इस पुर्नसमीक्षा से यह बात साफ़ हो गई कि मौजूदा उत्पादन संबंधों में सुधार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह बदल देना चाहिए ।

इन घटना प्रक्रमों का देश में व्यापक असर हुआ और लोग सोवियत इतिहास, विशेषकर स्टालिन के काल को ढंग से देखने लगे । समाज के विभिन्न हल्कों में यह बात उठने लगी कि सोवियत इतिहास को ईमानदारी से सामने रखा जाए और उसकी विकसियो को उजागर किया जाए ।

पुनर्सरचना की प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वाली ताक़तों, को सीधे तौर पर स्टालिन की नौकरशाही और प्रशासनिक विरासत के रूप में देखा जाने लगा । इस दौरान समाज के आरंभिक चरण की घटनाओं जैसे खेती के सामूहिकिकरण करने आदि पर बहस खड़ी की गई । यही नहीं सोवियत इतिहास की उन 'खाली जगहों' पर भी जिन पर बात करना वर्जित था, अब पुनर्विचार किया जाने लगा । ग़ौरतलब है कि यह समस्त विचार विमर्श समाजवाद के दायरे के अंदर रहते हुए ही किया जा रहा था । सुधार के पक्षधर इन बहसों में यह दलील पेश कर रहे थे कि ये सुधार स्टालिन द्वारा पैदा की गई विकसियों को दूर करने तथा लेनिन के असली समाजवाद को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न हैं [7] । परन्तु सोवियत आर्थिक तंत्र के मूल मुद्दों पर सवाल खड़े करने के लिहाज़ से सोवियत सुधारक चीनी सुधारकों से एक कदम आगे थे । यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस सारे

7. Gorbachev, report at the CPSU plenum, February 17, 1988, *Pravda*, February 18, 1988; and talk at the meeting with media executives, May 7, 1988, in *Pravda*, May 8, 1988.

बहस-मुबाहिसे में सोवियत संघ के भारी उद्योगों पर आधारित विकास के मॉडल का ज़िक्र छोड़ दिया गया था । आधिकारिक और जन विमर्श का सारा ध्यान आर्थिक तंत्र की पुर्नसरंचना पर था, जिसे अन्ततः पार्टी ने 1987 में अपना एंजेडा घोषित कर दिया । सुधार कार्यक्रम इसी एंजेडा का हिसा थे।

राजनीति के क्षेत्र में सोवियत पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया का स्वरूप और भी भिन्न था । वहां अब खुलेपन और लोकतंत्रीकरण को सिर्फ़ पार्टी के Instrumental लक्ष्य न बताकर, बुनियादी मूल्यों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था । 1987 के प्लेनम में गोर्बाचोव ने लोकतंत्रीकरण को पुर्नसंरचना का 'सार', 'आधार' और 'आत्मा' बताया था और खुलेपन को सूचना के संवाहक के रूप में चित्रित किया था । उनके अनुसार इन दोनों तत्वों का देश के अतीत और वर्तमान को समझने में बुनियादी महत्व था । लोकतंत्रीकरण और खुलेपन की प्रक्रिया को सुदश्ढ़ बनाने के लिए गोर्बाचोव ने 'समाजवाद के अंदर मत-बहुलता' की वकालत करते हुए एकाधिकारवादी चिंतन की निंदा की ।

समाजवाद द्वारा विभिन्न मतों और हितों को धारण किए जाने की क्षमता पर जोर देने के क्रम में गोर्बाचोव ने 'मानवीयता' की एक ऐसी अवधारणा भी सामने रखी जो बाद में चलकर ख़तरनाक सिद्ध हुई। गोर्बाचोव के मुताबिक पुनर्सरचना का अंतिम उद्देश्य समाजवाद की मानवी प्रकृति को उद्घाटित करना था । इस लक्ष्य को पुरानी व्यवस्था में जनता के 'अलगाव' के विरूद्ध एक सकारात्मक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था ।

हालांकि इस काल में बहुलता और मानवीयता के आदर्शों को समाजवादी संदर्भ में ही व्याख्यायित किया जा रहा था, परन्तु गोर्बाचोव के उदार विरोधियों, जो सुधारों की गति को तेज करने के पक्षधर थे, के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया । यह ठीक है, कि इस दौर में येल्तसिन को मास्कों की पार्टी कमेटी के प्रथम सचिव के पद से हटा दिया गया था क्योंकि वे सुधारों को लेकर पार्टी के ठंडे रवैये से असहमत थे। परन्तु गोर्बाचोव के निशाने पर मुख्यतः रूढ़िवादी तत्व ही थे । गोर्बाचोव

के सत्ता ग्रहण करने के बाद से लेकर अक्टूबर 1987 तक पोलित ब्यूरो के दस सदस्यों में से आधे सदस्यों को हटा दिया गया था । और गोर्बाचोव के वैचारिक सहायक के तौर पर ए. एन. याकोव लोव की नियुक्ति की गई थी जिन्हें उदारवादी समझा जाता था । रूढ़िवादी तत्वों से मुक्त होने के चलते ही C.P.S.U. व्यवस्था की जड़ों पर निषेध करने और समाजवाद के बहुलतावादी व मानवीय पहलुओं को प्रकट करने में सफल हो पाई । यह एक ऐसी बात थी जिसे चीनी नेतत्व ने स्वीकार नहीं किया ।

लोकतंत्र का मुद्दा

चीनी नेतत्व पुनर्मूल्यांकन के तीसरे चरण में (1983-1986) जाकर ही पुरातन आर्थिक तंत्र के आधार को नकार पाया और राजनीतिक व आर्थिक सुधारों की अन्तर्क्रिया पर ध्यान दे पाया । हालांकि सी सीपी ने सुधारों की वस्तुगत स्थिति को आंकलन का काम सोवियत नेतत्व से काफ़ी पहले कर लिया था ।[8] परन्तु सोवियत संघ की कमांड अर्थव्यवस्था का निषेध 1984 के शहरी सुधार के समय ही किया गया तथा सोवियत संघ से प्रेरित राजनीतिक व्यवस्था पर 1986 में ही सवाल खड़े किए गए । सोवियत संघ में राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन का काम आर्थिक सुधारों से प्रेरित था और उसका लक्ष्य आर्थिक सुधारों को मजबूत बनाना था । किन्तु चीन में यह प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं थी, न ही उसके तहत C.P.C. के इतिहास की पुर्नसमीक्षा करने का प्रयत्न किया गया । चीन का नेतत्व राजनीतिक सुधारों की एक सामयिक भूमिका देखता था, पार्टी और राज्य को एक-दूसरे से अलग करने की उसकी बात से यह साफ़ जाहिर होता है, लेकिन वह पार्टी के सिद्धांत और उसकी भूमिका को अग्रणी बनाए रखने के पक्षधर थे । उसने बाज़ार अर्थव्यवस्था के आधार पर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने की मांग को कड़ाई से दबा दिया था ।

---

8. For a comparison of Chinese and Soviet reforms, see Lowell Dittmer, "Soviet Reform and the Prospect of Sino-Soviet Convergence," *Studies In Comparative Communism* 22, 2/3 (Summer/ Autumn 1989(: 123-38.

C.P.S.U. की 29 वीं कांग्रेस (1988) से उसके प्लेनम (1990) के बीच के दौर में सोवियत नेतृत्व ने दो नई दिशाओ का आवाहन किया । इस दौर में दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने चिंतन की दिशा तय की । पहली घटना , 29 वीं कांग्रेस के एक प्रस्ताव से संबंधित थी जिसके तहत कि प्राथमिकता को बदल दिया गया । अब का अर्थव्यवस्था के बजाए राजनीति पार्टी का प्रमुख सरोकार बन गई । प्राथमिकता के इस परिवर्तन में गोर्बाचेव ने महत्वूपर्ण भूमिका निभाई । उनके मुताबिक स्टालिन की व्यवस्था में राजनीति की निर्णायक भूमिका थी और वह समाज पर भी इसका चतुर्मुखी प्रभाव था । 29 वीं कांग्रेस ने C.P.S.U. की विचार धारा को अन्य प्रस्तावों तरीकों से भी प्रभावित किया था । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कान्फ्रेंस 'समाजवाद के भीतर मत बहुतलता' के मुद्दे तक ही सीमित नहीं रही, उसने 'लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति' तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों को पूरा करने के लिए पूरी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी बहुलता लाने की वकालत की। C.P.S.U. के तीन क्रांतिकारी प्रस्तावसों में से एक प्रस्ताव में बहुलवाद को 'लोकतंत्रीकरण' और 'खुलेपन' के रूप मं प्रतिष्ठित किया गया था। कान्फ्रेस में पार्टी और राज्य को अलग करने पर भी जोर दिया गया, लेकिन राज्य के अंगों की सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लेनिन के वक्तव्य - 'सारी सत्ता सोवियत को' को उद्धधत किया गया । इससे पार्टी नेतृत्व का दबदबा कमज़ोर पड़ने लगा कांग्रेस के अंत में 'बैरक-समाजवाद' के स्थान पर एक 'मानवीय व लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा ।[9] सोवियत सुधारों के कार्यक्रम में इस नई अवधारणा ने इस मायने में बुनियादी भूमिका निभाई कि इसके चलते सुधारों का लक्ष्य समाजवाद का 'सुधार' न होकर 'विकल्प समाजवाद' को बदलना हो गया ।

सोवियत पुर्नमूल्यांकन के इस चरण में, गोर्बाचेव के समाजवाद और सुधारों से संबंधित एक लेख ने भी महती भूमिका निभाई । उक्त लेख 26 नवंबर 1989 के प्रावदा में प्रकाशित हुआ था

9. Gorbachev, political report to the Nineteenth All-union Conference of the CPSU, *Pravda*, July 19, 1988.

। इस लेख में उन्होंने मानवीय और लोकतांत्रिक समाजवाद' के बारे में विस्तार से लिखा था, तथा कुछ ऐसे भी विचार प्रकट किए थे जो सीपीएसयू के पूर्व मत से ख़ासे अलग थे । गोर्बाचोव ने इन सुधारों को महज समाजवाद को दुरूस्त करने का माध्यम मानने के बजाए, समूची सामाजि संरचना को बुनियादी ढंग से बदलने का माध्यम बताया । यही नहीं गोर्बाचोव ने इन सुधारों को 'लेनिनवादी समाजवाद की ओर वापसी' नहीं कहा, क्योंकि, बकौल गोर्बाचोव, लेनिन के पास भी समाजवाद के निर्माण का पूरा कार्यक्रम नहीं था। इसके उलट गोर्बाचोव ने पुनर्संरचना को ही वह सक्षम तरीका बताया जिसके सौ साल से गलत रास्ते पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को पुनः पटरी पर लाया जा सकता था । इस संदर्भ में उन्होंने सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों के महत्व को पुनः रेखांकित किया। गौरतलब है कि 1914 में लेनिन ने इन पार्टियों की निंदा की थी । अपने इसी लेख में गोर्बाचोव ने 'मानववाद' को समाजवाद का सार तत्व बताया था और भावना भी प्रकट की थी कि सामाजिक कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में 'मानवीय आदर्शों' के प्राथमिकता मिलनी चाहिए । गोर्बाचोव की यह सोच उस समाजवादी दलील की कमजोर बनाती थी जिसके अनुसार राजनीतिक सत्ता का एक निश्चित वर्गीय आधार होता है ।

यह मत समाजवाद के सामाजिक उद्देश्यों की अवधारणा को भी कमजोर बनाता था । अंत में गोर्बाचोव ने समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के वैचारिक टकराव को ख़त्म करने की बात करते हुए यह सलाह दी थी कि समकालीन पूंजीवाद की पुनःसमीक्षा की जानी चाहिए । जहां चीनी नेतृत्व दोनों व्यवस्थाओं के एतिहासिक संरचनात्मक अंतर पर जोर देता था, वहीं गार्बाचोव ने दोनों व्यवस्थाओं को ऐसी विकासशील प्रक्रिया बताया जिसकी अन्तवस्तु दोनों से संबंधित थी । इसी आधार पर उन्होंने दोनों व्यवस्था के 'टकराव' के बजाए दोनों के बीच सहयोग की बात की ।[10]

संक्षेप में यह कहा जा सकता है उस काल में कि लेनिनवाद, समाजवाद पूंजीवाद और

---

10. Gorbachev, "Socialist Thought and Revolutionary Restructuring," *Pravda*, November 26, 1989.

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज़्म की समक्ष को लेकर गोर्बाचोव के विचारों में बुनियादी परिवर्तन आया । तुलनात्मक दष्टि से देखे तो चीन के नेतत्व में यह बात नहीं दिखाई देती । हालांकि गोर्बाचोव दक्षिण और वाम से एक संतुलित विरोध बनाए रखने में सफल रहे, परन्तु सांगठनिक रूप से उन्होंने दक्षिणपंथी रूढ़िवादियों का ज़्यादा प्रबल विरोध किया । सीपीएसयू की सैंट्रल कमेटी के एक असाधारण सत्र में उन्होंने आंदेई ग्रोमिको सहित पांच वरिष्ट नेताओं का हटा दिया । पार्टी के दूसरे नंबर के नेता लिगाचेव, जो इस समय सचिवालय और पार्टी के वैचारिक कामकाज को देखते थे, को गोर्बाचोव ने पार्टी के कषि विभाग का कम महत्वपूर्ण काम सौंप दिया । उसके स्थान पर उदारवादी और सुधार समर्थ वी.ए. मेदवेदेव को पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया। अप्रैल 1989 में पार्टी की केंद्रीय समिति और केंद्रीय निरीक्षण समिति के 110 सेवानिवष्त और वैकल्पिक सदस्य को अपने पदों से इस्तीफा देने को कह गया सितंबर 1989 में केंद्रीय समिति ने उन सभी शेष सदस्यों को पदमुक्त कर दिया जो गोर्बाचोव के सत्ताग्रहण के समय पोलित ब्यूरो में थे । इस तरह की सांगठनिक फेरबदल के जरिए गोर्बाचोव के राजनीतिक विरोध को कमजोर बताया गया ।

अतीत से छुटकारा या समझौता ?

1987 के मध्य से 1989 के मध्य तक चीन की सरकारी विचारधारा में अंतिम तौर पर समाजवाद की एक नई संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ जिसको समाजवाद की प्रारंभिक विचारधारा में व्यक्त किया गया था। किंतु नए उद्देश्यों और नई परिस्थितियों के संदर्भ में समाजवाद को परिभाषित करने के स्थान पर संभवतः उसने समाजवाद की प्रारंभिक चरण की ओर वापसी का संकेत दिया । आर्थिक आधार की (महत्व) केन्द्रीयता को न्यायोचित ठहराने के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत के चुनिदा प्रयोग पर आधारित इस संकल्पना ने मार्क्सवाद के उन पहलुओं को अनदेखा कर दिया जिसमें मानवतावादी पक्षों को संबोधित किया गया था । भौतिकवादी विचारधारा है के प्रति इसका जुडाव धन्य है, नई विचारधारा में आर्थिक क्षेत्र में मार्क्सवादी से भारी अलगाव या किंतु राजनीतिक क्षेत्र में

इस पर न्यूनतम समझौता था । सरकारी ढांचे में इस अवधि के दौरान, कुछ बौद्धिक में तो चीनी शासन के "समग्रवादी" मानवतावाद तथा विश्व आधारित प्रजातंत्र की समीक्षा के साथ सोवियत पुनर्मूल्यांकन के स्तर तक बात की गई । लेकिन विश्लेषण की इस विचार धारा को शासकी विचारधारा में रूपांतरित नहीं किया जा सका । बल्कि उदारता विरोधी अभियान ने 1989 के मध्य के बाद 1989 के बसंत में छात्रों के विरोध आंदोलन को भड़काने के मुख्य स्रोत के रूप में इस पर तीखे हमले किए गए ।

इसके विपरीत सोवियत रूस में फरवरी 1990 की महासभा से प्रचलित समाजवाद के प्रति पूर्ण अलगाव की भावना दृष्टिगोचर हुई और इसकी परिणति जुलाई 1991 की महासभा के रूप में हुई । सोवियत रूस के राजनैतिक विकास के इस ऐतिहासिक चरण में दो महत्वपूर्ण घटनाएं इंगित हुईं : समाज की प्रमुख शक्ति के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का अंत और इस अग्रगामी पार्टी का एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के रूप में अवतरण जिसका स्तर अन्य राजनैतिक दलों के समान ही था । फरवरी 1990 में सीपीएसयू की महासभा में सीपीएसयू के अग्रणी स्तर के बारे में एक प्रमुख निर्णय लिया गया, नई राजनीतिक शक्तियों के आर्विभाव को सुचारू बनाने के लिए बहुदलीय प्रणाली का सञ्जन सहित कम्युनिस्ट पार्टी के विधिक तथा राजनीतिक उच्च स्तर को समदा करने के लिए संवैधानिक संशोधन करते हुए, पोलित ब्यूरो को बदलने के लिए राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित की ।[11] इन विचारों को सोवियत सुप्रीम के असाधारण सत्र के बाद के महीनों में लागू किया गया, इनमें सोवियत संविधान के अनुच्छेद 6 का उन्मूलन भी शामिल था जो पार्टी के अग्रणी स्तर की गारंटी देता था ।

सीपीएसयू की 28 वीं पार्टी कांग्रेस जो जुलाई 1990 में हुई थी मानवतावादी, प्रजातांत्रिक समाजवाद के निकास की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी । यह सम्मेलन पार्टी के उदारतावादी

---

11. Gorbachev's report at the CPSU Central Committee Plenum on February 5, 1990, in *cdsp* 42, 6 (1990): 2-5.

संघवादी, तथा रूढ़िवादी शक्तियों के तीखे संघर्ष के बीच मानवतावादी, प्रजातांत्रिक समाजवाद के मानदंडों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई । रूढिवादियों, जिनका नेतत्व, लिधाचेव कर रहे थे ने पार्टी की की बौद्धिक तथा संगठनात्मक शक्तियों को कम करने का विरोध किया । और श्रमिक वर्गों के हितों को बचाने का दावा किया ।[12] उदावादियों, जिनका नेतत्व येल्तसिन कर रहे थे ने सीपीएसयू को संसदीय पार्टी के रूप में परिवर्तित करने की वकालत की, प्रजातांत्रिक, संघवाद की पुनर्घोषणा की और विश्व स्तर पर मानव मूल्यों का समर्थन किया ।[13] मध्यमार्गी जिनका प्रतिनिधित्व, गोर्बाचोव कर रहे थे, विश्व मानव मूल्यों का समर्थन किया लेकिन उदारवादियों से अलग संसद के माध्यम से सीपीएसयू के अग्रणी संचालक की भूमिका की वकालत की और एक प्रकार से आंशिक तौर पर प्रजातांत्रिक संघवाद को बनाए रखा ।[14] यद्यपि कांग्रेस ने गोर्बाचोव की मूल विचारधारा को स्वीकार किया जिसका परिणाम उदावाद की ओर झुका था । समाजवाद के उद्देश्यों को औपचारिक तौर पर पुनः परिभाषित करना तथा वैयक्तिक तथा बहुलवादी विकास के तथाकथित मानदंडों के संदर्भों में पार्टी की विचारधारा ।

कांग्रेस के कार्यक्रम में समाजवाद को विश्वमानवीय मूल्यों के साथ सूत्राबद्ध कर दिया संसदीय पार्टी सहित एक अग्रणी दल और प्रजातांत्रिाक संघवाद जिसमें मत व्यक्त करने का क्षीण सा राजनैतिक अधिकार और साझा दलों का अस्तित्व । इसने सार्वजनिक उपक्रम और योजना की विचारधारा को नष्ट कर दिया और निर्देशित अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए उसके स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था के एक मात्र विकल्प का प्रस्ताव रखा ।

जुलाई 1991 में महासभा में सीपीएसयू ने इसी वर्ष में बाद के समय अपने विखंडन के पहले

---

12. Ye K. Ligachev, statement for Pravda's "Debate Page," Pravda, May 12, 1990, in : *CDSP*-42, 19 (1990): 4.
13. See the draft Democratic Platform, *Pradva* March 3, 1990, in *cdsp* 42, 19 (1990): 1-3.
14. Gorbachev, speech at the CPSU Central Committee, *Pravda* March 3, 1990, in *cdsp* 42, 11 (1990): 16; speech to Communist of the Capital's Frunze Boroguh, Pravada, May 14, 1990. In *CDSP* 42, 19 (1990): 1-2.

एक नई परिस्थितियों के अंतर्गत एक नई पार्टी कार्यक्रम का मसौदा रखा और समाजवाद के पुनर्मूल्यांकन तथा पुनः समंजित होने का सीपीएसयू का अंतिम प्रयास देखा गया। गोर्बाचोव इस महासभा रिपोर्ट में अपनी 28 वीं कांग्रेस में समाजवादी साम्यवाद तथा पार्टी की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन से एक कदम आगे बढ़ गए । समाजवाद पर वे अपने 'अलंकरण और विरूपण की अपनी पिछली आलोचना से बहुत आगे निकल गए । इसके समग्र सिद्धांत और व्यवहारिकता को नकारने के लिए उन्होंने स्टालिन के काल को एक दलीय परंपरात्मक सत्ता काल की संज्ञा दे दी और स्वलित के बाद के काल को स्टालिनोत्तर काल का नाम दिया। साम्यवाद के बारे में उन्होंने साम्यवाद को उखाड़ के सीपीएसयू के एक मात्रा उद्देश्य को न्यायोचित ठहराया, जिसका कारण साम्यवाद की काल्पनिक सिद्धांतों को बताया गया । उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे और दूसरों के अनुभवों से हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि निकट भविष्य में ये उद्देश्य प्राप्त नही किए जा सकते ।

पार्टी की भूमिका के बारे में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के आमूल परिवर्तन की बात की । भविष्य में पार्टी वर्ग संघर्ष तथा उदारवाद की राजनीतिक अग्रणी के रूप उमें कोई भूमिका अदा नहीं करेगी बल्कि एक प्रजातांत्रिक सुधारवादी राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और विश्व मानव मूल्य के पोषक के रूप में कार्य करेगी और यह एक ऐसी पार्टी के रूप में कार्य करेगी जो सामान्य नागरिक समझौतों तथा चुनावी जीत के लिए होंगी। उन्होंने इसे समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का नाम दिया एक ऐसा नाम जिसे बाल्शेविकों ने 1910 में छोड़ दिया था यद्यपि वे ऐसा कर नहीं सके क्योंकि वास्तव में पार्टी में ऐसे अनेक सदस्य थे जो साम्यवाद में विश्वास रखते थे ।

गोर्बाचोव की इन टिप्पणियों ने जैसा कि महासभा में कुछ प्रतिनिधियों ने शिकायत की थी, का उद्देश्य घरेलू साम्यवादी आंदोलन को कमजोर करके मार्क्सवाद-लेनिनवाद का विनाश करना था । बाद कें महीने में घटनाओं की यह दिशा रूढिवादियों के विद्रोह के रूप में सामने आई जो पुराने

तंत्र को बनाए रखना चाहते थे और रूस विद्रोह की असफलता के साथ ही सोवियत समाजवादी ढांचे का तेजी के साथ विखंडन हो गया ।

चीनी और रूसी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण विरोधाभास दष्टव्य हैं । पहला पुनर्मूल्यांकन के पहले चरण के बाद प्रत्येक तुलनात्मक स्तर पर रूस के सुधारवादियों चीनी सुधारवादियों से एक कदम आगे थे । दूसरे यद्यपि दोनों ने आर्थिक क्षेत्र में अपने-अपने पुनर्मूल्यांकन शुरू किए थे परन्तु चीनी नेता निरंतर इसी बिन्दु पर केन्द्रित रहे जबकि सोवियत नेता आर्थिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में चले गए । तीसरे, चीनी उदारवादी दष्टिकोण जिसने रूसी मुख्यधारा के समीक्षा के स्तर पर स्वर को सत्ता द्वारा निर्विरोध रूप से दबा दिया गया । गोर्बाचोव के रूढिवादियों और उदारवादियों के बीच संतुलन के बावजूद विरोध द्वारा रूढिवादियों के दबाव को पोषित करने के लिए गोर्बाचोव के समस्त काल के दौरान कोई राजनैतिक आंदोलन शुरू नहीं किया गया । इसके विपरीत गोर्बाचेव के शासन में मुख्यधारा की विचारधारा निरंतर उदावादी विचारधारा की ओर झुकती चली गई ।

ये भिन्न प्रक्रियाएं निकटता के साथ चीनी तथा रूसी पुर्नमूल्यांकन से संबंधित थी । पुनर्विवेचन के तीन प्रमुख क्षेत्रों में इन दोनों देशों के चरित्र तथा दिशा को परिभाषित करता है । ये पूर्व समाजवादी अनुभवों की पुनः परीक्षा है, समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार और समाज में साम्यवादी पार्टी का स्थान ।

गोर्बाचोव ने विगत नेताओं की आलोचना करने में भी कोई कोताही नहीं बरती । स्टालिन के शासन को उन्होंने 'व्यक्ति पूजा के दौर' तथा 'तानाशाही की सत्ता' कहकर अभिहित किया । हालांकि ख्रुश्चेव के व्यक्तित्व के कुछ सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, परन्तु Subjectivism और नौकरशाही को प्रश्रय देने का कारण उनकी निंदा भी की गई गोर्बाचोव ने ब्रेझनेव के काल को 'ठहराव' और चौतरफा नाक़ामयाबी का दौर बताया । इस प्रकार पुराने नेताओं में सिर्फ़ लेनिन को

ही को ही वास्तविक समाजवाद का कर्णधार बताया गया । इस अधिकारिक रवैये से प्रेरणा पाकर अनेक उदारवादी आलोचकों ने स्टालिनवाद और सोवियत व्यवस्था की त्रुटियों को लेनिन के काल से भी जोड़ने की कोशिशों कीं और अंततः मार्क्स के मूल सिद्धांत पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।

समाजवाद के तहत व्यक्ति की अहमियत

समाजवाद के पुनर्मूल्यांकन को लेकर चीन और सोवियत संघ के बीच जो फ़र्क़ देखने में आया, उसका ताल्लुक सिर्फ़ अतीत की पुनः समीक्षा करने और वर्तमान तथा भविष्य के लक्ष्यों को तय करने से ही नहीं था । समाजवाद के अन्तर्गत व्यक्ति को मिलने वाला महत्व भी इन मूल्यांकनों की भिन्नता दर्शाता है । अतीत की विफलताओं के विश्लेषण में उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ये विफलताएं पार्टी के एजेंडा को आर्थिक तंत्र से अलगाने, अनुचित उत्पादन संबंध तथा राजनीतिक संरचनाओं को अपनाने का परिणाम थी । विगत नीतियों के परिणामों का विश्लेषण करते हुए उनका जोर वर्ग संघर्ष के आधिक्य तथा उत्पादन शक्तियों में आए संकटों पर रहा । इसलिए नेतृत्व की दृष्टि में, इस पार्टी ऐजेंडा को दुरूस्त कर देने तथा आर्थिक विकास में बाधक बने उत्पादन संबंधों पर अधिरचना के दोषों को दूर तक देने से व्यवस्था के संकटों को दूर किया जा सकता था । सी सी पी ने समाजविज्ञानियों और उदावादी बुद्धिजीवियों के उस विश्लेषण को अस्वीकार कर दिया जिसके अनुसार समाज का वर्गीय निर्धारण और व्यक्ति की महत्वहीनता अतीत की समस्याओं और विफलताओं के बुनियादी कारण थे। सी सी पी ने उदारवादियों के इस मत को बुर्जुआ प्रचार कहकर नकार दिया कि व्यक्ति का अलगाव अतीत की विफलताओं का ही परिणाम है तथा व्यक्ति के महत्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इस संकट का उचित हल है ।

इसके विपरीत सोवियत पुनर्मूल्यांकन के कार्यक्रम में गोर्बाचोव ने अलगाव और मानववाद को

मूल संदर्भ बताया था । 'विकश्त समाजवाद' की अवधारणा में स्वतः यह निर्णय निहित था कि तानाशाही-नौकरशाही पर आधारित व्यवस्था ने 'समाजवाद की मानवीय संभावनाओं' को नष्ट कर दिया था ।

सीपीएसयू की विफलताओं के विश्लेषण में व्यक्ति के अलगाव को विशेष मापदंड बनाया गया था। जैसा कि गोर्बाचोव ने दलील दी थी कि समाजवादी इस बात से निहित है कि व्यक्ति का समाज में, सत्ता से, उत्पादन के साधनों और उसके अधयात्मिक मूल्यों से अलगाव ख़त्म हो सके । परन्तु संकट की बात यह है कि व्यावहारिक रूप में यह जनता के स्वैच्छिक प्रयासों का दमन करता है, उन्हें सर्जनात्मक गतिविधियों से अलगा देता है, तथा व्यक्ति की गरिमा को कुंद करता है । गौरतलब है कि सोवियत संघ के समाज विज्ञानियों ने भी इस बात की तसदीक की थी कि सोवियत संघ की प्रशासनिक कमांड व्यवस्था में वहां का कामकाजी वर्ग राजनीतिक सत्ता से अलगाव महसूस करता है । इसी तरह उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व के चलते मजदूर वर्ग भी अलगाव अनुभव करता है, सोवियत समाजशास्त्री और सुधारों की सिद्धांतकार - तायना जास्लास्काया के अनुसार पार्टी अधिकारियों का सतारूढ दस्ता ही एक 'शासक वर्ग' बन गया है, और वह राजनीति और आर्थिक तंत्र पर अपने नियंत्रण के ज़रिए जनता के सत्ता से अलगाव का कारण बनता है । अन्य लोगों के विचार में अगर के पूंजीवाद में Commodity fetishism व्यक्ति के अलगाव का कारण बनता है तो समाजवाद के तहत सत्ता की ग्रंथि समाजिक अलगाव को जन्म देती है अर्थात इस अलगाव का स्रोत उत्पादन के साधनों के साथ उतना संबंधित नहीं है जितना इन साधनों के राजनीतिक और वैचारिक नियंत्राण से । हालांकि इस अलगाव का कारण 'विकश्त समाजवाद' (न कि स्वयं समाजवाद) को बताया गया था, परन्तु व्यक्ति के महत्व को नकारे जाने के पीछे समाजवाद के वर्गीय चरित्र और Teleological दष्टिकोण को ही ज़िम्मेदार ठहराया गया । 28 वीं कांग्रेस के अवसर पर सीपीएसयू ने व्यक्ति की महत्वहीनता को समाजवाद की वर्ग आधारित अवधारणा से जोडते हुए यह कहा था कि

मनुष्य के सत्ता और संपत्ति से अलगाव के नए रूप सार्वजनिक जीवन के मानकीकरण और सर्वहारा के नाम पर जारी पार्टी और राज्य नेतत्व की तानाशाही के चलते पैदा हुए थे ।

जिस तरह गोर्बाचोव ने अतीत की विफलताओं के निर्धारण में मानवीय अलगाव को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, उसी तरह अलगाव की समाप्ति को पुनर्संरचना का लक्ष्य बताया गया था । मानवीय, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में व्यक्ति को महत्व दिए जाने की बात निहित थी । इस अवधारणा में सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाए व्यक्ति के विकास को सामाजिक विकास का उच्चतम उद्देश्य घोषित किया था। उसी वर्ष, उन्होंने एक भाषण में यह भी कहा था कि 'अगर एक क्षेत्रा में प्रगति होती है और उसी के साथ मनुष्य का मनोवैज्ञानिक राजनीतिक तथा शारीरिक अवमूल्यन भी होता है तो इस अवमूल्यन को जन्म देने वाले तंत्रा पर संदेह किया ही जाना चाहिए''। तदनंतर गोर्बाचोव लगातार यह दोहराते रहे कि पुनर्संरचना का मकसद 'वास्तविक मानववाद', 'समाजवाद की मानवीय संभावनाओं' तथा व्यक्ति का महत्तम विकास करता है । 1990 की 28वीं कांग्रेस के अवसर पर सीपीएसयू ने इस आशय की आधिकारिक घोषणा की कि ''सामाजिक विकास का लक्ष्य व्यक्ति है, उसके लिए रोजगार और आवास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, तथा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे व्यक्ति का राजनैतिक सत्ता, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से अलगाव ख़त्म किया जा सके और उसे सामाजिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया सके ।

दूसरे, मानवीय, लोकतांत्रिक समाजवाद में वर्ग-आधारित मूल्यों के बरअक्स सार्वभौमिक मानव मूल्यों ज़्यादा महत्व दिया गया । 1989 में इतालवी श्रोताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए गोर्बाचोव ने 'विश्व में सार्वभौमिक मानव मूल्यों की प्राथमिकता' स्थापित करने की बात की थी । 28वीं कांग्रेस के अवसर पर गोर्वाचोव ने यह बयान दिया था कि हम समाजवाद में सार्वभौमिक मानव मूल्यों का पुनः प्रवेश कराएंगे, और यह चीज वर्ग चेतना के विरोधी भाव की तरह नहीं बल्कि

मनुष्य की सामान्य प्रवत्ति तौर पर स्थापित की जाएगी । ये मूल्य सहस्रों वर्षों से अर्थवान रहे हैं और हम जानते हैं कि उनकी अवहेलना करने से हम किन संकटों को न्यौता देते हैं । हालांकि ऐसे वक्तव्यों के बाद भी सीपीएसयू समाजवाद और साम्यवादी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताती रही परन्तु अब वह वर्गहीन समाज के निमार्ण की बात पर जोर नहीं देती थी । इसके उलट साम्यवाद के भविष्य को भी सार्वभौमिक मानववाद की अनिश्चित शब्दावली में अभिव्यक्त किया जाने लगा ।

28वीं कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा गया था कि "पार्टी के सामाजिक आदर्श में मानव संस्कृति के सिद्धांत तथा बेहतर जीवन व सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी अकांक्षा का समावेश किया गया है ।' या जैसा कि 1991 में गोर्बाचोव ने कहा था - समाजवाद के विचार और आंदोलन के वास्तविक अर्थ को सभ्यता के सामूहिक विकास के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है ।

इन आदर्शों को प्राप्त करने वाले साधनों को लेकर भी सीपीएसयू के रवैये में बदलाव आया। गोर्बाचेव ने इस संबंध में यह बात कही कि अतीत में एक अन्यायपूर्ण समाज का उन्मूलन करने के लिए जनता के पास हिंसक संघर्षों और क्रान्ति का ही सहारा था परन्तु अब आर्थिक समश्द्धि, सामाजिक बदलाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा ट्रेड यूनियनों के चलते समाजवादी आदर्शों को सुधारों के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है । पहले जहां इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंधों और सर्वहारा की अधिरचना को माध्यम माना जाता था, अब दूसरे समाजों से प्राप्त बहुमूल्य ज्ञान, को भी इन लक्ष्यों को सिद्ध करने का माध्यम स्वीकार किया जाने लगा ।

मानवीय, लोकतांत्रिाक समाजवाद का एक तीसरा पहलू यह था कि अब समाजवाद को मनुष्य की वहत्तर सभ्यता का हिस्सा माना जाने लगा । गोर्बाचोव के अनुसार समाजवाद में 'सार्वभोमिक मानव मूल्यों के प्रवेश से समाजवाद 'वैश्विक रूपांतरण की धारा' में शामिल हो गया। मानव प्रगति की सामूहिकता को स्वीकार करने के बाद समाजवादी व पूंजीवादी चिंतन और विकास का फ़र्क़ बेमानी सिद्ध हो गया। मनुष्यता के सारे संकट को देखते हुए गोर्बाचोव और सुधारों सिद्धांतकारों ने समाजवाद

और पूंजीवाद के बीच सहमति के बिंदुओं की बात करनी शुरू की । इसी के मद्देनज़र फरवरी 1990 के प्लेनम में गोर्बाचोव ने कहा कि 'हमें ऐसी प्रत्येक चीज को त्याग देना चाहिए जिसके कारण समाजवादी देश विश्व सभ्यता की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ गए हैं, हमें प्रगति की उस समझ को भी त्याग देना चाहिए जो सामाजिक रूप से भिन्न दुनिया के साथ टकराव के रास्ते पर ले जाती है । उनके अनुसार नई सोच का उद्देश्य दुनियां को बांटता नहीं बल्कि उसे एक करना था ।

इस तरह अब सीपीएसयू ने अपनी समस्त गतिविधियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर निर्भर करना छोड़ दिया था । अब वह समाजवाद को एक ऐसी व्यापक अवधारणा के तौर पर देखती थी जिसमें महान चिंतकों के विचारों, क्रांतिकारी अनुभवों, तथा 20वीं सदी के वस्तुगत बदलावों को समाहित कर लिया था । 28वीं कांग्रेस के कार्यक्रम में इसी भावना को प्रकट करते हुए यह कहा गया था कि सीपीएसयू समाजवाद के सिद्धांत और व्यवहार के संबंध मं एक ऐसी दृष्टि अपनाये जाने की पक्षधर है जो बीसवीं सदी के ऐतिहासिक अनुभवों से प्रतिकश्त हो तथा जिसमें मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की विरासत का समावेश हो । पार्टी के अनुसार इस नए समाजवाद में मनुष्य की तर्कबुद्धि से उपजी महान उपलब्धियों को स्थान दिया जाएगा, तथा आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक समस्याओं के निराकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने के लिए दिनया के संचित अनुभवों से लाभ उठाया जाएगा ।'' ग़ौरतलब है कि इस टिप्पणी में विश्व के संचित अनुभवों से लाभ उठाने की बात करते हुए इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि उनका स्वरूप गैर मार्क्सवादी होगा या मार्क्सविरोधी । अतः मनुष्य जाति और मानव मूल्यों की सार्वभौमिकता को केंद्रीय महत्व दिए जाने का मतलब समाजवाद का विआदर्शीकरण करता था।

कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान

चीनी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में यह मुद्दा एक समस्या बना रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का समाज में क्या स्थान है । इस संबंध में तीन बिन्दू विशेष महत्व के थे - पहला पार्टी का स्वरूप (वर्गीय), पार्टी

की उच्च भूमिका का स्रोत, तथा अन्य वैकल्पिक राजनीतिक हितों और मतों की बैधता । सीसीपी इनमें से किसी भी बिन्दु पर बुनियादी ढंग से पुनर्विचार करने को तैयार नहीं थी। हालांकि पार्टी ने वर्ग संघर्ष को चीनी समाज की मुख्य परिघटना मानने की बात छोड़ दी थी, परन्तु अपनी अग्रणी भूमिका की वैधता स्थापित करने के लिए वह पार्टी के वर्गीय स्वरूप (अर्थात, सर्वहारा की तानाशाही) पर अब भी जोर देती थी। यह ठीक है कि अब पार्टी ने अपनी वैधता का स्रोत विचारधारा में ढूंढना कम कर दिया था, परन्तु वह अभी भी सत्ता के कानूनी और सांस्थानिक आधार को स्वीकार करने से कतराती थी और अपनी प्रधानता जताने के लिए इतिहास की शरण में जाती थी। हालांकि उसने राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श के दायरे को थोड़ा और फैला दिया था, फिर भी वह विमर्श के दायरे को थोड़ा और फैला दिया गया था, फिर भी वह शासन के गैर-वर्गीय आधार को स्वीकार नहीं करती थी। संक्षेप में पार्टी अपनी सत्ताा और सत्य के एकाधिकार पर सवाल खड़े किए जाने को बर्दाश्त नही करती थी ।

इसके बरअक्स सोवियत नेतत्व ने पार्टी की सामाजिक भूमिका को बुनियादी ढंग से संबोधित किया । सर्वप्रथम नेतत्व द्वारा पार्टी के वर्गीय स्वरूप को नकारने से पार्टी उसकी अग्रणी भूमका की वैधता ख़त्म हो गई । जुलाई 1988 में एक मानवीय, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार को स्वीकार किए जाने के बाद धीरे-धीरे Working Class के बजाय व्यक्ति को समाजवादी की अग्रणी शक्ति और लक्ष्य माना जाने लगा । सार्वभौमिक मानव मूल्यों और मानवतावादी आदर्शों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता ने उसके वर्गीय स्वरूप को क्षीण कर दिया । अंततः पार्टी को महज श्रमिक वर्ग का संगठन मानने के बजाए, यह घोषित किया गया कि पार्टी समान विचारों वाले लोगों का स्वैच्छिक संगठन है ।'' वर्गीय स्वरूप का परित्याग करने के बाद सीपीएसयू के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक जीवन से बाहर रखना, या उन्हें राज्य का शत्रु कह पाना संभव नहीं रह गया था ।

वर्गीय आधार के परित्याग से सीपीएसयू के लिए सत्ता के लोकप्रिय और सांस्थानिक आधार को स्वीकार करना आसान हो गया । 28 वीं कांग्रेस के कार्यक्रम में, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया कि जनता की संप्रभुइच्छा को ही राजनीतिक सत्ता का स्रोत होना चाहिए' ताकि राज्य समाज पर नियंत्रण कायम करने के बजाए व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता, गरिमा, की बिना किसी भेदभाव के रक्षा कर सके । इसी के साथ पार्टी कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए चुनावी प्रतिस्पर्द्धा तथा विधि के नियम को माध्यम बनाना चाहिए ।

सत्ता के लोकप्रिय और सांस्थानिक आधार को स्वीकार करने से, पार्टी के एकांगिक दृष्टिकोण या समाजवादी बहुलता के स्वरों के बजाए भिन्न और विरोधी राजनीतिक हितों एवं शक्तियों को भी वैधता मिल गई । 28वीं कांग्रेस में अन्य राजनीतिक संगठनों को सीपीएसयू के साथ समानता का दर्ज़ा प्रदान करते हुए यह कहा गया कि ये संगठन श्रमिकों, किसानों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, सेवाक्रर्मियों, और वरिष्ठ लोगों के हितों का प्रतिनेधित्व करते हैं सीपीएसयू की अग्रणी भूमिका तथा राजनीति में उसकी केंद्रीयता को ख़त्म करने के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए, गोर्बाचोव ने कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राजनीतिक संगठनों को भी बराबर की भूमिका मिलनी चाहिए । उन्होंने आगे कहा - हालांकि हम सीपीएसयू की सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं परन्तु हम ऐसा लोकतांत्रिक प्रकियाओं की सीमा के अंदर रहते हुए ही करेंगे तथा अपनी सत्ता से किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहेंगे । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों को वैधता देने से पार्टी को सत्ता और सत्य पर स्थापित एकाधिकार को चुनौती मिलने लगी।

जहां चीन के नेतत्व ने अतीत की समस्याओं और वर्तमान के सुधारों को उत्पादन संबंधों के स्तर पर आंकने का प्रयास किया, वहीं सोवियत नेतत्व ने अतीत की विफलताओं और समाजवाद के पुनर्निर्माण पर दृष्टिपात करते हुए व्यक्ति की अवहेलना को ज़्यादा महत्व दिया ।

आखिर में, अतीत के अपूर्ण विश्लेषण तथा व्यक्ति के महत्व पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण सीसीपी अपनी सामाजिक भूमिका पर बुनियादी ढंग से विचार नहीं कर पाई । इसके विपरीत गोर्बाचोव के नेतत्व ने समाजवाद के केंद्र में व्यक्ति को स्थापित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि समाज के अन्य संगठित समूहों के बनिस्वत पार्टी का स्थान अहम् नहीं रह गया ।

समाजवाद के चीनी और सोवियत पुनमूल्यांकनों के बीच दो प्रमुख अंतर थे । इन दोनों देशों में सुधारों की दिशा तथा समाजवाद के भविष्य पर इन अंतरों का गहरा प्रभाव पड़ा। पहले, चीनी पुनर्मूल्यांकन की तरह सोवियत पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया Zigzag नहीं थी । सोवियत संघ में पुनः समीक्षा के इस काम में राजनीतिक अंतरालया समय-समय पर चलाए गए विशेष अभियान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। नेतत्व ने विरोध को प्रतिबंधित न करके उसे अपनी गति से बढ़ने दिया । दूसरे, जहां तक पुनर्मूल्यांकन की अन्तर्वस्तु का प्रश्न है, सोवियत नेतत्व ने चीनी नेतत्व द्वारा खड़ी की गई वर्जनाओं को अपने यहां विकसित नहीं होने दिया उसने स्थापित व्यवस्था के आधार पर गंभीर सवाल खड़े किए और तंत्रा की ख़ामियों को उजागर करते हुए व्यक्ति को राजनीतिक जीवन तथा सामाजिक विकास का लक्ष्य घोषित किया । यही नहीं सोवियत नेतत्व ने विरोधी राजनीतिक विचारों एवं हितों को भी स्वीकृति दी और इस प्रक्रिया में व्यवस्था की अग्रणी भूमिका को नकार दिया ।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि चीन और सोवियत संघ में पुनर्मूल्यांकन का अलग-अलग ढंग से विकास क्यों हुआ ? सोवियत पुनर्मूल्यांकन अपने चीनी दृष्टांत से आगे कैसे निकल गया । इन सवालों की एक संभावित व्याख्या यह हो सकती है । कि प्रारंभिक अवस्था में चीन में आर्थिक सुधारों और आर्थिक समीक्षा का काम ज़्यादा सटीक ढंग से किया गया । चीनी और सोवियत दोनों ही नेतत्वों में विचार को छोड़ने के पश्चात्भारी उद्योगों और मात्रात्मक वद्धि तथा कमांड अर्थव्यवस्था के सोवियत मॉडल को भी गलत बताया । गौरतलब है कि भारी उद्योगों और

मात्रात्मक वद्धि का उद्देश्य निवेश और वद्धि की दिशा को कषि और हल्के उद्योगों की ओर मोड़ना था जबकि कमांड अर्थव्यवस्था को सर्वाहार बाज़ार और ग़ैर सार्वजनिक स्वामित्व के क्षेत्र को पूरक भूमिका में लाना था । पुनसंयोजन और सुधार के ये तरीके सफल रहे जिसके परिणामस्वरूप चीनी नेतस्व ने आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान देने की नीति को बनाए रखे । आर्थिक सुधारों की वस्तुगत सफलता से नेतस्व में यह विश्वास पैदा हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक दायरों को पषक करवा सकता है ।

सोवियत संघ के मामले में आर्थिक सुधारों को प्रारंभिक असफलाओं ने नेतस्व को राजनीतिक व्यवस्था की ओर मुडने को मजबूर किया । चीनी नेतस्व की दष्टि में सोवियत आर्थिक सुधारों की प्रारंभिक असफलता के तीन कारण थे - पहला, सुधारों की शुरूआत के समय सोवियत नेतस्व भारी उद्योगों के मॉडल को पुनःसमायोजित नहीं कर पाया, वह इस मॉडल का उचित आंकलन भी नहीं कर पाया । इस तरह समस्त निवेश और वशद्धि, रक्षा उद्योग सहित भारी उद्योगों पर निर्भर बने रहे । दूसरे उद्यम के स्तर पर शुरू किए गए सूक्ष्म आर्थिक सुधारों के लिए राष्ट्र-व्यापी स्थूल आर्थिक सुधारों की व्यवस्था नहीं की गई जिसके चलते अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई ।

जहां चीन के सुधारों को लागू करते हुए आवश्यक आर्थिक नियंत्राण को बनाए रखा गया और उत्पादन इकाईयों के बीच प्रतिर्स्पद्धा की भावना का विकास किया गया, वहीं सोवियत सुधार उद्यमों की बढ़ती स्वायत्तता पर केन्द्रित थे । उनमें राज्य नियोजन की भूमिका ख़त्म हो गई थी । तथा उन पर स्कूल आर्थिक नियंत्राण कमजोर पड़ गया था । सुधारों की इस प्रक्रिया पर किसी मूल्य, वित्तीय या कराधानी नीति का नियंत्राण नहीं था । तीसरे सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों को अनमने और अव्यवस्थित ढंग से लागू किया गया । सोवियत नेतस्व ने तीसरी समस्या पर ध्यान दिया था और, इसी कैडर के विरोध और जनता की उदासीनता का परिणाम बताया था । इसी के चलते नेतस्व ने राजनीतिक सुधारों की ओर रूख किया । परन्तु राजनीतिक सुधारों के राष्ट्रीय चर्चा का विषय

बनते ही, गर्मागर्मी का माहौल पैदा हो गया और स्थिति नियंत्राण से बाहर हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक सुधारों के प्रयास स्थगित कर दिए गए ।

दोनों ही देशों में राजनीतिक शक्तियों के संतुलन के वैचारिक समीक्षा के परिणामों और उसकी प्रक्रियागत भिन्नताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा । हालांकि 1980 के मध्य तक चीन के अधिकांश वरिष्ठ नेता राजनीति से हट चुके थे, परन्तु अपनी औपचारिक प्रभाव के ज़रिए वे राष्ट्रीय राजनीति में अब भी सक्रिय भूमिका निभाते रहते थे । पुनर्संयोजन की नीति के लागू करने एवं नए-पुराने आर्थिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाये रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं संक्रमण की गति को नियंत्रित करने और सुधारों के दुष्परिणामों को सीमित बनाए रखने में भी वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी । इसके अलावा पूनर्मूल्यांकन की सीमा तय करने में रूढिवादी नेताओं की भी कम बडी भूमिका नहीं थी । विद्रोही स्वरों की निंदा और चार सिद्धांतों के समर्थन में वे हमेशा तत्पर रहते थे ।

इसके विपरीत, सोवियत संघ में गोर्बाचोव की सुविचारित योजना के चलते रूढिवादी ताक़तों का राजनीतिक एवम् वैचारिक प्रभाव घट गया था । वहां जब भी महत्वपूर्ण सुधारों को लेकर विवाद खड़ा होता था तो वरिष्ठ नेताओं का कोई न कोई समूह पार्टी छोड़ देता था । ग़ौरतलब है कि सोवियत मामले में विचारधारात्मक कार्य की ज़िम्मेदारी उदारवादी समर्थकों के हाथ में छोड़ दी गई थी । राष्ट्रीय विमर्श पर अपने नियंत्रण के चलते उन्होंने नीति संबंधी एजेंडा को गहराई से प्रभावित किया । रूढिवादी ताकतों की कमजोरी के चलते सोवियत सुधारों ने एक ज़्यादा रेडिकल और एकतरफ़ा चरित्र ग्रहण कर दिया । पीढ़ीगत अंतर के अलावा पार्टी के अंदर लाकतांत्रिक केंद्रवाद के तत्व अनुशासन ने भी गोर्बाचोव ने सांगठनिक फेरबदल को सफ़ल बताया । इसी के चलते रूढ़िवादी तब भी बिना हंगामा किए पार्टी से चुपचाप बाहर निकल गए । दूसरे शब्दों में, गोर्बाचोव के उक्त प्रयास इसलिए भी ज़्यादा सफल रहे क्योंकि पार्टी के अधिकारी और केंद्रीय समिति के सदस्य

असहमति के बावजूद लोकतांत्रिाक केंन्दवाद का पालन करते थे । इसके उलट चीन में वरिष्ठ नेताओं द्वारा सामान्य राजीनीतिक प्रक्रियाओं को भंग करने के बावजूद देश को अलग-थलग करने का निर्णय नहीं लिया इसलिए वहां रूढ़िवादी शक्तियां का पूर्ण उन्मूलन होने से बच गया। यह एक रूचिकर तथ्य है कि चीनी बुद्धिजीवियों के मुकाबले सोवियत बुद्धिजीवियों की शक्ति ज़्यादा व्यापक थी ।

इस संदर्भ में दोनों देशों के नेतत्व पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन की दिशा तय करने में उसकी निर्णायक भूमिका थी । सुधारों की इब्तदा के वक़्त आर्थिक विफलताओं और मानवीय त्रासदियों के लिहाज़ से दोनों देशों के अनुभव एक समान थे । मानवीय त्राासदी की दष्टि से चीन में सांस्कत्तिक क्रांति और सोवियत संघ में स्टालिन का दौर क्रांति उत्तर-काल का सबसे दर्दनाक दौर था । फिर भी एक जैसे अनुभवों और एक समान व्यवस्थाओं वाले इन देशों में पुनर्मूल्यांकन अलग-अलग दिशाओं में क्यों विकसित हुआ ? इस सवाल का जवाब चीनी और सोवियत नेतत्वों की समझ व निर्णय क्षमता के फ़र्क़ में ढूंढा जाना चाहिए । चीन के सुधार समर्थक और रूढ़िवादी नेताओं दोनों ने ही सा. क्रांति-पूर्व के अतीत को पूरी तरह नहीं नकारा, कयोंकि वह ख़ुद उनका भी अतीत था । चीनी नेतत्व का सारा जोर आर्थिक सुधारों पर था क्योंक सांस्कत्तिक क्रांति के बाद वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा गई थी । इसलिए देगं सांस्कत्तिक क्रांति के दिनों की दुर्दशा की ओर संकेत करके राजनीतिक स्थायित्व के पक्ष में माहौल बनाते थे। वे राजनीतिक स्थायित्व को आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त मानते थे । गोर्बाचोव ने समूचे अतीत का खंडन किया, क्योंकि उसके साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं था । गोर्बाचोव ने मानवीय लक्ष्यों को आर्थिक लक्ष्यों से बड़ा बताया तथा राजनीतिक सुधारों की भी वकालत की । वे समझते थे कि इन कदमों से समाजवाद को एक नया जीवन मिलेगा । गोर्बाचोव की 'नई सोच' पर किन्हीं बुनियादी सिद्धान्तों की बंदिशें नहीं थीं । हू याओवांग की तरह वह भी एक आदर्शवादी मार्क्सवादी थे । और लोकप्रिय शासन के आदर्श में ईमानदारी से यकीन करते थे । उन्हें यह गलतफहमी थी कि एक समुचित आर्थिक आधार था पार्टी के बिना भी समाजवाद राष्ट्र की मुख्य पसंद बना रहेगा ।

अध्याय - 4

समाजवादी ब्लॉक का बिखराव व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया

सोवियत संघ में पहले कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति तथा फिर स्वयं सोवियत संघ का बिखराव पिछली सदी की उन महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में भी जिसने दुनिया के स्तर पर विशेषतः 1990 के पश्चात राजनीतिक परिपेक्ष्य व शक्ति सन्तुलन को एक नई दिशा प्रदान की । राजनीतिक स्तर पर एक और सोवियत संघ के बिखराव और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरीका एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में सामने आया वही अर्थव्यवस्था के क्षेत्रा में समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था की स्वीकार्यता का पतन हुआ तथा बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में पूंजीवादी अर्थतन्त्रा का उभार हुआ। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति के पश्चात आया उसकी प्रकृति विचारधारा के स्तर पर थी। 'इतिहास के अन्त' जैसी सोच के विकसित होने में निःसन्देह पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ में विकसित हुई परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था । सामाजिक विकास के हर पहलू की दृष्टि से स्वयं को उच्चतर विचारधारा के रूप में स्थापित किए गए मार्क्सवादी दावे की विचारधारा पर दुनिया भर में प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हुए तथा उदारवाद अपनी बाज़ारू अर्थव्यवस्था व 'व्यक्ति स्वतन्त्राता' के साथ लोकतन्त्र के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है । कुल मिलाकर पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ के बिखराव ने 1990 के पश्चात सामाजिक मूल्यों में भारी परिवर्तन ला दिया और निश्चित ही यह नए मूल्य पूंजीवाद के मूल्य थे ।

4.1 चूंकि चीन की 20वीं सदी का इतिहास विशेषकर कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना के

पश्चात बहुत गहरे तक सोवियत संघ के विकास से प्रभावित रहा अतः यह समझना बहुत अहम है कि समाजवादी केन्द्र व विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ के बिखराव सरीखी राजनीतिक उथल-पुथल को चीन किस रूप में समझा और इस समझ पर आधारित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? यह अध्याय चीनी कम्यूनिस्ट पाटी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हुए इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि चीन की घरेलु राजनीतिक परिस्थिति और सोवियत संघ में हो रहे बदलावों के बीच सम्बंध की प्रकृति क्या थी? राजनीतिक उथल-पुथल के उस दौर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में आर्थिक सुधारों के भविष्य को लेकर गंभीर और उत्तोजक बहसें चलीं जो कि पूर्वी यूरोप के समाजवादी पतन, चीन में थ्येनानमेन आन्दोलन और सोवियत संघ में कम्यूनिस्ट शासन के पतन से प्रभावित थी । इन बहसों और कम्यूनिस्ट पार्टी के अन्दर राजनीतिक मतभेदों ने सोवियत संघ के प्रति उस दौर में चीन की नीति को प्रभावित किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेशी ताक़तों से अपने सम्बंधों के संदर्भ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 'दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने' की नीति का अनुसरण करती रही, और यही नीति पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ के संदर्भ में भी मानी गई। मई 1989 में गोर्वाचोव व तंग सियाओ पिंग के बीच बीजींग में हुई चीन-सोवियत उच्च स्तरीय बैठक में दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में दख़ल न देने, हस्तक्षेप न करने की समझ पर काफ़ी ज़ोर दिया गया । दोनों तरफ़ से यह सहमति भी बनी कि 'विचारधारा के स्तर पर असहमतियों को दोनों देशों के आपसी सम्बधों के बीच नहीं आने दिया जाए । 1989 और 1990 के दौरान पूर्वी यूरोप के कई कम्युनिस्ट शासकों की समाप्ति पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बार-बार 'हस्तक्षेप न करने' की नीति की घोषणा की तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की समाप्ति तथा सोवियत संघ के 1991 में बिखराव तक इसी नीति का अनुसरण किया जाता रहा । 20 अगस्त 1991 सोवियत संघ में तख़्ता पलट के

अगले दिन चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की' सोवियत संघ में हो रहे बदलाव उनका अन्दरूनी मामला है, और चीन दूसरे देशों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति का अनुसरण करेगा' [1] और यही वक्तव्य सोवियत संघ में तख़्ता पलट के असफल हो जाने पर भी दोहराया गया ।[2]

बीजींग में 1989 में लोकतंत्र के नाम पर हुए व्यापक आन्दोलन के दमन के पश्चात 'हस्तक्षेप न करने' की नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गई। हस्तक्षेप न करने की चीनी नीति ने सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में आने वाली किसी भी नयी सत्ता से अपने आर्थिक व राजनीतिक सम्बंधों को स्थायी बनाया । 1989 में पूर्वी यूरोप की 'कम्युनिस्ट सरकारों' के ख़िलाफ़ 'कम्युनिस्ट शासन विरोधी ताक़तों' की सफलता ने यह दर्शा दिया था कि सोवियत संघ की शक्ति व राज्य पर उसका नियंत्राण तथा प्रभाव घट रहा है। पूर्वी यूरोप के संदर्भ में गौर्बाचोव की नीति ने वहाँ के राजनीतिक हालातों में पवितर्न लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवादी शासन की पूर्वी यूरोप से समाप्ति पर मूलतः गौर्बाचेव की 'नई सोच' को ज़िम्मेदार माना । और गौर्बाचोव से अपनी इस समझ को ज़ाहिर करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1990 के शुरूआत में तय हुई जिंयाग जैमिन की यात्रा को रद्द कर दिया ।[3] जिंयाग जैमिन की जगह प्रधानमंत्री ली पिंग की यात्रा रखी गई जो कि चीनी राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर थी न कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च नेता 'वांग चेन' लगातार इस समझौते के ख़िलाफ़ थे, वांग

---

1. Xinhua, 20 August 1991, in *Foreign Broadcast Information Service, Daily Report*, China, (hereafter *FBIS-CHI*), 20 August 1992, p. 7.
2. *Renmin ribao* (People's Daily), 28 August 1991, in *FBIS - CHI* 28 August 1991 pp. 2-3
3. During their Sep. 1989 meeting Alexander Yokovlers has conveyed to Zhu Ling a letter from Gorbachev inviting Jiang to visit the Soviet Union "at a time convenient for him." *TASS* 11 Sep 1989, in *Foreign Broadcast Information Services, Daily Report, Soviet Union* (hirafter *FBIS - SOI*), 12 Sep 1989, p. 16.

महसूस करते थे कि सोवियत नेताओं को चीन के प्रधानमंत्री की यात्रा से नहीं नवाज़ा जाना चाहिए ।[4] यह बात तय थी कि पूर्वी यूरोप की परिस्थितियों के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएसयू व गौर्बाचेव को जिम्मेवार मान रही थी।

दिसम्बर 1989 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने पार्टी में पूर्वी यूरोप में आए बदलावों के सन्दर्भ में एक 'मसविदा' प्रकाशित किया। जिसका शीर्षक था 'सार्विक सोचो' (Unifying Thinking) इसमें पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति पर विश्लेषण करते हुए पाँच कारणों का उल्लेख किया गया था प्रथम 'कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर कम्युनिस्ट विरोधी तत्वों का आस्तित्व' व दूसरा कारण था 'पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों व कम्युनिस्ट शासन का गहरे से सोवियत संघ से प्रभावित होना ।[5] ("were heavily influenced by the Soviet Union") चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के इस विश्लेषण में जहाँ पूर्वी यूरोप की कमजोरी की आलोचना थी, वहीं यह सोवियत संघ के राजनीतिक शासन को भी रेखांकित करता है ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा 'अन्दरूनी दस्तावेज़' ली पिंग की सोवियत यात्रा से पहले निकाला गया। यह दस्तावेज़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक ओर पूर्वी यूरोप में समाजवादी पतन पर प्रतिक्रिया थी वहीं यह तत्कालीन समय में सोवियत संघ में आर्थिक व राजनीतिक सुधारों पर समझ भी थी । अप्रैल 1990 के इस दस्तावेज़ में कहा गया, "गौर्बाचेव संशोधवादी हैं जिसने पूरी तरह से मार्क्सवाद - लेनिनवाद के सिद्धान्तों से धोखा किया है, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष की अवधारणा को नकारता है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के चरित्रा को पूरी तरह से बदल दिया है। और वह पश्चिमी तरीकों पर आधारित संसदीय लोकन्त्रा को लागू कर रहा है ।[6]" ("completely betrayed

4. Kyodo, Tokyo, 9 Dec 1989, in *FBIS - CHI*, 12 Dec 1989 p. 5.
5. *Jingji Ribao* (Economic Daily), Hong Kong, 11 December 1989, in *FBIS - CHI*, 13 Dec 1989 p. 7.
6. *Zhonggon Yifen Zhonghao jimi wenjian quanwen*," ("Complete text of several important secret CCP documents") in Zhengining (Contention), No.151 (1 May 1989), pp. 8-10.

the basic principles of Marxism-Leninism. In essence, he denies class struggle in the international sphere, has changed the character of the Communist party, and implemented Western-style parliamentary democracy.")

गौर्बाचोव के सुधारों के सन्दर्भ में यह दस्तावेज़ कहता है - 'तथ्य प्रत्यक्षतः यह साबित करते हैं कि गौर्बाचोव के सुधार किसी तरह की समाजवादी व्यवस्था का रूप नहीं है बल्कि वह पूंजीवाद की तरफ़ एक आधारभूत यात्रा है, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के फरवरी 1990 प्लेनम में जो कार्यक्रम चुना गया है वह सोवियत संघ को केवल समाजवाद के साथ गद्दारी की ओर ले जाएगा न सिर्फ़ यह सोवियत संघ को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व राष्ट्रीयताओं के संकट से भागने को प्रेरित करेगा बल्कि साथ ही हर तरह के अन्तर्विरोधों को तीखा करेगा और सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप को एक लम्बे समय तक अव्यवस्था तथा अस्थायित्व में डाल देगा ।''[7]

गौर्बाचोव की 'संशोधनवादी' 'नई सोच' को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में इससे खुले रूप से संघर्ष करने पर चर्चा थी । लंग लिगची चेन युन जैसे पार्टी के बड़े नेताओं ने 'बुर्जुआ उदारीकरण'' के गौर्बाचोवी संस्करण को चीन में सुधारों के बुर्जुआ विचारधारा को पनपने ने देने हेतु पार्टी स्तर पर संघर्ष भी शुरू किया, परन्तु तंग सियाओ पिंग की राय थी-हमें इससे बचना चाहिए विचारध ाारात्मक मतभेदों को देनों देशों के सम्बधों में नहीं लाना चाहिए । परन्तु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में व चीन के अन्दर गंभीर 'वैचारिक संघर्ष' गौर्बाचोव के 'संशोधनवाद' के ख़िलाफ़ जारी हो गए । इसी दौरान तंग सियाओ पिग ने ये दिशा निर्देश जारी किए जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दुनियाभर के समाजवादी व्यवस्था में आए संकट पर एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी । ("Observe developments

7. Ibid.

soberly, maintain our position, meet challenges calmly, hide our capacities, bide our time, remain free of ambitions, and never claims leadership.")[8]

१.२ जहाँ एक ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में पूर्वी यूरोप के पतन व सोवियत संघ में लगातार बढ़ी रही अस्थिरता के लिए गौर्बाचोव व उसकी नई सोच को ज़िम्मेवार ठहराया और प्रतिकान्तिकारी के रूप में उसकी आलोचना की जा रही थी वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने सम्बंधों को विकसित करना भी शुरू किया । गौर्बाचोव की 1989 में बीजींग यात्रा से लेकर 1991 में सोवियत तख़्ता पलट की घटना तक मास्को और बीजिंग के बीच कई उच्च स्तरीय सरकारी यात्राएं व पार्टी नेताओं की प्रतिनिधि यात्राओं का सिलसिला चला । एक तरह से सोवियत संघ और चीन के बीच बढ़ते हुए सम्बन्ध तथा अपनी नीतियों में राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन महत्वपूर्ण था। हालांकि १९८९ में तंग सियाओ पिंग और गौर्बाचेव के बीच हुई बैठक में सम्बंधों को बढाने और अधिक बैठकों के आयोजन पर सहमति बनी थी।

गौर्बाचेव ने 1989 में चीन में 'लोकत्रातांत्मक आंदोलन' के दमन को 'समझ सकने' की भाषा में समर्थन दिया । परन्तु कुछ समय पश्चात गौर्बाचोव की 'समझ सकने की नीति में व्यापक परिवर्तन दिखता है, और महत्वपूर्ण रूप से अगर यह वह दौर था जिसमें सोवियत संघ के अन्दर सुधारों की प्रकृति का केन्द्र आर्थिक से राजनीतिक हो रहा था । सोवियत संघ में ख़ासकर गौर्बाचोव की यह राय बन रही कि राजनीतिक रूप से बदलाव व सुधर के बिना सोवियत संघ में कोई सुधार कार्यक्रम लागू नहीं हो सकता । एक नपी-तुली भाषा में सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत के पहले सेशन में । अगस्त को गौर्बाचोव ने कहा, "हम सबसे अधिक गंभीर समस्याओं का राजनीतिक हल निकालने

8. Shih Chun-yu, "China, Soviet Union establish new relations of good-neighbourliness, co-operation," Da gong bao, HonKong, 16 May 1991, in *FBIS-CHI*, 16 May 1991 p. 13-14.

के पक्ष में है, जो कि प्रशासन व लोगों के बीच राजनीतिक आदान-प्रदान से संभव है यह हमारा विश्वास है, यही पद्धति है जो हमने अपने लिए चुनी है, मेरा विश्वास है कि यह हमारी व बदलने वाली समझदारी व पक्ष है ।[9]"

बोरिस येल्तसिन जो कि सुधारों की तेज़ी का कट्टर समर्थक था, कड़े रूप से अपनी समझ व्यक्त की तथा 1989 की बीजिंग घटना को 'स्टालिनवादी इतिहास की वापसी' के रूप में सम्बोधित किया ।[10] मास्को न्यूज कमंटेटर बोविन ने 'ली पिंग' की अप्रैल 1990 की यात्रा से पहले सोवियत उदापंथी विचारों को सम्बोधित करते हुए कहा, "ताक़त का इस्तेमाल कभी भी लोगों को खुश नहीं रख सकतों अपने विरोधियों पर ताक़त के इस्तेमाल का चीनी उदाहरण 'दबोचने' जैसा था जो कि आसान और पारंपरिक है परन्तु हमें एक बार यह कहना चाहिए और हमेशा के लिए कि आदमी को ताक़त के ज़रिए खुश नहीं रखा जा सकता ।" ("simple and traditional..... But we should say once and for all that man cannot be made happy by force.")[11]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस दौरान नीति को दर्शाने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रैल 1990 में तंग सियाओ पिंग के पोलित ब्यूरो में दिए गए वक्तव्य से मिलता है "we must place our hopes in the Soviet people, place our faith in the broad masses of true Bolshevik party members."[12] सोवियत संघ में अगस्त 1991 के तख़्ता पलट के कुछ ही दिन पूर्व हांकांग की एक पत्रिका के हावाले से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक भाषण में कहा गया कि "we must unite with the progressive

---

9. Alexander Lukin, "The initial Soviet reaction to the events in China in 1989 and the prospects for Sino-Soviet relations," *The China Quarterly*, No. 125 (March 1991), p. 124.
10. Lincoln Kaye, Tai Ming Cheung and Julian Baum, "Bitter Medicine", *FEER*, 5 Sep 1991, p. 10.
11. Aleksandr Bovin, "China, the USSR, and Europe," Moscow News, 8 April 1990, in *FBIS - CHI*, 30 April 1990 pp. 12-13.
12. *Zhengming*, 1 May 1990, p. 5.

elements within foreign Communist parties that uphold Marxism-especially the healthy force within the Soviet army, the KGM, and the party-and these people should be invited to visit China.")[13]

अलेक्सेन्डर विअमरतयनरत के साथ अपनी बैठक के दौरान बीजिंग में ली पिंग ने सोवियत विदेश मंत्री से कहा, "the methods of buildings one's own country and the kind of the road to take are matters which could be decided by the people of that country... the Chinese side is {nevertheless} concerned about the situation in the Soviet Union, hoping that it will enjoy political stability, economic development and national unity." [14]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य ली शिमिंग मार्च 1991 में मास्को की यात्रा पर थे, उन्होंने कहा कि "we sincerely hope that the comrades of the Soviet Communist Party will surely resolve the current problems... and move the situation into a trake of steady and healthy development."[15]

अपनी मई 1991 की सोवियत संघ यात्राा के समय जिंयांग जेमिन ने गौर्बाचोव से कहा, "हम इस बारे में सजह हैं कि सोवियत संघ जटिल और परेशानी से भरे समय का अनुभव कर रहा है । यह हमारी दिली उम्मीद है कि महान सोवियत जनता जिसने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो एक यादगार क्रान्तिकारी परंपरा को अपने में संजोए है अपनी हालिया अस्थायी समस्याओं को दूर कर अपने सामाजिक सुधार और निर्माण पर अन्तिम विजय प्राप्त

---

13. Tsai Yung- mei, "Beijing's reactions."
14. Xihua, 1 April 1991, in FBIS - CHI, 2 April 1991 pp. 9-10.
15. Xihua, 27 March 1991, in FBIS - CHI, 27 March 1991 p. 2

करेगा।"[16] सोवियत उप राष्ट्रपति ग्रेनड़ी मानयेव (अगस्त तख़्ता पलट का अध्यक्ष) को जियांग जैमिन ने उम्मीद ज़ाहिर की, "सोवियत संघ समाजवादी रास्ते पर कायम रहेगा।"[17] चीन और सोवियत संघ दोनों इस समस्या से जुझ रहे हैं कि किस तरह समाजवादी व्यवस्था को स्थायी बनाए रखा जा सके साथ ही जियांग जैमिन ने कहा, और हमें पश्चिमी देशों के उन प्रयासों को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए जिनसे वो चीन और सोवियत संघ में सुधारों की आड़ लेकर अपनी पश्चिमी विचारधारा को अर्थव्यवस्था व उत्पादन के क्षेत्रा में मज़बूती के आधार पर फैलाना चाह रहा है ।"[18] इसके अलावा स्वयं तंग सियाओ पिंग का इस दौरान सीपीएसयू व गौर्बाचोव के बारे में बदले आंकलन का उदाहरण मिलता हैं तंग ने कहा, "हम उनके 'नए विचारों' को नकार नहीं सकते सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से भिन्न है वह अभी भी समाजवाद चाहते हैं। हमें गौर्बाचेव की वर्तमान समस्याओं को समझना चाहिए हम अकेले समाजवाद का झण्डा उठाकर नहीं रख सकते यह बहुत भारी है ।"[19]

यह तमाम वक्तव्य तथा कूटनीतिज्ञ यात्राओं के दौरान, पूर्वी यूरोप के पतन के बाद दी गई प्रतिक्रियाएं चीन कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के बारे में तथा सोवियत संघ में तेज़ी से हो रहे परिवर्तन के दौर में नये विश्लेषण या पार्टी के रूख में किन्हीं भी वजहों से आए परिवर्तन को रेखांकित करते हैं ।

1.3 अप्रैल 1990 में जियांग जैमिन के बदले ली पिंग की सोवियत संघ की यात्रा से एक और चीन ने सोवियत संघ से अपनी नाराज़गी (पूर्वी यूरोप के पतन व फरवरी प्लेनम के संदर्भ) ज़ाहिर की वहीं यात्रा के दौरान चीन ने कम अवधि वाले 500 मिलियन सरकारी उधार चीनी हल्के

---

16. Xihua, 17 May 1991, in *FBIS - CHI*, 21 May 1991 p. 10.
17. Tsai, Yong-mei, "*Beiging's reactions*," p. 16.
18. Shih Chun-yu, "China, Soviet Union agree to expand co-operations." Da Gong Bao, 18 May 1991, in *FBIS - CHI*, 21 May 1991 pp. 14-15.
19. Xihua, 25 April 1990, in *FBIS - CHI*, 26 April 1990 p. 18.

औद्योगिक उत्पादों की खरीदारी के लिए दिए ।[20] सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल "हलादिमी इब्बासलो" की फरवरी 1991 बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी खाद्य सामग्री ख़रीदने के लिए ।" बिलियन स्विस फ्रैक का उधार दिया ।[21] इस दौरान जब चीन में सोवियत सुधारों व गौर्बाचोव को लेकर तथा सुधारों के चलते 'बुजुर्आ उदारीकरण' पर गम्भरी विचारधारात्मक बहसे पार्टी स्तर पर जारी थी, चीन द्वारा सोवियत संघ को यह अनुदान बहुत महत्वपूर्ण अंन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में दिया गया । जनवरी 1991 में पश्चिमी देशों की समूह - 7 ने 15 बिलियन अमेरीकी डालर जो कि खाद्य और तकनीकी सहायता हेतु सोवियत संघ को मिलने थे को रद्द कर दिया गया था तथा और अनुदान हेतु होने वाली बैठक भी टाल दी गई । अमेरीका ने भी सोवियत संघ को मिलने वाली 1.5 बिलियन डालर की सहायता की बात आगे विचार हेतु बढ़ा दी, साथ ही जार्ज बुश व गौर्बाचेव के बीच होने वाली बैठक को टाल दिया गया ।

इस परिस्थिति में चीन द्वारा दिया गया अनुदान न सिर्फ़ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था अपितु उसका तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक महत्व भी समझा जा सकता है । इस तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की प्रति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह की नीति का अनुपालन कर रही थी ।

1.4 मई 1991 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियांग जेमिन अन्ततः लम्बे समय से रूकी सोवियत संघ की यात्रा पर गौर्बाचोव के निमन्त्राण पर गए । चीन और सोवियत संघ के बीच 1989 के पश्चात यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी तथा सांकेतिक रूप से इसका राजनीतिक महत्व

---

20. *Renmin Ribao*, 3 March 1991, in *FBIS - CHI*, 6 March 1991 pp. 1-2.
21. Tso Ni, "Chinese pilots to be trained in the Soviet Union," *Zhengming*, No. 163 (1 May 1991) in *FBIS CHI*, 1 May 1991 pp. 11-12.

भी अधिक था ।

1989 में पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था की समारित, तथा सोवियत संघ गौर्बाचोव द्वारा लागू किए जा रहे सुधार कार्यक्रमों के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गौर्बाचेव को 'संशोधनवादी', 'वर्गीय गद्दार' पतित मार्क्सवादी आदि कहा था। परन्तु 1989 के अन्त से गौर्बाचेव के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी का रूख़ बदलने लगा और उस पर हमले बन्द हो गए । जिंयाग जैमिन की मास्को यात्राा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस बदली राय को परिलक्षित भी करता है ।

फरवरी 1991 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग द्वारा प्रसारित एक दस्तावेज़ कहता है, "सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को भारी बहुमत ने परिस्थितियों पर नई और सामूहिक दृष्टि डाली है ।"[22] सम्भवतः सोवियत संघ में कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विरोधी ताक़तों के बीच टकराव (1990 के मध्य) में गौर्बाचेव दो शैतानों में कम शैतान व एकमात्रा यथार्थवादी संयुक्त कम्युनिस्ट ताक़तों का प्रतिनीधि रह गया था। सम्भवतः यह बदलाव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की जुलाई 1990 में हुई २८वीं कांग्रेस के विश्लेषण पर आधारित हो जिसमें येल्तसिन व उसके सहयोगीयों से स्वयं को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया था। सेमिन रिपाओं के एक लेख ने कहा, "Political stability is more necessary now than in any other period."[23] और जब येल्तसिन ने कांग्रेस के अंत में स्वयं को पार्टी से अलग कर लिया, "पार्टी कांग्रेस में आए प्रतिनिधियों ने पार्टी की एकता और मज़बूती बनाए रखने पर काफ़ी जोर दिया ।" और अन्त में निष्कर्षतः कहा कि "सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वयं को एक बड़ी टूट से बचा लिया है ।" राजनीतिक स्थायित्व की इस समय किसी भी अन्य समय से अधिक ज़रूरत है।"[24] चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आंकलन में और सोवियत

---

22. See *FBIS-CHI*, 11 July 1990, p. 4.
23. *FBIS - CHI*, 25 July 1990 pp. 10-11.
24. Yu Pin, "Will China and the USSR form another alliance?" Also, *Christian Science Monitor*, 8 March 1991.

कम्युनिस्ट पार्टी व गौर्बाचेव की तत्कालीन सोवियत परिस्थितियाँ में भूमिका के संदर्भ में परिवर्तन दिखाई देता है । यह संभव है कि यह परिवर्तन गौर्बाचेव के 'वर्गीय चरित्र' व उसके 'संशोधनवादी राजनीति' के प्रति न आकर सोवियत संघ में राजनीतिक उथल-पुथल तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदश्श्य के बारे में तत्कालीन रणनीतिक समझ के संदर्भ में आया, दो पर परिवर्तन आया यह साफ़ था । इस बारे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यह वक्तव्य इसे और साफ़ कर देता है ।

सोवियत संघ में तीन प्रभुत्वशाली समूह है । येलत्सिन के नेतस्व में रेडिकल, गौर्बाचेव के नेतस्व में सुधारवादी नरमपंथी तथा पोलोजकोव के नेतस्व में संकीर्णतावादी। चीनी कम्युनिष्ट पार्टी की सहानुभूति संकीर्णतावादी नेतस्व में है परन्तु उसकी ताक़त कमज़ोर हो चुकी है तथा 'पतन की ओर है' उसके सत्ता में वापसी के आसार बहुत कम हैं गौर्बाचेव का विकल्प येलत्सिन ही हो सकता है, इन परिस्थितियों में चीन का हित सबसे बेहतरी से गौर्बाचेव का सत्ताा में बने रहने से ही सिद्ध हो सकता है ।"[25]

इस तरह यह सम्पूर्णता एक राजनीतिक समझ से प्रेरित कदम था जिसने गौर्बाचेव से सहयोग की नीति अपनाकर येलत्सिन जैसे कम्युनिस्ट विरोधियों को दूर रखा जा सके ।

1.5 18-19 अगस्त 1991 को सोवियत संघ में गोर्बाचौव का तख़्ता पलट कर दिया गया, इस घटना के प्रति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी व मीडिया का रूख समर्थन का रहा । इस कार्यवाही से पहले ची हाओतियन मास्को में थे ची दो बार सोवियत रक्षा मंत्री याजोव से मिले ।[26] के पश्चात ची चीन लौटे और 18 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो मीटिंग में शामिल हुए और संभावित तख़्ता पलट

25. Lu Gong, "Wide gap still exists between PRC, USSR", Ming bai, 15 May 1991, in FBIS - CHI, 16 May 1991 pp. 14-15.
26. Xihua, 12 April 1991, in FBIS - CHI, 13 August 1991, p. 6.

से पार्टी को अवगत कराया ।[27]

19 अगस्त को चीनी राष्ट्रीय चैनल ने सोवियत संघ में हुई घटना का सम्पूर्ण ब्यौरा दिया ।[28] २० अगस्त को लगभग सभी केन्द्रीय अख़बारों ने इसे प्रमुख ख़बर के रूप में छापा "Gorbachev suspended from performing his presidential duties."[29] २० अगस्त को एफबीआईएस चाईना रिपोर्ट में इसे भारी कवरेज मिली, गौर्बाचेव के हटाने और बाकी ख़बरों का रूख़ समर्थन में था । येलत्सिन के वारे में कोई ख़बर नहीं दी गई । रेनमिन रीपाओं के ओवरसीज प्रकाशन ने २० अगस्त को सोवियत संघ की आपातकालीन राज्य कमेटी उसके सदस्यों व सोवियत जनता के लिए उनकी अपील को प्रमुखता से छापा ।[30] उसी रोज बीजिंग रेडियो के हवाले से खबर प्रसारित की गई जिसके अनुसार, "पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ में आर्थिक व सामाजिक समस्याओं, जीवन स्तर के पतन, मुद्रा स्फीति और बेरोज़गारी की बाढ़ की वजह राजनीतिक जीवन का उदारीकरण आर्थिक जीवन में बदलाव तथा बहुदलीय व्यवस्था की संस्था का आस्तित्व में आना थी ।" ("liberalization of political life, changes in economic life, and the institution of multi-party systems.")[31]

ज्यों ही तख़्ता पलट कुछ दिन में असफल हुआ चीनी मीडिया व अन्य प्रकाशनों ने सोवियत संघ के बारे में ख़बरों का प्रसारण कम हो गया । गौर्बाचेव की वापसी महत्वपूर्ण ख़बर को मात्रा २ वाक्यों में दिया गया 'गौर्बाचेव वापिस आ गए हैं और उन्होंने परिस्थितियों के नियंत्रण का दावा किया है ।[32] रेनमिन रिपाओ एकमात्र अख़बार था जिसने गोर्वाचौव की सत्ता में वापसी की ख़बर छपी

---

27. Ibid.
28. *SCMP*, 23 August 1991, in *FBIS - CHI*, 23 August 1991 p. 7.
29. Yeh Lu-ching, "CPC holds up Communism on its own."
30. *Renmin Ribao*, 20 August 1991, in *FBIS - CHI*, 20 August 1991 pp. 11-12.
31. *Beijing Radio*, 21 August 1991 in *FBIS - CHI*, 22 August 1991 pp. 1-2.
32. *FBIS - CHI*, 22 August 1991 p. 6.

I("restored his links with the nations which had been cut for a certain time.")[33]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19 अगस्त को पोलित ब्यूरो मीटिंग हुई । तंग सियाओं पिंग ने बैठक में कहा, "चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ग़ौर से नज़र रखनी चाहिए कि क्या घटित हो रहा है और खुले रूप से अपना पक्ष तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक स्थिति काबू में न आ जाएं, 'सोवियत तख़्ता पलट अच्छी चीज है ।"but we must not be visibly pleased but only delighted at the bottom of our hearts."[34] तंग ने कहा, "सार्वजनिक रूप से पार्टी को इस नीति पर टिकना चाहिए कि किसी देश के अंदरूनी मामले उसे देश की जनता की चिन्ता का विषय हैं ।" साथ ही यह भी कहा कि "चीन सोवियत संघ की स्थिति को ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहता बल्कि सोवियत संघ को मजबूत ताक़तवर और स्थायी रूप में देखना चाहता है जहाँ लोग जीवन का सही आनन्द उठा सकें ।"[35]

19 अगस्त की पोलित ब्यूरो मीटिंग के पश्चात् तीन सूत्री दिशा-निर्देश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निचले स्तरों पर भेजे गए । प्रथम "गौर्बाचेव का पतन एक अच्छी चीज है ।" दूसरा "सोवियत आपातकालीन राज्य कमेटी को मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि इसे सच्चे मार्क्सवादियों ने बनाया है ।" तीसरा सोवियत संघ और चीन के बीच सम्बंधों को मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि सोवियत यूनियन समाजवादी कैम्प में वापस आ गया है ।" यह निर्देश वापस मंगा लिए गए जब तख़्ता पलट असफल हो गया ।"[36]

---

33. *FBIS - CHI*, 22 August 1991 p. 5.
34. Tsai Yung-mei, "*Beiging's reactions*."
35. *FBIS-CHI*, 9 Sep. 1991, p. 10
36. Yeh Lu-ching, "CPC holds up Communism on its own." Tsai Yung-mei, "*Beiging's Reactions*."

पोलित ब्यूरो की एक अन्य बैठक में २० अगस्त को जियांग जैमिन के ज़रिए तंग ने नपा-तुला दष्टिकोण अपनाने को कहा, "चीन को अमेरीका विरोधी किसी भी मुहिम में सोवियत संघ के साथ गठजोड़ नहीं बनाना चाहिए ।"[37] साथ ही यह निर्देश भी पार्टी को दिए गए कि "सोवियत संघ की स्थिति बहुत अस्थायी दौर से गुज़र रही है और यह ज़रूरी है कि हम किसी सार्वजनिक बहस में शामिल न हों तथा पार्टी के दिशा निर्देश में चलें ।"

तख़्ता पलट के असफल होते ही चीन में सोवियत संघ के राजदूत एन एन सोलोवयेव ने चीनी विदेश मंत्री क्वीन-क्वीचन को गौर्बाचेव की तरफ़ से तीन बातें कहीं, "गौर्बाचेव स्वस्थ स्थिति में हैं, सोवियत संघ संवैधानिक शासन को दुबारा स्थापित करेगा और सोवियत संघ जल्द ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थायित्व को स्थापित कर लेगा ।"[38] सम्भवतः यह चीन को सचेत करने के लिए भी हो कि वह गौर्बाचेव विरोधी तख़्ता पलट का समर्थन न करे । चीनी विदेश मंत्री ने कहा, "We respect the choice of the Soviet people made, and we believe that with the resumption by President Gorbachev of his duties, the good-neighbourly and friendly relations between China and the Soviet Union will continue to develop on the basis of the principles set forth in the 1989 and 1991 Sino-soviet joint communiqués."[39]

गौर्बाचेव के ख़िलाफ़ तख़्ता पलट की असफलता के पश्चात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आपातकालीन पोलित ब्यूरो मीटिंग निष्कर्ष पर पहुंचती है कि "गौर्बाचेव की सत्ता में वापसी एक प्रति क्रान्तिकारी पुनः स्थापना है ।" जो कि "शान्तिपूर्ण विकास का नतीजा है ।" जिसकी "रचना पश्चिमी देशों ने की" ओर नेतत्व अमेरिका ने दिया" गौर्बाचेव जनता का विश्वास खो चुका है । उसके

37. *FBIS-CHI*, 9 Sep. 1991, p. 10.
38. *FBIS-HI*, 23 August 1991, pp. 5-6.
39. *Beijing Radio*, 21 August 1991, in *FBIS-CHI*, 22 August 1991, p. 7.

सुधारों ने पिछले 6 सालों में सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को समाप्ति पर पहुँचा दिया है और देश का बिखराव इसका नतीजा है, उसकी 'नई सोच' वर्ग संघर्ष की मौजूदगी को नकार कर पूंजीवाद को पुनर्स्थापित किया है और विचारधारात्मक कन्फ्यूज़न को सोवियत यूनियन ने ऊपरी नेतत्व तक पैदा कर दिया है और प्रतिक्रियावादी व समाजवाद विरोधी ताक़तों को बढ़ावा दिया है। आपातकालीन राज्य कमेटी को लोगों ने समर्थन दिया यह असफल हो गई अपनी कमजोरियों तथा अमेरीका, फ्रांस और जापान के हस्तक्षेप के कारण ।"[40] चीनी कम्युनिष्ट पार्टी के अनुसार तख़्ता पलट की असफलता के कई कारण थे, "आपातकालीन राज्य कमेटी का लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं पर अधिक विश्वास कानूनन कार्य करना, गौर्बाचेव वयेल्लसिन को व अन्य प्रतिक्रान्तिकारियों के ख़िलाफ़ सही तरीक़ों का इस्तेमाल न करना, उनका बाहरी दुनिया से सम्बंध समाप्त न कर पाना, सेना पर सही तरीक़े से नियन्त्राण क़ायम न हो पाना, चीन ने आपातकालीन राज्य कमेटी को समर्थन दिया क्योंकि चीन चाहता था कि सोवियत संघ अमेरिका का प्रतिरोध करने वाली मजबूत ताक़त बना रहा।"[41] 31 अगस्त 1991 को समाचार पत्रों के सम्पादकों को सम्बोधित करते हुए "गाओ ती" ने अपने शब्दों में केन्द्रीय समिति के सोवियत तख़्ता पलट की घटना के बारे में राय रखते हुए कहा,

The 19 August [Incident]... was so very much like our own 4 june, and yet the result was completely the opposite. This was because we resolutely suppressed [the counter-revolutionary forces] without the slightest mercy, whereas the Soviet Eight was unable to implement the dictatorship of the proletariat. In the end they not only suffered defeat, but also ruin and disgrace."[The August coup] failed because the people's thought had been thrown into confusion

40. He p-shish, "CCP issues successive emergency circulars." This report is corroborated by the talk by Gao Di cited in the following note.

41- Talk by Gao Di, Documentation, *The China Quartely*, No. 130 (June 1992) pp. 482-491.

by Gorbachev's new thinkings. The most significant aspect [of this] is that the good of mankind as a whole has replaced the [doctrine of] class struggle. This is purely and simply the viewpoint of democratic socialism, and in denies [true] socialism.... The test of the true Marxist is whether or not the acknowledges the dictatorship of the proletariat. Overthrowing the reactionary regime which Gorbachev and Yeltsin represented would have been an act of revolution, a seizure of power. Revolution is merciless; if you do not overthrow him, he will overthrow you. There is no room for compromise is this, or for so-called human sympathy. Revolution is violence; once the seizure had begun, they should have arrested Gorbachev and Yeltsin. They could never have achieved their ends by working within the framework of the constitution and the law."[42]

यह वक्तव्य स्वयं में सोवियत संघ के जहाँ एक ओर तख़्ता पलट के कारण के रूप में राजनीतिक नियन्त्राण व राज्य का प्रभाव में न होना मानता है वहीं यह चीन के पक्ष को राजनीतिक रूप से सही ठहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया को एक ठोस आधार भी प्रदान करता है।

सोवियत तख़्ता पलट की असफलता पर गाओती के अनुसार केन्द्रीय समिति की समझ यह थी, "अगस्त तख़्ता पलट असफल हुआ क्योंकि लोगों की सोच व उनके विचारों को गौर्बाचेव की 'नई सोच' ने उलझन में फेंक दिया था ।" आगे विस्तश्त में उनका आंकलन था कि "मानवतावादी समाजवाद' ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को बदल दिया ।" और सही समाजवाद को नकार दियों एक सच्चे मार्क्सवादी की परीक्षा इस बात से तय होती है कि वह सर्वहारा की तानाशाही को मानता है या नहीं । गौर्बाचेव व येल्तसिन की प्रतिक्रियावादी सत्ता को उखाड़ फैंकना क्रांतिकारी कार्य हो सकता

---

42. *Ibid*

थों उन्हें गौर्बाचेव व येल्तसिन को बन्दी बना लेना चाहिए था, संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपने उद्देश्यों को वह पूरा नहीं कर सकते थे ।"[43]

अगस्त तख़्ता पलट होने के पश्चात पोलित ब्यूरो ने यह निर्णय लिया कि चीन व सोवियत संघ के बीच दख़ल न देने की नीति पर आधारित होंगे ।"[44]

तख़्ता पलट के असफल पश्चात सोवियत संघ का बिखराव शुरू हुआ चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए 7 सितम्बर 1991 को 'इस्ओनिया, लाथविया, लिथुआनिया की आज़ादी को मान्यता प्रदान कर दी । 12 दिसम्बर को सी आई एस के गठन के बाद चीनी विदेश मंत्राालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनाने को तैयार है, सोवियत संघ व सोवियत गणराज्य दोनों से। २७ दिसम्बर को गौर्बाचेव के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने के अगले दिन सर्वोच्च सोवियत और सोवियत संघ भंग हो गए ।

1.7 सोवियत संघ के बिखराव की पृष्ठीय भूमि व पूर्वी यूरोप के पतन में गौर्बाचेव के आने से गुणात्मक परिवर्तन ज़रूर आया । गौर्बाचेव की समाजवाद के बारे में समझ व उसकी परिणति के रूप में राजनीतिक वह आर्थिक सुधारों के पतन की प्रक्रिया को बहुत तेज़ किया। विशेषतः सोवियत संघ व गौर्बाचेव के बारे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की समझ 1985 से सोवियत संघ के बिखराव तक कई बार बदली यह संभव है यह बदलाव ''टेक्टिकल'' हो परन्तु यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी गौर्बाचोव पर उन दबावों को भी रेखांकित करता है जिसके प्रभाव में यह राय बदलती रही । इस प्रभाव की पुष्टि

---

43. Tsai Yung-mei, "*Beiging's reactions*."
44. Deng Xiaoping ti Zhonggong suanming" ("Deng Xiaoping sees the future for the CCP"). *Zhengming*, 151 (1 May 1990), pp 6-7.

अप्रैल 1990 में तंग सियाओं पिंग द्वारा दिया गया वक्तव्य करता है, "सभी को यह साफ़ हो जाना चाहिए कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अधीन, सभी दुश्मन चीन पर सावधान हो गए है, वह हर तरह से हम पर दबाव डालने व समस्या पैदा करने के लिए तैयार हैं। अगले तीन में से पांच साल हमारी पार्टी व देश के लिए गंभीर रूप से परेशानी वाले हैं ।"[44]

पोलित ब्यूरो के एक निर्देश के मुताबिक सोवियत संघ में विजयी होने के पश्चात पश्चिमी देश चीन में 'शान्तिपूर्ण विकास' के नाम पर समाजवाद को उखाड़ फेंकने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे[45] मोटे तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यह आंकलन उनकी प्रतिक्रिया में दिखता कि सोवियत संघ की स्थिति ख़राब होने का असर चीन को यह संभावना भी थी कि सोवियत संघ के पतन के पश्चात रूस पश्चिमी देशों के गठजोड़ बनाने की ओर अग्रसर होगा । 1991 में इराक पर हमले के अमेरिकी निर्णय पर रूस की सहमति इसका उदाहरण थी ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारात्मक सिद्धान्त आयोग की तरफ़ से अगस्त तख़्ता पलट के असफल होने के एक महीने पश्चात प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार, "सात औद्योगिक जी-7 देशों में रूस के शामिल होने के पश्चात 'पश्चिमी हेजामनी' उदय हो रही हैं रणनीतिक सन्तुलन पश्चिमी की ओर होने से चीन के पास कोई कार्ड खेलने के लिए नहीं बचा है।"[46] यह बहुत साफ़ था कि सोवियत संघ के बिखराव का दूरगामी राजनीतिक असर पड़ेगा । दुनिया के नए शक्ति सन्तुलन को समझते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 14 वीं कांग्रेस के दौरान तंग सियाओं पिंग ने कहा, "हमें बार-बार शान्तिपूर्ण विकास के पिश्चमी हमले को नहीं रटना चाहिए हमें अपने सुधारों

45. He Po-shih, "*CCP issues successive emergency circulars.*"
46. "Sulian jubian zhihou Zhongguo de xianshi yingsui yu zhanluc xuanze" ("The realities to be faced in China in the wake of the dramatic changes in the USSR and strategic choices☺. *Zhonggou qingnlan qingnian bao* (China Youth Daily). Beijing, 9 Sep 1991."

हेतु अमेरीका की मदद की ज़रूरत है ।" यहाँ तक कि मानवअधिकार के मुद्दों पर हमें अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए ।[47]

इस प्रकार सोवियत संघ के पतन से पैदा हुई राजनीतिक स्थिति का यह तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक तार्किक लक्षण था ।

1.8 पूर्वी यूरोप के पतन व सोवियत संघ के बिखराव की प्रक्रिया के दौरान, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर विभिन्न प्रतिक्रिया से अलग थी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने खुले रूप से व्यक्त की । यह प्रतिक्रियाएं मूलतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत संघ व चीन में हो रहे सुधारों की प्रकृति व उसके बारे में राजनीतिक समझ में सम्बधित थी जो कि 1989 में गंभीर बहस का हिस्सा बनी । 14 वीं पार्टी कांग्रेस तक'' बुर्जुआ उदारीकरण शान्तिपूर्ण विकास, पूंजीवादी पुनर्स्थापना व सुधारों की पूंजीवादी प्रकृति से सम्बधित यह तमाम बहसें कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेदों को दर्शाती है। विशेषतः 1989 में पूर्वी यूरोप के पतन तियेनामेन की घटना व सोवियत संघ के बिखराव को पार्टी के अन्दर पश्चिमी देशों की बुर्जुआ उदारीकरण के ज़रिए पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की कोशिश के रूप में भी देखा जाने लगा था । हालांकि 14 वीं कांग्रेस के अन्त में निष्कर्षतः इन सब समझों को अस्वीकार्य कर दिया गया था परन्तु पार्टी के तमाम विकसित होती परिस्थितियों ने विचारधारात्मक सवाल खड़े किए और सुधारों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए पार्टी के वरिष्ट नेता तंग लिगची व सहयोगियों ने खुलेपन की नीति को आगे बढ़ाने पर विरोध किया, उनका तर्क था कि वह शान्तिपूर्ण विकास के ज़रिए पूंजीवाद की पुनर्स्थापना को विकसित कर रहा हैं इस ख़तरे को उनके अनुसार पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ के अनुभव ने सिद्ध भी किया है । उनके अनुसार ''बुर्जुआ उदारीकरण में जो अन्दरूनी व विदेशी

47. FBIS-China - 22 July 1991.

ताक़तें व्यवस्त हैं इस नए मध्यम वर्ग पर उनकी काफ़ी उम्मीदें हैं ।'' वर्तमान में बुर्जुआजी के नए तत्व सामने आ रहे हैं और एक मध्यम वर्ग आकार ग्रहण कर रहा है'' आगे वह कहते हैं कि ''बुर्जुआ उदारीकरण की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ वर्ग संघर्ष ही सही जवाब हो सकता है ।'' ''चेयरमैन माओं ने इसे सही पहचाना था'' और पढ़ाया था कि ''बुर्जुआजी व सर्व हारा के बीच आख़री जीत लम्बे समय तक हमारे देश में अनसुलझी रहेगी। विचारधारा के स्तर पर जीत को एक लम्बा सफ़र तय करना पड़ेगा'' तंग लिगची के अनुसार, ''1978 के बाद से बुर्जुआ उदारीकरण की शुरूआत और पूर्वी यूरोप के महान बदलावों ने चेयरमैन माओं की वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को पुष्ट किया है ।'' आगे वह माओं के सांस्कृतिक क्रान्ति के सिद्धान्त को आधारभूत रूप से सही मानते हुए उस पर पुनर्विचार की बात करता था साथ ही माओ द्वारा पूंजीवादी पथगामियां पर बमबारी को सही ठहराता था ।

तंग लिगची व उसके समर्थकों के अनुसार यूरोप व सोवियत संघ में कम्यूनिष्ट शासन की असफलता अन्तर्राष्ट्रीय बुर्जुआजी की ख़तरनाम रणनीति को दर्शाता है, चीन में समाजवाद को बचाने हेतु तंग लिंगजी का कहना था कि ''चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरह के 'बुर्जुआ उदारीकरण' का विरोध करना चाहिए ।''[48]

तंग सियाओ पिंग की असहमति थी, उनके अनुसार चीन में हुए 1989 की घटना का मुख्य कारण सम्राज्यवादी शन्तिपूर्ण विकास या बुर्जुआ उदारीकरण नहीं था, बल्कि ग़रीबी व चीनी अर्थव्यवस्था का अर्धविकसित होना था। सोवियत कम्यूनिज़्म व सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पतन से जो मुख्य सीख तंग सियाओ पिंग ने निकाली उसके अनुसार, ''सिर्फ़ लगातार सुधार और खुलेपन की नीति ही चीन में कम्युनिज़्म को बचा सकती है ।''

---

48. See FBIS-CHI, 21 Oct. 1992, Supplement.

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 14 वीं कांग्रेस की अन्तिम रिपोर्ट तंग लिंगगी के वक्तव्यों को ख़ारीज कर देती है। इस रिपोर्ट में 1978 व 1981 के पार्टी इतिहास से सम्बधित प्रस्तावों का सही ठहराया गया जिसमें महान सांस्कृतिक क्रान्ति को नकारना तथा ''लगातार क्रान्ति'' को सर्वहारा की तानाशाही में जारी रखने के के सिद्धान्त को पुनः नकारती है । यह रिपोर्ट समाजवाद निर्माण के प्रमुख कार्यभार के संदर्भ में आर्थिक विकास को प्राथमिकता प्रदान करती है व समाजवादी बाजार व्यवस्था के विकास पर जोर देती है । वर्ग संघर्ष के संदर्भ में कहा गया कि यह आर्थिक निर्माण के केन्द्रीय कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया ।''

समाजवादी केन्द्र के रूप पूर्वी यूरोप विशेषतः सोवियत संघ के बिखराव पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया के हवाले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष व साथ ही कुछ सवाल भी निष्कर्ष की ऐवज में सामने आते हैं ।

विघटन की प्रक्रिया पर प्रतिक्रियाएं यह बताती हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत संघ को बिखराव से बचाने व कम्युनिस्ट शासन को बनाए रखने हेतु सतत नीति रही । इसका स्पष्ट उदाहरण हमें विपरित परिस्थितियां में सोवियत संघ की आर्थिक मदद, दो तरफा राजनीतिक आदान-प्रदान सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप न करने की नीति से अलग अन्दरूनी तौर पर उसके पक्ष में खड़े होना और विभिन्न बैठकों के दौरान सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी व शासन के मजबूत होने की इच्छा से सम्बन्धित वक्तव्य यह बताते हैं कि चीन सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के बने रहने के पक्ष में था । सोवियत संघ में गोर्वाचौव के विरूद्ध तख़्ता पलट को समर्थन व्यक्त

करना, इसका एक और स्पष्ट उदाहरण है ।

दूसरा यह कहा जा सकता है कि सोवियत कम्युनिस्ट शासन के बने रहने की चीनी नीति महज मार्क्सवादी विचारधारा के विश्लेषण पर आधारित न होकर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय, घरेलू व राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित भी रही । उदाहरण स्वरूप 1989 से पहले के समय तक जब पूर्वी यूरोप घंटित नहीं हुआ था, अमरिका एक ख़तरे के रूप में उतना सामने नहीं दिखता था परंतु यूरोप के पतन व सोवियत संघ में लगातार कम्यूनिस्ट शासन के ह्रास ने चीन में भी कम्युनिस्ट शासन को बचाए रखने का सवाल खड़ा हुआ, सोवियत संघ के बिखराव के बाद निश्चित ही चीनी समाजवाद की समाप्ति पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों की नीति थी, चीन की कम्यूनिस्ट शासन की स्थिरता हेतू सोवियत संघ का बने रहना व मजबूत बना रहना बहुत ज़रूरी था और यही कम्युनिस्ट पार्टी के कई वक्तव्य व बुर्जुआ उदारीकरण पर पार्टी में मतभेद के दौरान दिखता था। सोवियत तख़्ता पलट को तुरंत समर्थन देना चीन की इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी । घरेलू राजनीति ने भी चीन की सोवियत संघ को बने रहने की प्रतिक्रिया को आधार दिया । ताईवान, तिब्बत, सिंगचियांग आदि इलाकों में सोवियत बिखराव चीन के लिए नई समस्या पैदा कर सकत था । राजनीतिक रूप से चीन की नीति, समाजवाद की स्वीकार्यता के सवाल से जुड़ी थी। चीन को यह अहसास था कि सोवियत संघ का बिखराव पूर्व यूरोप में हुए घटनाक्रम से प्रभावित था । पूर्वी यूरोप के बाद सोवियत संघ की समाप्ति, समाजवादी अर्थव्यवस्था व कम्युनिस्ट शासन की लोक स्वीकार्यता को निसन्देह कम बनाती ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया में जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें राजनीतिक स्थायित्व बने रहना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकार्यता तथा पश्चिमी आधारित बहुदलीय लोकतंत्र की बुर्जुआ

विचारधारा प्रमुखतः दिखती है । सोवियत संघ वह पूर्वी यूरोप के बिखराव की प्रतिक्रिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की यह समझ अपने देश के अनुभवों से प्रेरित अधिक थे। यह बात और स्पष्ट इस तथ्य से होती है कि आर्थिक सुधारों के बारे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रूस इन देशों के प्रति डाहाँ एक और समार्थन का या नहीं बिखराव की वजहों में आर्थिक सुधारों की कमजोरी एक महत्वपूर्ण वजह नहीं थी । कुल मिलाकर चीनी प्रतिक्रिया का केन्द्रिय बिन्दु राजनीतिक शासन से अधिक प्रभावित था । दूसरे शब्दों में यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चार अधारभूत सिद्धान्तों व ग्लान्तोन्स्त के बीच विरोधाभासी समझ का प्रतिबिंब था ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया से जो सवाल खड़ा होता है वह चीनी पार्टी की समझदारी व उसकी सैद्धातिक समझ के बारे में संकेत देता है। उदाहरण बुर्जुआ उदारीकरण का सोवियत संघ में प्रमुख आधार क्या था ? क्या यह संभव है कि महज राजनीतिक सुधारों की पश्चिमी पद्धति के अपनाने से ही सोवियत संघ में बुर्जुआ विचारधारा को अस्तित्व मिला या चीन के संदर्भ में जिस 1989 के 'प्रति कान्तिकारी' के उभार को तंग सियाओ पिंग में बुजुर्आ उदारीकरण व चार सिद्धान्तों के बीच संघर्ष के रूप में परिभाषित किया था वह चीन में कहाँ पैदा हो रहा था । यह मानने के बाद कि बुर्जुआजी के नए तत्व समाजवादी समाज में विकसित हो रहे हैं उनके खिलाफ़ समाजवादी चेतना को विकसित करने का क्या तरीका होना चाहिए इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती ।

दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया में बुर्जुआ उदारीकरण के विकसित होने की एकतरफा समझ स्वय चीन के आर्थिक सुधारों की स्वीकार्यता को स्थापित करने की कोशिश में समझी जा सकती है । आर्थिक सुधारों को बुर्जुआ उदारीकरण की वजह के रूप में रेखांकित करना चीन के आर्थिक सुधारों की समझ व प्रकृति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता

है कि सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के पतन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि उस दौर में विचारधारा से अधिक विभिन्न तहर के दबाव सम्बधों को अधिक प्रभावित कर रहे थे और यह दबाव स्वयं उस दौर में विचारधारा पर पूंजीवाद के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं । साथ ही चीनी प्रतिक्रिया 90 के दशक में मार्क्सवादी विचारधारा में प्रतिकूल परिस्थितियों में आए राजनीतिक बदलावों को भी स्पष्ट रेखांकित करती है ।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में शुरू में ही यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य महज कुछ महत्तवपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन करते हुए सवालों को रेखांकित करना है। अतः निष्कर्षतः कुछ महत्तवपूर्ण टिप्पणी करना न तो आवश्यक है न संभव, परंतु निष्कर्ष की एवज में अध्ययन से उपजे सवालों को रेखांकित करना महत्तवपूर्ण होगा। इन महत्तवपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करने से पहले यह दर्ज करना महत्तवपूर्ण होगा कि दरअसल मुद्दों व समय-काल से यह अध्ययन सम्बन्धित है वह समय मोटे तौर पर समाजवाद के एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के रूप में अन्तिम बिखराव का समय था तथा यह वह दौर भी था जब बैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवादी अमेरिका विश्व-व्यवस्था नए सिरे से दुनिया भर को प्रभावित करने लगी थी। सोवियत संघ के बिखराव, पूर्वी यूरोप के पतन व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की समूचे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया को भी इसी फ्रेमवर्क में देखा जाना चाहिए। चूँकि संकट महज विखंडित समाजवादी व्यवस्था के लिए नहीं था, अपितु यह उन देशों के लिए भी था, जो अभी तक एक समाजवादी व्यवस्था के रूप में कार्यरत है।

दूसरा यह भी साफ होना चाहिए कि जिस समाजवादी विखराव या व्यवस्था की पूरे अध्ययन में बात हो रही है वह देश के हिसाब से विभिन्न भी है। साथ ही नोट करने वाली महत्तवपूर्ण बात यह भी है कि जिस समाजवाद की हम चर्चा कर रहे हैं वह समाजवाद दुनिया भर में अपने निर्माण काल के बाद कई रूपों में विकसित हुआ है, अवधारणात्मक व व्यवस्थात्मक रूप से उसकी सार्वभौमिक प्रकृति नहीं रही। ऐसा नहीं है कि समाजवाद कहते ही सार्वभौमिकता का बोध या आभास होने लगे। अतः इस बहस की गुंजाईश प्रस्तुत अध्ययन में नहीं है कि क्या जिसे हम समाजवाद कह रहे हैं वह समाजवाद वाकई में था कि नहीं, जिस

संघ के बिखराव की हम चर्चा कर रहे हैं वह कब तक समाजवादी था तथा कब से वह संशोधनवादी समाजवाद में परिवर्तित हुआ आदि। यहाँ यह मानकर चलना होगा कि व्यवस्था, राजनीति व अर्थव्यवस्था के आधार पर अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट शासनों की प्रकृति एक सी थी। और यही हम समाजवादी देशों के एक ------के बिखराव पर एक अन्य देश की कम्युनिष्ट पार्टी की प्रतिक्रियाओं व व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवादी ब्लाक के विस्तार पर प्रतिक्रिया मूलतः दो बिन्दुओं पर महत्तवपूर्ण है। प्रथम बिखराव के कारणों को वह किस तरह परिभाषित करती है, दूसरा बिखराव के प्रभावस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में वह कैसे व्यवहार करती हैं।

प्रथम मुद्दे के कई पहलू हैं। एक बिखरावपूर्व स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पाटी का आकलन तथा बिखराव के पश्चात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की समझ। दूसरे बिन्दु में महत्तवपूर्ण रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश के अन्दर व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से कैसे पेश आती है। अन्ततः इन परिस्थितियों के दौरान दिखने वाले अन्तर्विरोध।

जैसा कि विदित है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी १९८९ के पश्चात् से दूसरे देशों के अन्दरूरी मामलों में दखन न देने की नीति का अनुसरण करने लगी। विशेषतः १९८९ की तेगसियाओ गोर्वाचौव के बीच उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय भी लिया गया। जाहिर है यह नीति नयेनआनमेन की उस घटना के बाद अधिक मुखर हुई जहाँ से पश्चिमी देशों ने चीन पर प्रतिबन्ध लगा दिए तथा मानवाधिकार हनन पर व्यापक आलोचना की। इस घटना के बाद से चीन पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाब बहुत अधिक था, यह महत्तवपूर्ण इस वजह से भी था चूंकि चीन के आर्थिक सुधारों व खुले द्वार की नीति को इससे नुकसान था, अतः एक तरफ सम्प्रभुता का मसला था, दूसरी तरफ देश के आर्थिक विकास का। बावजूद चीन पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के इस दबाव के चीन सोवियत संघ के विघटन को रोकने का समर्थक था,

क्योंकि सोवियत संघ के पश्चात् स्वाभाविक रूप से विश्व --------व्यवस्था का चरित्र बदल जाना था जो चीन के पक्ष में कम से कम नहीं था। यहां साथ ही यह भी महत्तवपूर्ण है कि घरेलू तौर पर चीन सोवियत संघ के आर्थिक सुधारों का पक्षधर होते हुए, राजनीतिक सुधारों का घोर विरोधी था। कम्युनिस्ट पार्टी के संविधानिक एकाधिकार की समाप्ति पर गोर्बाचौव की "नई सोच" व 'बुर्जुआ जनतन्त्र' की समझदारी की आलोचना की गई।

यहां दो तरह की धारा दिखती है, प्रथम जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप न करने की नीति पर बने रहना। पर साथ ही सोवियत संघ के सम्भावित बिखराव से बचाने की कोशिश वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अन्दर, गौर्बाचोब की आलोचना मुखर थी।

दरअसल जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक तरफ, सोवियत संघ के बिखराव का भय था वहीं दूसरी तरफ, देश के अन्दर एक कम्युनिस्ट शासन की वैधता, स्वीकार्यता को बनाए रखने का सवाल भी था। इसलिए सम्भवतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं को पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ का अगला संस्करण बनने से रोकना चाहती थी, वहीं वह सोवियत संघ के संभावित बिखराव के पश्चात् परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, इससे भी जूझ रही थी। इस मायने में संकट महज विखंडित होते हुए, समाजवादी देशा का या अपितु संकट गहरे रूप में चीन जैसे देशों के लिए भी था। एक तरह से कहें तो चीन सोवियत संघ के बिंखराव से इसलिए चिंतित नहीं था कि समाजवाद पतन की ओर अग्रसर है बल्कि वह अपने देश में १९८९ के दूसरे संस्करण से भी चिंतित था। सोवियत संघ में तेजी से हो रहे बदलव इस बात की ओर पुष्टि करते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया में यह मुद्दा कितना महत्तवपूर्ण था। सोवियत संघ में गोर्वाचौव रेडिकल विरोधी येल्तसिन को अपार समर्थन मिलना चीन के लिए चिंता का विषय बन गया। इस स्थिति में चीन की तरफ से डियांग डौमिन गोर्बाचौव से बैठक करने गए, गोर्बाचौव से, चीनी कम्युनिष्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का मिलना सांकेतिक रूप से महत्तवपूर्ण था। इससे वह गोर्बाचौब को CPSU के नेता के रूप में मान्यता दे रहे थे।

चूकि येल्तसिन राजनीतिक सुधारों का कट् टर समर्थक था, तथा कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता समाप्त करने का पक्षधर था अतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी गोर्बाचौव को महत्तव प्रदान करने लगी। परन्तु अगस्त तख्तापलट होते ही तुरन्तु चीनी कमयुनिस्ट पार्टी ने, आपातकालीन राज्य कमेटी को मान्यता दे दी। साथ ही उन्हें सच्चा मार्क्सवादी बताकर उनके समर्थन की घोषणा कर दी। युद्ध की घटना के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस वक्तव्य का आना कि सोवियत संघ समाजवादी कैम्प में वापस आ गया है, इस बात को स्पष्ट करता है कि चीनी पार्टी गोर्वाचौव को लेकर बहुत दोतरफा नीति अपना रही थी। अगस्त तख्तापलट के असफल होते ही पार्टी अपनी पुरानी लाईन पर वापस आइ तथा गोर्वाचौव से अच्छे सम्बंधों की बात दोहराई। यह तथ्य साफ तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर सोवियत विखंडन के संभावित खतरों के प्रभाव को स्पष्ट करता है।

महत्तवपूर्ण रूप से दिसम्बर में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् चीन उन प्रथम देशों में से था जिन्होंने नए राष्ट्रों को मान्यता प्रदान की, साथ ही यह शर्त रखी की वह हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करे। परन्तु इस पूरे घटनाक्रम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए महत्तवपूर्ण क्या था? या सोवियत संघ का विघटन की संभावना का ---- क्या चीन के विघटन के संभावना हो सकने वाली -------थी। यहां तथ्य रूप से एक महत्तवपूर्ण मुद्दा है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रियाओं में मिलता है- संभावित अमेरिकी विश्व-व्यवस्था से चीनी राष्ट्र के हितों को खतरा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया में यह युग बहुत अहम था कि सोवियत विघटन पश्चात् संभावित विश्व-व्यवस्था में चीन के खुले द्वार की नीति, आर्थिक सुधारों को सुचारु रूप से चलाने में खुश्किल होगी, इसका स्पष्ट उदाहरण १९८९ के पश्चात् मानवाधिकार मुद्दे पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाजवाद का पतन महत्तवपूर्ण उतना नहीं था जितना सोवियत संघ का बिखराव और यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि समाजवाद के पतन व सोवियत संघ का विघटन के मुद्दों में मूलभूत अन्तर है। अतः यह सम्भावना तथ्यात्मक रूप से प्रबल है कि

सोवियत संघ के बचाव की मुद्दा में अन्तर्निहित हित चीनी राष्ट्र के विकास के हित से बहुत गहरे सम्बन्ध थे। इसके उदाहरणस्वरूप १९९१ के सोवियत विघटन की परिस्थितियां हैं। विदित है कि सोवियत विखराव के पश्चात् तंग सिलाओ पिंग और पार्टी में अमेरिका से सम्बन्धों को लेकर काफी बहस थी, अंततः अमेरिका से सम्बन्धों को सुधारने की नीति को स्वीकृति मिली, परन्तु जिन तर्कों पर यह स्वीकार्यता मिली, वह पिछले तर्क के सही होने की पुष्टि करते हैं। अमेरिका से संघर्ष में न उलझने व सहयोग के नीति को वैधता मिलने के पीछे कुछ महत्तवपूर्ण तर्क थे। दरअसल पार्टी में सोवियत बिखराव के पश्चात उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में "शान्तिपूर्ण विधान" व बुर्जुआ उदारीकरण को लेकर संघर्ष चलाने पर एक पक्ष जोर दे रहा था, जिसका तर्क यह थी था कि सोवियत संघ के बिखराव में शान्तिपूर्ण विकास व बुर्जुआ चेतना के विकसित होने का महत्तवपूर्ण कारक रहा है। इस बैचारिक आकलन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में तंग सियाओ की सुधार लाइन व अमेरिका सहयोग सोच पर हमला था। तंग ने १४ वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान इस हमले के प्रति उत्तार में अपना आकलन प्रस्तुत किया। इस आकलन के मुताविक, सोवियत संघ के बिखराव की मूल वजह उनकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था व गलत राजनीतिक निर्णय थे, न कि अमेरिका प्रायोजित शान्तिपूर्ण विकास । इस आकलन में तंग ने कहा यदि चीन में कुछ गलत घटना होती है तो वह अन्दर से होगी तथा इसका केन्द्र पार्टी होगी। यह आकलन उस आकलन से एकदम भिन्न था जिसमें १९८९ के दौरान यह कहा गया था कि International climate was the main cause of trouble या वर्तमान समस्या की जड़ बुर्जुआ उदारीकरण व चार कार्डिनल प्रिंसिपल के बीच का संघर्ष है। बहरहाल अपनी समझदारी में बदलाव करते ही दो चीजें साफ हो गई, एक 'खतरे के रूप में अन्दुसी स्मजिपेउ पर हमला, चूंकि वह तीव्र गति से आर्थिक सुधारों को चलाने का विरोधी था। दूसरा आथ्रिक सुधारों से चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाना तथा तीसरे यह कहा गया कि चूंकि हमारे अमेरिका से मूलभूत अंन्तर नहीं है तथा "शान्तिपूर्ण विकास" हमारे रहते खतरा नहीं है अतः अमेरिका व पश्चिमी देशों से अपने सम्बन्धों को सुधारा जाए। यहां हम उस तर्क को पुष्ट कर सकते हैं जो सोवियत संघ के संदर्भ में दिया गया था। सोवियत संघ के

बिखराव को बचाने की एक मूल वजह को चीन के आर्थिक सुधारों के सुचारू रूप से चलाने के रूप में देखा जा सकता है। वही जब संभावना सच हो गई तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में अन्ततः अमेरिका से सम्बन्ध सुधारने की वकालत की गई जो १४वीं पार्टी कांग्रेस १९९२ में स्वीकार्य की हो गई।

अतः कुल मिलाकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया में समाजवाद के पतन का कार्य इस बात से अधिक प्रभावित था कि समाजवाद के चीनी चरित्र का विकास, विश्व-व्यवस्था में कैसे किया जाए।

दूसरा महत्तवपूर्ण मुद्दा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की वैधता का भी था। उदाहरणतः १९८९ की समझ ---१९९१ में बदलाव कयों आय? क्या बुर्जुआ उदारीकरण अब समस्या नहीं था। दरअसल इसका संभावित जबाव संदर्भ के बदलने में ढूंढा जा सकता है। १९८९ की घटना चीन कम्युनिस्ट पार्टी की भीतरी घटना था १९९१ का घटनाक्रम बाहरी था। पर दोनों घटनाक्रम अपने मूल मुद्दों के चलते एक महत्तव के थे। इसके बाद १९८९ में श्येनआनमेन की घटना के समय मोटे तौर पर संकट के इस दौर में यदि दो मुद्दे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए महत्तवपूर्ण थे। एक कम्युनिस्ट पार्टी व नेतृत्व की वैधता व स्वीकार्यता तथा दूसरा आर्थिक सुधारों व खुले द्वार की नीति को सुचारू रूप से चलते रहना। मूलतः इसी आधार पर सोवियत संघ से सम्बंध बढ़ाने की नीति १९८९ की प्रतिकूल परिस्थितियों में शुरू हुई और यह उन कुछ महत्तवपूर्ण कारकों में से थे जिन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट को बचाए रहने की नीति को प्रभावी बनाया। मूलतः तंग सियाओ पिंग द्वारा समर्थित नीति में १९८९ व १९९१ दो संदर्भों का बहुत महत्तवपूर्ण प्रभाव दिखता है। १९८९ में च्येनआनमेन आन्दोलन के दमन में "बुर्जुआ उदारीकरण को समस्या के रूप में "बाहरी" तत्व करार देना या यह कहना "International climate was the cause of trouble" एक साथ दो तरह के दृष्टिकोण को इंगित करता है। प्रथम कि समस्या का स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य है तथा बुर्जुआ

उदारीकरण है, दूसरा यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर पूर्वी यूरोप के पतन व सोवियत बदलावों के प्रभाव को दिखाता है। परन्तु महत्तवपूर्ण मुद्दा जो इस तर्क में छिपा है वह परोक्ष रूप से यह साबित करने की कोशिश है कि दरअसल जो भी घटित हुआ उसमें तत्कालीन नेतृत्व व १९७८ के बाद शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का कोई योगदान नहीं है।" इस बात का महत्व इससे लगाया जा सकता है कि यह तंग सियाओ के सुधारों व नेतृत्व को वैधता व स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए आवश्यक था अन्यथा यह सम्भव था कि यदि सुधार-विरोधियों या सुधारों की ---- को समस्या रेखांकित करने वाली दूसरे पक्ष की राय प्रमुख हो जाती तो वह सम्भवतः तंग सियाओ के नेतृत्व को समाप्त कर देती। अतः समस्या को चीनी संदर्भ में बाहरी बताना, स्वयं को सही सिद्ध करना भी था।

वहीं १९९१ कमें सोवियत विखंडन के क्षेत्र को उनकी अथव्यवस्था व राजनीतिक निर्णयों में ढूंढ़ना भी एक खास किस्म की राजनीतिक समझदारी के तहत कहा गया। यह बात गौरतलब है कि १९८९ का International climate 1991 के सोवियत विखराव में अपने चरम सीमा पर था। समाजवाद व कम्युनिस्ट पार्टियों पर अन्य संकट का १९९१ तक और गंभीर हो चुका था। यूगोस्लाविया संकट ने इसे और आगे बढ़ाया। परन्तु तंग सिपाओ द्वारा आरोपित International climate 1991 के बाद अदृश्य हो जाता है, क्यों? क्या International climate अब कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए अनुकूल हो चुका था? इसका एक संभावित व्याख्या यह हो सकती है कि सवाल Innternational climate के साथ यह भी महत्तवपूर्ण था कि यदि International climate सोवियत संघ पूर्वी यूरोप को समाप्त कर सकता है तो चीन भी इस गिरफ्त में आ सकता है, ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी में संभवतः इस International climate के विरुद्ध संघर्ष की बात आना लाजमी होता जो कि चीनी संदर्भ में तंग सिंयाओ की राजनीतिक लाईन पर हमला हो सकता था जिसका उदाहरण उन वक्तव्यों में मिलता है जो बुर्जुआ उदारीकरण, शान्तिपूर्ण विकास की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर यह तंग के राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल होता, अतः तंग के बयानों में इस स्थिति

के मद्देनजर समस्या के स्रोत क्यों, इस तरह anticipate किया गया जो कम –कम तत्कालीन सुधारों, राजनैतिक नेतृत्व पर सवाल खड़ा न करें और अंततः यही हुआ कि, समस्या को भीतरी (रूस के संघर्ष में) घोषित करते ही leftism, सुधार, विरोधियों की आलोचना शुरू हो गई। सोवियत संघ के बिखराव के स्रोत के भीतरी रूप से सम्बोधित करने के बाद स्पष्टतः यह Implication निकला कि If somthing wrong occurs in China, it will be come from within the Communist Party" इस तरह जहां एक ओर इस समझदारी ने तत्कालीन नेतृत्व की वैधता पर सवाल खड़ा नहीं होने दिया, वही सुधारों को जारी रखने की सैद्धान्तिक स्वीकार्यता भी मिल गई।

ooo

BIBLIOGRAPHY

Primary Sources

"Advance Along the Road to Socialism with Chinese Characteristics", Beijing Review, 45, November 9-15, 1987.

"Building up a great wall of steel against peaceful evolution", Renmin Ribao Commentator, August 16, 1991, trans. in FBIS-Chi, August 19, 1991.

"Communiqué of the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee of the Communist Party of China", (December 29, 1978) in Schell, Orville, and Shambaugh, David, (eds.), The China Reader: The Reform Era, New York: Vintage Books, 1999.

"Deng Calls for Speedup in Reform", Beijing Review, 34, August 24, 1987.

"How to Define Mao Zedong Thought", Beijing Review, 1, January 7, 1980.

"Hu Yaobang's Speech", Beijing Review, 28, July 13, 1981.

"Li Peng Delivers Government Work Report", Chinese Premier's NPC Address, 1993, SWB, FE/1638 C2/1, March 16, 1993.

"Nature of Chinese Society", Beijing Review, 23, June 8, 1981.

"Overcoming Two Erroneous Trends of Thought", Beijing Review, 24, June 8, 1979.

Anonymous, "The Ten-Thousand-Character Manifesto", (1996) in Schell, Orville, and Shambaugh, David, (eds.), The China Reader: The Reform Era, New York: Vintage Books, 1999.

Chou En-lai, "Learn from Maos Tse-tung", Peking Reveiew, 43, October 27, 1978.

Deng Liqun, "Answers to Questions Concerning the 'Resolution on Certain Questions in the History of the Party since the Founding of the PRC', July 30, and August 11, Chinese Law and Government, Vol.19, No.3, Fall 1986, pp.12-55.

Deng Xiaoping, "Answers to the Italian Journalist Oriana Fallaci", (August 1980) Selected Works of Deng Xiaoping (1975-1982), Beijing: Foreign Languages Press, 1984.

_____, "Taking a Clear-cut Stand Against Burgeois Liberalization", (excerpt of speech to the Central Committee of the Communist Party of China, December, 1986) in Schell, Orville, and Shambaugh, David, (eds.), The China Reader: The Reform Era, New York: Vintage Books, 1999.

_____, Fundamental Issues in Present-Day China, Beijing: Foreign Languages Press, 1987.

_____, Selected Works of Deng Xiaoping (1975-1982), Beijing Foreign Languages Press, 1984.

Jiang Zemin, "Accelerating the Reform, the Opening to the Outside World and the Drive for Modernization, so as to Achieve Greater Successes in Building Socialism With Chinese Characteristics", (Report delivered at the 14th National Congress of the Communist Party of China, October 12, 1992) Beijing Review, 35, Oct 26 – Nov 1, 1992.

_____, "Hold High the Great Banner of Deng Xiaoping Theory for an All-round Advancement of the Cause of Building Socialism with Chinese Characteristic into the 21st Century", (Report delivered at the 15th National Congress of the Communist Party of China, 12 September, 1997) Beijing Review, Sept 26 – Oct 2, 1997.

_____, "Patriotism and the Mission of Our Intellectuals – a speech given at a meeting held by the young people of the capital to commemorate the May Fourth, May 3 1990, published in Renmin Ribao, May 4, 1990, trans. in FBIS-Chi, May 7, 1990.

Li Peng, "Report on the Work of the Government", (delivered at the Second Session of the Eight National People's Congress, March 10, 1994) Beijing Review, April 4–10, 1994.

Mao Tse-tung, "On Contradiction", in Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. I, Peking: Foreign Languages Press, 1967.

_____, "On Practice", in Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. I, Peking: Foreign Languages Press, 1967.

_____, "On the Ten Major Relationships, April 25, 1956", Peking Review, 1, January 1, 1977.

Selected Works of Mao Tse-tung, Peking: Foreign Languages Press, 1967.

The Constitution of the Communist Party of China, 1982.

The Constitution of the People's Republic of China, 1982.

Secondary Sources

Books

Barnett, A Doak, After Deng, What? Will China Follow the USSR, Washington D C: John Hopkins Foreign Policy Institute Papers, 1991.

Baum, Richard, Burying Mao: Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

Benewick, Robert and Wingrove, Paul, (ed.), Reforming the Revolution: China in Transition, London: Macmillan Education, Ltd., 1988.

Dittmer, Lowell, China Under Reform, Boulder: Westview, 1994.

_____, China's Continuous Revolution: The Post-Liberation Epoch, 1949-1981, Berkeley: University of California, Press, 1987.

Domes, Jurgen, The Government and Politics of the PRC: A Time of Transition, Boulder: Westview Press 1985.

Evans, Richard, Deng Xiaoping and the Making of Modern China, London: Hamish Hamilton, 1993.

Gamer, Robert E, (ed.), Understanding Contemporary China, Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1999.

Ginsburg, M and Lalor B A, China: The 80s Era, Boulder and London: Westview Press, 1989.

Gittings, John, China Changes Face: The Road from Revolution, Oxford and New York: Oxford University Press, 1989.

Glassman, Ronald M, China in Transition: Communism, Capitalism, and Democracy, New York: Praeger, 1991.

Goldman, Merle, Sowing the Seeds of Democracy in China: Political Reform in the Deng Xiaoping Era, Cambridge: Harvard University Press, 1994.

Goodman, D S G and Hooper, B, (eds.), China's Quiet Revolution, Murdoch: Longman Cheshire, 1994.

Grasso, June, Jay Corrin and Michael Kort, Modernization and Revolution in China, revised ed., Armonk, NY and London: M E Sharpe, 1997.

Harding, Harry, China's Second Revolution: Reform after Mao, Washington DC: The

Brookings Institution, 1987.

History of the Chinese Communisty Party: A Chronology of Events (1919-1990), 1991, Beijing : Foreign Languages Press.

Hong Yung Lee, The Politics of the Chinese Cultural Revolution: A Case Study, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1978.

Hook, B, (ed.), The Individual and the State in China, Oxford: Clarendon Press, 1996.

Hsiung, James C, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

Ka-ho Mok, Social and Political Development in Post-Reform China, London, Macmillan Press Ltd., 2000.

Ladany, Laszlo, The Communist Party of China and Marxism, 1921-1985: A Self-Portrait, Stanford: Hoover Institution Press, 1988.

Lawrence, Alan, China Under Communism, London and New York: Routledge, 1998.

Mackerras, Collin, Taneja, Pradeep, and Young, Graham, China Since 1978: Reform, Modernisation and 'Socialism with Chinese Characteristics', Melbourne: Longman Cheshire Pvt. Ltd., New York: St. Martin's Press, 1994.

McCormick, Barrett, Political Reform in Post-Mao China: Democracy and Bureaucracy in a Leninist State, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Meisner, Maurice, Mao's China: A History of the People's Republic, New York: The Free Press, 1977.

Meskill, John, (ed.), An Introduction to Chinese Civilization, New York and London: Columbia University Press, 1973.

Misra, Kalpana, From Post-Maosim to Post-Marxism: The Erosion of Official Ideology in Deng's China, New York: Routledge, 1998.

Moody Jr., Peter R, Opposition and Dissent in Contemporary China, Stanford: Hoover Institution Publication, 1977.

Nathan, Andrew J, China's Transition, New York: Columbia University Press, 1997.

_____, Chinese Democracy: The Individual and the State in 20th Century China, London: I B Tauris and Co., Ltd., 1986.

Oksenberg, Michel, Sullivan, Lawrence and Lambert, Marc, (eds.), Beijing Spring, 1989:

Confrontation and Conflict: The Basic Documents, New York: M E Sharpe, 1990.

Rosenbaum, A L, (ed.), State and Society in China: The Consequences of Reform, Boulder: Westview Press, 1992.

Saich, Tony, (ed.), The Chinese People's Movement: Perspectives on Spring 1989, New York and London: M E Sharpe, 1990.

_____, (ed.), The Rise to Power of the Chinese Communist Party: Documents and Analysis, New York and London: M. E. Sharpe, 1996.

_____, and Shambaugh, David, (eds.), The China Reader: The Reform Era, New York: Vintage Books, 1999.

_____, and Ven, Hans van de, (eds.), New Perspectives on the Chinese Communist Revolution, New York and London: M. E. Sharpe, 1995.

Schurmann, Franz, Ideology and Organizations, Berkekly: Universtiy of California Press, 1956.

Schwartz, Benjamin I, Communism and China: Ideology in Flux, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968.

Shaozi Su, Democratisation and Reform, Nottingham Spokesman Press, 1988.

Snow, Edgar, Red Star Over China, Middlesex: Penguin, 1972.

_____ ____, The Long Revolution, New York: Vintage Books, 1973.

Spence, Jonathan D, The Search for Modern China, 2nd ed., New York and London: W. W. Norton & Company, 1999.

Stavis, Benedict, China's Political Reforms: An Interim Report, New York: Praeger, 1988.

Tarrow, Sidney, Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, New York: Cambridge University Press, 1994.

Teiwes, Frederick C, Politics and Purges in China: Rectification and the Decline of Party Norms 1950-1965, (2nd ed.), New York and London: M E Sharpe, 1993.

Vanhanen, Tatu, The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States, 1980-88, New York: Crane Russak, 1990.

Wang, James C F, Contemporary Chinese Politics: An Introduction, fifth ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Wasserstrom, Jeffrey N and Perry, Elizabeth J, (eds.), Popular Protests and Political Culture in Modern China, (2nd ed.), Boulder, Colorado: Westview Press, 1994.

White, Gordon, (ed.), The Chinese State in the Era of Economic Reform: The Road to Crisis, Armonk, New York: M E Sharpe, Inc., 1991.

Yan Sun, The Chinese Reassessment of Socialism, 1976-1992, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995.

Articles

Amin, Samir, "The Future of Socialism", Monthly Review, July-August 1990, pp. 10-29.

Barme, G, "'Road' versus 'River'", Far Eastern Economic Review, October 25, 1990, p. 32.

Baum, Richard, "China in 1985: The Greening of the Revolution", Asian Survey, Vol.26, No.1, January 1986, pp. 31-53.

_____, "Politicial Stability in Post-Deng China: Problems and Prospects", Asian Survey, Vol.32, No. 6 (June, 1992), p.491-505.

Bert, Wayne, "China's policy towards democratization movements : Burma and the Philippines", Asian Survey, Vol 30, No 11, 1990, pp. 1066-1083.

Braun, Aurel and Day, Richard B, "Gorbachevian Contradictions", Problems of Communism, May-June 1990, pp. 36-50.

Breslauer, George W, "Bursting the Dams: Politics and Society in the USSR since the Coup", Problems of Communism, November-December 1991, pp. 2-12.

Burns, John P., "China's Governance: Political Reforms in a Turbulent Environment", The China Quarterly, No.120, December 1989, pp. 481-518.

Chamberlain, Heath B, "On the search for civil society in China", Modern China, Vol 19, no 2, 1993, pp. 199-215.

Chang, David Wen-wei, "Confucianism, democracy, and communism: the Chinese example in search of a new political typology for systematic integration", Issues and Studies, Vol 26, no 11, 1990, pp. 53-74.

Chang, David Wen-wei, "Sun Yat-senism: a general theory for developing countries", Issues and Studies, Vol 28, no 5, 1992, pp. 63-72.

Chang, Parris, "Chinese Politics: Deng's Turbulent Quest", Problems of Communism, Vol.30, No.1, January-February 1980, pp.1-21.

Chao Chien-min, "Transition from authoritarian: is Eastern Europe today mainland China's tomorrow?", Issues and Studies, Vol 26, no 11, 1990, pp. 33-52.

Christiansen, F and Rai, S, "Political Mobilization and Democratization in China", The Centre for Studies in Democratization Working Papers, Coventry: University of Warwick, 1995.

Dittmer, Lowell, "China 1989: The Crisis of Incomplete Reform", Asian Survey, Vol.29, No.1, January 1990, pp.25-41.

_____, "China in 1988: The Dilemma of Continuing Reform" Asian Survey, Vol.29, No.1, January 1989, pp.12-28.

_____, "Patterns of Elite Strife and Succession in Chinese Politics", The China Quarterly, No.123, September 1990, pp.405-430.

_____, "The Tiananmen Massacre", Problems of Communism, Vol.38, No.5, September-October 1989, pp.2-15.

Ferdinand, Peter, "Social Change and the Chinese Communist Party: Domestic problems of rule", Journal of International Affairs, Vol. 49, No. 2, Winter 1996, pp. 590-604.

Fewsimth, Joseph, "Neoconservativism and the End of the Dengist Era", Asian Survey, Vol.35, No.7, July 1995.

Fewsimth, Joseph, "Reform, Resistance, and the Politics of Succession", in William A. Joseph, ed., China Briefing, 1993, Boulder: Westview Press 1994.

Francis, Corinna-Barbara, "The Progress of Protest in China", Asian Survey, Vol.29 No.9, september 1989, pp. 898-915.

Halpern, Nina, "Learning from Abroad: Chinese Views of the Eastern Europe Economic Experience, 1977-1981", Modern China, Vol.1, 1985, pp.77-109.

Hong Yung Lee, "The Implication of Reform for Ideology, State and Society in China", in "China in Transition", Journal of International Affairs, Winter 1986.

Jencks, Harian, "Party Authority and Military Power: Community China's Continuing Crisis", Issues & Studies, Vol.26, No.7, July 1990, pp. 11-39.

Kelly, D and He, Baogang, "Emergent Civil Society and the Intellectuals in China", in Miller R, (ed.), The Development of Civil Society in Communist Systems, Sydney: Allen & Unwin, 1992.

Kim, Samuel S, "China in and Out of the Changing World Order", World Order Studies Programme, Occasional Paper, 1991.

Kirkpatrick, Jeanne J, "After Communism, What?", Problems of Communism, January-April 1992, pp. 7-10.

Kux, Ernst, "Revolution in Eastern Europe - Revolution in the West", Problems of Communism, May-June 1991, pp. 1-13.

Li-min Fan, "On mainland China's democratization", Issues and Studies, Vol 26, no 8, 1990, pp. 30-42.

Lo, Carlos Wing-hung, "The Chinese Communist Party's perception of crisis and methods of solving during the 1989 democratic movement: a legal perspective", Asian Affairs, Vol 19, no 2 1992, pp. 97-120.

Ma Shu Yun, "The Rise and Fall of Neo-Authoritarianism in China", China Information, Vol. 5, No.3, Winter 1990-91, pp. 1-19.

Ma, Shuyun, "The Chinese Discourse on Civil Society", The China Quarterly, Vol. 137, 1994, pp. 180-93.

Magdoff, Harry, "Are there Lessons to be Learned?", Monthly Review, Vol. 42, No. 9, February 1991, pp. 1-19.

McAdam, Doug and Rucht, Dieter, "The Cross-National Diffusion of Movement Ideas", Annals of the American Academy of Political and Social Science, No. 528, 1993, pp. 56-74.

Milband, Ralph, "Socialism in Question", Monthly Review, March 1991, pp. 16-26.

Moody, Peter R, "Some nonofficial trends in political thought during Mainland China's decade of reform", Issues and Studies, Vol 28, no 2, 1992, pp. 28- 50.

Nathan, Andrew J, "China's path from communism", Journal of Democracy, Vol 4, no 2, 1993, pp. 67-81.

_____, "Chinese Democracy in 1989: Continuity and Change", Problems of Communism, Vol.38 No.5, January 1989, pp.17-29.

Odom, William E, "Alternative Perspectives on the August Coup", Problems of Communism, November-December 1991, pp. 13-19.

Oksenberg, Michel, "China's 13th Party Congress", Problems of Communism vol.36, No.6, November-December 1987.

Petracca, Mark, and Mong Xiong, "The Concept of Chinese Neo-Authoritarianism: An Exploration and Democractic Critique", Asian Survey, Vol.30, No.11, November 1990, pp. 1099-1117.

Prybyla, Jan S, "The Road From Socialism: Why, Where, What, and How", Problems of Communism, Jan-April 1991, pp. 1-17.

_____, "Why China's Economic Reforms Won't Work", Asian Survey, Vol.29, No.11, November 1989, pp.1017-32.

Rosen, Stanley and Zou, Gary (eds.), "The Chinese Debate on the New Authoritarianism", Chinese Sociology and Anthropology, Winter 1990-91, Spring 1991, Summer 1991(series of articles).

_____, "The CCP and Chinese society: Popular attitude towards party leadership and party image", Australian Journal of Chinese Affairs, No. 24, July, 1990.

Sah Kung-Chiang, "On 'peaceful evolution' and 'anti-peaceful evolution'", Issues and Studies, Vol 28, no 8 1992, pp. 32-45.

Saich, Tony, "The fourteenth Party Congress : a programme for authoritarian rule", The China Quarterly, No 132, 1992, pp. 1136-1160.

Schoenhals, Michael, "Political Movements, Change and Stability: The Chinese Communist Party in Power", The China Quarterly, No. 159, September 1999, pp. 595-605.

Schram, Stuart R, "'Economics in Command'? Ideology and Politics since the Third Plenum, 1978-84", The China Quarterly No. 99, September, 1984, pp. 417-61.

Schram, Stuart R, "China after the 13th Congress", The China Quarterly No. 114, June 1988, pp. 177-97.

Shi Hong, "China's political development after Tiananmen : Tranquility by default", Asian Survey, Vol 30, no 12 1990, pp. 1206-1217.

Shi Tianjian, "The democratic movement in China in 1989: Dynamics and failure", Asian Survey, Vol 30, no 12, 1990, pp. 1186-1205.

Shue, Vivenne, "China: Transition Postponed?", Problems of Communism, January-April 1992, pp. 157-168.

Solinger, Dorothy J, "Capitalist Measures with Chinese Characteristics", Problems of Communism, January-February 1989, pp. 19-33.

Stokes, Gale, "Lessons of the East European Revolutions of 1989", Problems of Communism, September-October 1991, pp. 17-22.

Strand, David, "Protest in Beijing : civil society and public sphere in China", Problems of Communism, Vol 39, no 3 1990, pp. 1-19.

Sweezy, Paul M, "Dangers of Democracy", Monthly Review, Vol. 42, No. 7, December 1990, pp. 1-7.

Tong, James, (ed.), "Baptism by fire: the democracy movement in Beijing, April-June 1989", Chinese Law and Government, Vol 23, No 2, 1990, pp. 9-119.

Uhalley, Stephen Jr., "Structural political reform in mainland China: before and after Tiananmen", Issues and Studies, Vol 26, no 7 1990, pp. 40-58.

Whyte, Martin King, "Prospects for Democratization in China", Problems of Communism, May-June 1992, pp. 58-70.

Wilson, Frank l, Communism at the Crossroads: Changing Roles in Western Democracies, Problems of Communism, May-June 1992, pp. 95-106.

Womack, Brantly, "Political reform in China in the 1980s: a comparative communist perspective", in Vanhanen, Tatu (ed.), Strategies of Democratization, Washington D.C.: Crane Russak, 1992, pp. 113-129.

Newspapers and Periodicals

Asian Affairs
Asian Survey
Asiaweek
Beijing Review
China Daily
China Information
China Report
Chinese Law and Government
Chinese Studies in History
Chinese Studies in Philosophy
Comparative Politics
Discourse & Society
Dissent
Economic and Political Weekly
FBIS China
Foreign Affairs Journal
Frontline
Government and Opposition
Issues and Studies
Mainstream
Monthly Review
New Left Review
News from China
Newsweek
Pacific Affairs
Peasant Studies
Problems of Communism
Social Sciences in China
Study of Chinese Communism
The China Quarterly
The Hindu
Time

Websites

http://www.english.peopledaily.com.cn
http://www.insidechina.com
http://www.nytimes.com
http://www.scmp.com
http://www.iht.com